हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1994

खण्ड 1 अंक 9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 1994

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(9) 1
स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)2
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)6
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखा गया तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(9)22
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)23
कथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न	(9)24
ध्यानाकर्षण सूचनायें	(9)29
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	—
भिवानी शहर में पीलिया का रोग फैलने संबंधी	(9)34
वक्तव्य—	
स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(9)35

मूल्य :

	पृष्ठ संख्या
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(9)39
बैठक का समय बढ़ाना	(9)88
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)89
बैठक का समय बढ़ाना	(9)92
वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)92
बैठक का समय बढ़ाना	(9)95
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)95
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-- श्री धर्मपाल द्वारा	(9)97
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)98
बैठक का समय बढ़ाना	(9)99
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)99
बैठक का समय बढ़ाना	(9)105
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)106

ERRATA

To

Haryana Vidhan Sabha debates, Vol. 1, No. 9, dated the 15th March, 1994.

Read	For	Page	Line
मैं	में	3	20
पौलिसी	पौसिसी	11	23
जैसी	जसी	14	27
वित्त	वि	16	13
साहब	सहब	27	19
मैम्बर	मम्बर	28	7
उनको	अनको	31	4
बाड़	बाढ़	31	21
टैक्सटाईल	टक्सटाईल	36	1
गये	गय	36	14
हूं	हं	37	22
That	hat	40	17
for	or	40	27
Urban	under	43	3
हल्के	हल्ले	85	2
विधायक	विधायाक	87	20
कटोरे	ककोरे	91	7
कुछ	कछ	97	14
कर	कहै	98	14
महोदय	महोनय	98	19
सदस्यों	सदसीय	99	4
भाईयों	भाईयी	99	24
अध्यक्ष जी,	अध्यक्ष	100	14
वर्ल्ड	वल्ड	101	17
थे	थ	102	1
That	hat	108	9

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की ।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज़, अब मुख्य मंत्री जी आधुचरी रेफरेन्स करेंगे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन महात्मा गांधी जी की पौती श्रीमती मनुबैन सुरेन्द्र भाई मधुबाला जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, के 13 मार्च 1994 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनकी समाज सेवा व धार्मिक कार्यों में गहरी रुची थी। उनके निधन से देश एक सामाजिक कार्यकर्त्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टूकलां) : स्पीकर सर, हाउस के नेता ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन में रखा है, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उसका समर्थन करता हूं। हमें उनके निधन से बड़ी तकलीफ हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल(पलवल) : अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता व विपक्ष के नेता ने जो शोक प्रस्ताव यहां हाउस में रखा है, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं और शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। स्पीकर सर, मेरी हाउस के नेता से यह भी प्रार्थना है कि श्री रतीराम शर्मा, जो पब्लिक सर्विस कमिशन के मैम्बर रहे हैं, वे भी स्वर्गवास हो गए हैं और अगर उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जाए तो अच्छी बात है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the feelings expressed by the leaders of the different parties. Smt. Manubain Surender 'Bhai', महात्मा गांधी जी की पौती थी और महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता थे।

[श्री अध्यक्ष]

उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर देश को आजाद करवाया। अंग्रेजी प्राईम मिनिस्टर चर्चिल ने एक दफा कहा था कि मैं महात्मा गांधी के घुटने टिका दूंगा तो उस वक्त पास में बैठे हुए दूसरे स्टेट्समैन ने कहा कि नहीं, आप उनके घुटने नहीं टिका सकते, वे आपके घुटने टिका सकते हैं। उसके बाद जब चर्चिल ने कहा था I have not become the Prime Minister of England to liquidate the British Empire. वह ब्रिटिश ऐम्पायर महात्मा गांधी जी ने ही लिक्वीडेट कराया। भारत आजाद हुआ और उसके साथ सभी देश, जो अंग्रेज के गुलाम थे, सभी आजाद हुए वन बाई वन। तो मैं भी, हाउस के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए आप सभी के साथ एसोशिएट करता हूं और जो हाउस की फीलिंगज होंगी, उनको बीवड फैमिली तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं सब से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा के प्रति दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करें।

(इस समय सदन ने दिवंगत के सम्मान में दो मिनट खड़े होकर मौन धारण किया)

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, before we start questions enlisted for today, the postponed starred question No. 663 enlisted in the name of Prof. Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. will be first taken up.

Plantation of Trees

***663. Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for Forests be pleased to state the districtwise number of trees planted during the period from July, 1992 to-date in the State ?

Forest Minister (Rao Inderjit Singh) : Sir, statement is placed on the table of the House.

Statement

Sr. No.	Name of District	Total trees planted from July, 1992 upto 31-1-1994
1.	Ambala	21286468
2.	Yamuna Nagar	13962515
3.	Kurukshetra	6146878
4.	Kaithal	5045872

Sr. No.	Name of District	Total trees planted from July, 1992 upto 31-1-1994
5.	Karnal	7668472
6.	Panipat	4142731
7.	Sonipat	6731632
8.	Gurgaon	13477548
9.	Faridabad	7195494
10.	Mohindergarh	10417127
11.	Rewari	6954880
12.	Rohtak	10195207
13.	Bhiwani	12299879
14.	Hisar	14929925
15.	Jind	5633975
16.	Sirsa	11050112
		157138715

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो लिस्ट जुलाई 92 से 31-1-1994 तक की इन्होंने दी है, उनमें से कितने वृक्ष जिलाबाइज सरवाइव कर रहे हैं और कितने खत्म हो गये हैं ? इसके साथ-साथ में मन्त्री महोदय से यह भी कहूंगा कि जितने वृक्ष वे आगे लगवा रहे हैं उनमें कम से कम कीकर के वृक्ष न लगवाएं। राव साहब खुद तो शायद किसान नहीं हैं लेकिन वे किसान परिवार से सम्बन्धित जरूर हैं। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि कीकर का वृक्ष लगवाने से आधा-आधा एकड़ जमीन बिल्कुल नष्ट हो जाती है और उस जमीन में कोई फसल नहीं होती तथा उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिलता।

इस के अलावा मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि जो दरख्त गिराये जा रहे हैं, क्या सरकार पिछली सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए, उन दरख्तों की आमदनी का आधा हिस्सा किसानों को देने का इरादा रखती है ?

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, नवम्बर, 1991 में गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से हमारे यहां एक टीम आई थी। उस समय हमारी स्टेट प्लांटेशन कर चुकी थी। उन्होंने अपनी तरफ से जो उसका ब्यौरा दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा का सक्सैस रेट 80 प्रतिशत से ऊपर है। वैसे हमारा जो निजी मौनिटरिंग सैल है जो सोशल फारैस्टरी में करनाल और अरावली में रखा हुआ है, उसके हिसाब से इनका सक्सैस रेट 60-70 प्रतिशत है। दूसरी बात इन्होंने कही कि कीकर के

[राव इन्द्रजीत सिंह]

पेड़ न लगाए जाएं। स्पीकर साहब, कई किस्म के पेड़ लगाए जाते हैं। एक बात तो मैं भी मानता हूं कि कीकर के पेड़ के नीचे फसल ठीक ढंग से नहीं होती। लेकिन माननीय सदस्य यह बात भी मानेंगे कि गांव वाले फयूल के तौर पर कीकर की लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। अगर कीकर का पेड़ न हो तो वे अपना कुल्हाड़ा दूसरे पेड़ों पर चलाएंगे। हमारी फयूल की जरूरत को वही पेड़ पूरा कर सकता है इसलिए उसको लगाना जरूरी है। जहां तक पेड़ों का आधा हिस्सा किसान को देने की बात है उस के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार की नीति में यह था कि कुछ परसैंट हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। उसका फायदा उठाते हुए किसानों ने अपने खेत के साथ लगते पेड़ों के अलावा सड़क के साथ लगते हुए पेड़ भी काट लिए। तो इनकी नीति के हिसाब से खेत के साथ लगने वाले पेड़ों का हिस्सा उनको जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने सारे पेड़ ही काट लिए। इसलिए हमने उस नीति को लागू नहीं किया।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जिस तरह से कीकर का पेड़ नुकसानदायक है, इसी तरह से सफेदे का पेड़ भी खेती के लिए और सब सायल पानी के लिए लाभदायक नहीं है। दूसरे आपने जो पेड़ों का सरवाइवल रेट बताया है, क्या इसका हर साल सर्वे करवाते हैं, अगर हां तो इसमें कितनी सच्चाई है?

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, सफेदे के पेड़ के बारे में काफी डिबेट हुई है कि यह बेहतर किस्म का पेड़ है या नहीं, क्या यह वहां पर लग सकता है जहां पानी की कमी है? स्पीकर साहब, सफेदे के पेड़ की जड़ दस फुट से ज्यादा नहीं होती। जैसे हमारे साउथ के जिले हैं, वहां पर एक सौ फुट तक सब-सायल पानी होता है, इसलिए सब-सायल पानी को यह खराब नहीं करता। इन्होंने जो कहा कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कहां तक सच्चाई है या नहीं, उसके लिए हमारी हरियाणा सरकार ने मौनिट्रिंग सैल बना रखे हैं। एक करनाल के अन्दर है और एक गुड़गांव जिले में हैं। इनके अनुसार 60-70 प्रतिशत सक्सैस रेट है। हम बाकायदा 60-70 परसैंट मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर सक्सैस रेट का सर्वे करते रहते हैं। स्पीकर साहब, हमारे प्रदेश में भारत सरकार की ओर से एक सर्वेक्षण टीम आई थी, उन्होंने सर्वे के बाद यह बताया कि हरियाणा के अन्दर 80 परसैंट सक्सेस रेट है।

श्री सतबीर सिंह काद्यान: स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने किसान के खेत से 10 फुट तक दूरी के पेड़ों में किसानों को आधा हिस्सा देने का प्रावधान किया था। इसलिए मैं मौजूदा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पिछले दो साल में किसानों को पेड़ों में कितना हिस्सा दिया गया है? इसके साथ साथ मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि असंध ग्राम पंचायत ने जो एक हजार एकड़ जमीन ट्री प्लांटेशन के लिए सरकार को दी है, उसमें कब तक ट्री प्लांटेशन करवा दी

जाएगी । क्या वह जमीन पंचायत को वापिस कर दी जाएगी, अगर वापिस की जाएगी तो कब तक की जाएगी ?

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, किसानों को पेड़ों में हिस्सा देने के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह नीति अब लागू नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पिछली सरकार ने क्या वह नीति लागू की थी ?

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने सारे पेड़ कटवा दिए थे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज सारी दुनिया इस बात से चिन्तित है कि वायुमंडल को कैसे शुद्ध रखा जा सकता है, दूषित वातावरण से मानव को कैसे बचाया जा सकता है ? मानव को दूषित वातावरण से बचाने की बात पेड़ों से ही हो सकती है। पेड़ ही मानव को दूषित वातावरण से बचा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठे विरोधी पक्ष के भाइयों ने तो रास्ता रोकने के नाम से पेड़ों को काट-काट कर सड़कों पर डाल दिया था और लोगों को कह दिया था कि हमारी पार्टी की सरकार आते ही आप सारे पेड़ काट लेना, जो सरकारी पेड़ हैं उनमें भी आपको आधा हिस्सा मिलेगा। ये लोग इस तरह की बात करते हैं। लोगों को कर्जा माफी की बात कह करके उनको गुमराह करते हैं और लोगों से वोट ले कर गद्दी पर बैठे, क्या लोगों का कर्जा माफ हुआ ? उनका कर्जा माफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने कर्जा माफी की जो पालिसी बनाई, क्या वह लागू हुई ? ऐसी पालिसी लागू नहीं हो सकती। एक पेड़ की रक्षा करना एक इन्सान की रक्षा करना है। पेड़ में भी जीव है। अध्यक्ष महोदय, ये पेड़ की जीवनी के बारे में पढ़ें तो हम इनको बताएं, इन्होंने पेड़ कटवा कर प्रदेश के वातावरण को बहुत खराब किया। हम पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। हम प्रदेश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाने की कोशिश भी की है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि जुलाई, 1992 से 31-1-1994 तक करनाल जिले में 7668472 पेड़ लगाए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने परसैंट कीकर लगाई और कितने परसैंट सफेदे के पेड़ लगाए गए ?

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, नीति के अनुसार करनाल जिले में पेड़ लगाए गए हैं। इनमें से 31 परसैंट पेड़ ऐसे लगाए गए हैं जो छाया के तौर पर काम में आएंगे। 37 परसैंट पेड़ टिम्बर के इस्तेमाल के लिए, 17 परसैंट फीडर के इस्तेमाल के लिए और 6 परसैंट फ्रूट आदि के इस्तेमाल के लिए लगाए जाते हैं।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर साहब मैं जानना चाहता हूं कि ये पेड़ कहां-कहां पर लगाए गए ?

राव इन्द्रजीत सिंह : आमतौर पर पेड़ कम्युनिटी लैंड पर लगाए गए हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हमने पेड़ काट कर सड़कों पर डाल दिए थे। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जब स्टेट वाटर का और टैरीटोरियल का इश्यू चल रहा था तो उसकी रक्षा करने के लिए प्रान्त के हितों की खातिर लोगों ने पेड़ काट कर भी रास्ता रोका, ट्रैक्टर-ट्रालियों से भी रास्ता रोका। उन्होंने प्रोटैस्ट के तौर पर रास्ता रोका था। स्पीकर साहब, जो स्कीम थी, वह यह थी कि सड़कों या नहरों के किनारे पर जो पेड़ लगे हुए हैं, उनकी जो लास्ट लाईन होती है, वह किसान की फसल को नुक्सान पहुंचाती थी, इसलिए उस समय यह फैसला किया गया था कि जब ऐसे पेड़ जो 15-20 साल बाद मैच्योर होंगे, ऐसे पेड़ों को फोरैस्ट डिपार्टमैंट के द्वारा काटने के बाद औक्शन के जरिए आधा पैसा किसानों को दिया जाएगा। यह पैसा उनको बतौर मुआवजे के तौर पर देना था। लीडर तो चेंज होते रहते हैं लेकिन पालिसी सरकार की वही रहती है। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों की फसल को हुए नुक्सान का मुआवजा देने के लिए क्या उस नीति को दोबारा से लागू करने का सरकार का कोई विचार है ?

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात यह कही कि सरकार तो बदलती रहती हैं लेकिन नीतियां वही रहती हैं। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इनके समय के दौरान जो नीति लागू की गई थी, वह यह थी कि जो पेड़ किसानों के खेत के साथ-साथ सड़कों पर या नहरों के किनारे पर लगाए जाएंगे उनको काटने पर आधा हिस्सा उस पेड़ का संबंधित किसान को मिलेगा। हमारी नीति यह है कि अगर हम कोई कीकर का पेड़ लगाते हैं तो वह 15-16 साल में जा कर मैच्योर होता है। इसलिए उससे पहले उसको काटने की हम अनुमति नहीं देते। (विघ्न) कीकर के पेड़ की छाया से खेत को नुक्सान हो सकता है लेकिन अभी हमारी सरकार को आए हुए केवल अढ़ाई वर्ष हुए हैं और वे इतने छोटे पेड़ हैं कि उनसे किसान की फसल को नुक्सान नहीं हो सकता। किसानों को मुआवजा देने व पेड़ काटने के बारे में हमारी नीति यह है कि जब तक हम यह नहीं देख लेंगे कि फलां वृक्ष से किसान की फसल को नुक्सान हो रहा है, तब तक उसको काटने की अनुमति नहीं देंगे। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी तो उस समय शुरू-शुरू में हमने इनकी नीति के मुताबिक 1000—2000 हैक्टेयर जमीन में जो पेड़ लगे हुए थे, उनका मुआवजा किसानों को दिया था लेकिन अब हमारी नीति इनकी नीति से अलग है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 786

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य प्रो० राम बिलास शर्मा सदन में उपस्थित नहीं थे।

Raid Conducted on Veravali Hospital, Gurgaon

*809. **Shri Dhirpal Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state whether any raid on the Veravali Hospital, Gurgaon was conducted by the Police during the year 1992; if so, the result thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : अतिरिक्त उपायुक्त, गुड़गांव द्वारा जनवरी/फरवरी, 1992 के समय के दौरान एक जांच की गई थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्टेशन सिटी, गुड़गांव में केस दर्ज किया गया था, जिसकी जांच अभी चल रही है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने जो जवाब दिया है, वह हमें जो रिटन रिप्लाई मिला है, उससे अलग है।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न में यह पूछा है कि क्या वर्ष 1992 के दौरान पुलिस द्वारा वेरावाली अस्पताल, गुड़गांव में कोई छापा मारा गया है, यदि ऐसा है, तो उसका क्या परिणाम निकला है ? इसका मैंने जवाब दिया है, नहीं। इसके बावजूद भी अगर माननीय साथी कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो वे पूछ सकते हैं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो लिखित उत्तर मिला है उसमें कहा गया है कि जनवरी/फरवरी, 1992 में ए0डी0सी0, गुड़गांव ने इन्क्वायरी की थी। मैं माननीय मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि वह जांच रिपोर्ट पुलिस को किस तारीख को रैफर हुई थी ? (विघ्न)

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि रेड तो नहीं हुई थी। डी0सी0 गुड़गांव को रिटन शिकायत मिली थी और वह शिकायत सिटिजन राईट्स, हरियाणा द्वारा डी0सी0 को दी गई थी और वह शिकायत दिनांक 7-12-1991 को ए0डी0सी0 को सौंप दी। ए0डी0सी0 ने कुछ अधिकारियों को साथ ले कर मौके पर जा कर जांच की। उस में कौन-कौन से अधिकारी थे, वह भी मैं बता देती हूं। एक डी0एस0पी0, एक डाक्टर और एक आई0ए0एस0 अधिकारी मौके पर गए थे और उन्होंने वहां पर जा कर छानबीन की।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से जानकारी चाहता हूं कि सिटी गुड़गांव में यह केस किस तारीख को दर्ज हुआ और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, 8-3-1994 को केस दर्ज हुआ था। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर आगे की कार्यवाही हो सकेगी।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बी0ए0एम0एस0 डाक्टर अंग्रेजी दवाइयां रिकमैंड कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष : धीरपाल सिंह जी, यह सवाल तो रेड से संबंधित है, इसमें बी0ए0एम0एस0 की कोई बात नहीं है ।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, कहां-कहां पर केस रजिस्टर्ड हुए हैं या इस बारे में कोई और जानकारी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो अलग से नोटिस दें । (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री साहिबा काफी इन्टैलीजैन्ट हैं और वे इस सवाल का जवाब दे सकती हैं, इसलिए मैं इनसे जानकारी चाहूंगा कि जहां पर रेड डाली गई है ।.....(विघ्न) स्पीकर साहब, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मेरी पर्सनल जानकारी में भी है । मेरे पास बी0ए0एम0एस0 डाक्टर का लैटर पैड है जिस पर आयुर्वैदिक डिग्री लिखी होने के बावजूद अंग्रेजी दवाईयां प्रैस्काईब की गई हैं, क्या एक बी0ए0एम0एस0 डाक्टर ऐसी दवाइयां प्रैस्काईब कर सकता है ?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, शिकायत पर जो जांच की गई है, उसमें पाया गया है कि उनके पास सही डिग्री नहीं पाई गई थी । इसीलिए तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और कानून के मुताबिक जो कार्यवाही हो सकती है, वह जरूर की जाएगी ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जिन अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती और सरकारी अस्पतालों में डाक्टर नहीं मिलते हैं.....(विघ्न)

Mr. Speaker : It is no question. Next question please.

Dadupur-Nalvi and Dadupur-Ladwa Canal

*798. **Sathi Lehri Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the construction work of Dadupur Nalvi Canal has been started; if so, the time by which it is likely to be completed ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : No Sir. The scheme is under consideration.

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम में आपका हल्का भी आता है और मेरा हल्का भी आता है। इससे चार जिले इफैक्ट होते हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्होंने कहा है कि यह अन्डर कंसीडेशन है। पिछली बार सरकार ने कहा था कि यह कैनाल स्कीम में ही नहीं है। मैं सरकार का आभारी हूं कि इन्होंने इस बार स्कीम में इसे शामिल कर लिया है। अध्यक्ष महोदय यह किसान की लाईफ लाईन है। ऐसा करने से सरकार की 10 करोड़ रुपये की बिजली बच सकती है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ये दादूपुर नलवी पर कब तक काम शुरू कर देंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह सी0डब्ल्यू0सी0 के पास अन्डर कंसीडेशन है और हरियाणा सरकार इस बारे में जागरूक है। जब सी0डब्ल्यू0सी0 इजाजत देगी तो इस पर सरकार कार्यवाही करेगी।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जो नहर हमारे एरिया से निकलती है, उससे हमें पानी नहीं मिलता और यह हमारे साथ ज्यादती होती है। हमें न तो डब्ल्यू0जे0सी0 का पानी मिलता है और न ही आगमेंटेशन का पानी मिलता है। हमारी जौरी और गेहूं की फसलें सूख जाती हैं। क्या इन फसलों को बचाने के लिए सरकार हमें पानी देगी ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी ओम प्रकाश बैरो : अध्यक्ष महोदय, दादूपुर-नलवी नहर जब सैंक्शन की गई थी, तब से लेकर आज तक इस पर कितने करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है ? इसके साथ ही क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि जो वर्ल्ड बैंक से आठ सौ करोड़ रुपए मिल रहे हैं उसमें से कुछ पैसा इस कैनाल पर खर्च करने का प्रावधान करेंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम 1985 में सैंक्शन हुई थी। उस समय यह स्कीम 13 करोड़ रुपए की थी और आज 65 करोड़ रुपए की है। पहले जब डिजाइन किया था उस समय इसकी कैपेसिटी 590 क्यूसिक की थी और इससे जो एरिया कमान्ड हो रहा है, वह 1,86,114 एकड़ है। लाडवा वगैरह को मिलाकर इसकी टोटल लैन्थ 381.40 किलोमीटर है।

दूसरे इन्होंने वर्ल्ड बैंक की बात कही है। यह वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ जमुना के पानी के बंटवारे की बात जुड़ी हुई है। जमुना का पानी पांच सूबों में बंटना है और जब बंटवारा हो जाएगा, तब यह स्कीम आएगी। दादूपुर नलवी, हथनी कुण्ड बैराज, डब्ल्यू0जे0सी0 में पानी की कैपेसिटी बढ़ाना, जे0एल0एन0 की सप्लाई ठीक करना, दिल्ली कैनाल को पैरेनियल

[चौधरी जगदीश नेहरा]

बनाना, गुड़गांव कैनाल की कैपेसिटी बढ़ाना, किसाऊ डैम, रेणुका डैम, गिरी बाटा डैम और जमुना हाईडल पावर स्टेशन की स्कीमें हैं जो पानी के बंटवारे के बाद ही पूरी होंगी। इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें जमुना के पानी से जुड़ी हुई हैं। जरूर महोदय, जब पानी का बंटवारा हो जाएगा तो केन्द्रीय सरकार से भी सहायता मिलेगी। इनमें किसी स्कीम पर 40 करोड़, किसी पर 80 करोड़, किसी पर 100 करोड़ और किसी पर 400 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। सर, इसका संबंध केन्द्रीय सरकार से है।

श्री के0एल0 शर्मा : स्पीकर साहब, मैंने भी इसी क्वैश्चन को हाऊस में मार्च 1992 के सैशन में उठाया था और उस समय मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि ये दादूपुर-नलवी की जो स्कीम है, यह अंडर कंसीडरेशन है लेकिन बाद में कहा कि यह स्कीम छोड़ दी गई है। परन्तु अब फिर मन्त्री जी ने लहरी सिंह के सवाल के जवाब में बताया है कि यह स्कीम अभी अंडर कंसीडरेशन है लेकिन 1993 के सैशन में भी इन्होंने कहा था इस स्कीम को शुरू करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो इन्होंने कहा कि यह स्कीम अंडर कंसीडरेशन है, यह किन प्वायंट्स के आधार पर कहा गया है ? क्या कोई पैसा इसके लिए मंजूर हुआ है और इसके बारे में कोई एक्शन लिया गया है, अगर लिया है तो इस को कब तक चालू कर देंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इस स्कीम को अंडर कंसीडरेशन इस लिए कहा गया है क्योंकि कई मुद्दे और कई चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अंडर कंसीडरेशन का मतलब है कि अभी हमारे हाथ में पूरी तरह से यह बात नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह स्कीम पांच सूबों से जुड़ी हुई है, जिसमें हिमाचल, यू0पी0, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। इन सूबों के बीच में जो भी समझौता होगा, उसके बाद ही यह केस केन्द्रीय सरकार के सी0डब्ल्यू0सी0 के सामने रखा जायेगा तथा इसके बाद प्लानिंग कमीशन में जाएगा और उसके बाद ही इसके लिए बजट में प्रावधान किया जायेगा। स्पीकर सर, इस तरह से यह सारा सिस्टम कम्पलीट करना है इसीलिए यह स्कीम अन्डर कंसीडरेशन है। यह काम इनकी सरकार की औकात से बाहर का है।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी नेहरा जी ने कहा कि यह काम हमारी औकात का नहीं है। (विघ्न) स्पीकर सर, सवाल दादूपुर नलवी का था। अभी नेहरा साहब ने बड़ी ही सीरियस बात कही है जिसके बारे में हमने भी बार-बार सवाल उठाया है और मुख्य मन्त्री जी ने भी अपना बयान दिया है। स्पीकर सर, इन्होंने बड़े धड़ल्ले से गवर्नर ऐड्रैस में भी बोल दिया कि जमुना के वाटर में केवल दो

ही स्टेट्स का शेयर है, और वह हैं यू0पी0 और हरियाणा । लेकिन अभी नेहरा जी कह रहे हैं कि जमुना के वाटर में पांच स्टेट्स का डिस्प्यूट है और इनके बीच में जल्दी ही कोई फैसला होने वाला है । ये इस फैसले के बाद ही दादूपुर नलवी स्कीम को टेकअप करेंगे । इन्होंने कहा कि यह स्कीम अभी अंडर कंसीडेशन है । मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये दोगली बातें क्यों करते हैं ? मुख्यमन्त्री जी स्पष्ट करें कि क्या उस जमुना के वाटर में उन तीनों स्टेट्स का भी हिस्सा है ? स्पीकर सर, मैं मुख्यमन्त्री जी से कहूंगा कि मंत्री जी ने जो बयानबाजी की है, उसको स्पष्ट करें । हमें मन्त्री जी की बात से शंका हो रही है । स्पीकर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दादूपुर नलवी की स्कीम जमुना के पानी से जुड़ी हुई है । जितना जमुना का पानी फालतू होगा, वह इस स्कीम के माध्यम से दादूपुर-नलवी कैनाल में आएगा । (विघ्न) स्पीकर सर, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, गलत बात कहने से कोई फायदा नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बरसात में तो आपके पास काफी पानी हो जाता है । क्या आप उस नहर को बनाकर बरसात के मौसम में उसमें पानी नहीं छोड़ सकते ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यही कई बातें अंडर कंसीडेशन हैं । जो सवाल आपने किया है, वह बड़ा रेलैवेन्ट है और इसीलिए जो समझौते होने हैं, उनके तहत इस नहर की जो कैपेसिटी है, यानी बारह हजार क्यूसिक से तेईस हजार क्यूसिक के लिए इस नहर को तैयार करना है जो फ्लड का वाटर भी ले जाए, चाहे वह इरीगेशन के लिए हो, चाहे री-चार्जिंग के लिए हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप बैठ जाइए । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें सिवाये हरियाणा और यू0पी0 के इरीगेशन के लिए बाकी और किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है । पीने के पानी के लिए मानवता के आधार पर सारे देश की पौसिसी बननें जा रही है कि जहां पीने के पानी का संकट है, वहां पीने का पानी दिया जाए । दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया के लोग यहां आते हैं । उन्होंने पंजाब से भी कहा है कि एस0वाई0एल0 के रास्ते से दिल्ली को पीने का पानी दें । इसी बात को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली में 3-4 बार मीटिंग हुई हैं कि दिल्ली को पीने का पानी देना है । दिल्ली वाले भी बदले में हमको पानी देंगे । दिल्ली का जो गन्दा पानी है उसको बाकायदा साफ करके हमें सप्लाई करेंगे ।

प्रो0 सम्पत सिंह : इसमें और कौन-कौन सी स्टेट्स शामिल हैं ?

चौधरी भजन लाल : इनमें यू0पी0, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पांचवां हिमाचल प्रदेश है ।

श्री अध्यक्ष : हिमाचल से तो सारी नदियां होकर आती हैं ?

चौधरी भजन लाल : हिमाचल को पानी नहीं, बिजली की बात है। रेणुका और किसाऊ डैम के पानी में हिमाचल का शेयर नहीं है। मेन चार स्टेट्स हैं। वैसे शेयर तो दिल्ली का भी नहीं है। पानी अगर सिंचाई के लिए दिया जाए तो पानी के बंटवारे का सवाल होता है। मानवीय आधार पर उनको पीने का पानी दिया है क्योंकि दिल्ली में आबादी बढ़ रही है। हरियाणा के लोग भी वहां रहते हैं, यू0पी0 के लोग भी रहते हैं। देश की मान मर्यादा का सवाल है। अगर हम पीने का पानी दिल्ली को नहीं दे सकेंगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे ? मानवीय आधार पर सिर्फ आर्जी तौर पर कुछ समय के लिए पीने के लिए पानी दिया है। इसमें शेयर की कोई बात नहीं है। बार-बार वैसे ही ये बात कह रहे हैं, अब बात खत्म हो गयी है। (व्यवधान व शोर)

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इन्होंने यह कहा है कि 5 स्टेट्स की टाक्स ही रही हैं और मामला अंडर कंसीडेशन है। (व्यवधान व शोर)

Declaration of Farukh Nagar as a Sub-Tehsil

*753. **Shri Mohan Lal Pippal** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Farukh Nagar as a Sub-Tehsil; and

(b) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materialized ?

राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह) :

(क) हां जी।

(ख) निश्चित समय नहीं दिया जा सकता।

श्री मोहन लाल पिपल : स्पीकर महोदय, मन्त्री जी ने मेरे सवाल के भाग "क" के जवाब में 'हां जी' कह दिया है लेकिन "ख" का जवाब देते समय यह कह दिया है कि इस बारे में निश्चित समय नहीं दिया जा सकता। सर, यह तो हमारे इलाके की मांग है इसको कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री निर्मल सिंह : अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

Construction of Metalled Roads

*853. **Shri Chander Mohan :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to launch a crash programme to connect all the villages in Shivalik Region with metalled roads; and

(b) if so, the time by which the villages as referred to in part (a) above are likely to be connected ?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) :

(क) और (ख) : शिवालिक क्षेत्र के शेष काबिल डायरैक्ट्री गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है परन्तु इनका पूरा करना भारत सरकार द्वारा डिफोरैस्टेशन की अनुमति जहां तक आवश्यक हो तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने यह बताया है कि भारत सरकार जब मंजूरी देगी, तब इस क्षेत्र के बाकी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा । भारत सरकार से मंजूरी लेना तो स्टेट गवर्नमैंट का काम है, किसी आदमी विशेष का काम नहीं है । मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की यह नीति है कि हरेक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा । मैदानी इलाके में तो सरकार ने इस बारे में काफी सराहनीय कार्य किया है लेकिन मेरे क्षेत्र मोरनी के पहाड़ी क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं है । उन गांवों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है । भारत सरकार से आप कब तक मंजूरी प्राप्त कर लेंगे और कब तक वहां पर काम शुरू करा देंगे ? अब तक क्या ऐक्शन हुआ है, क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस पहाड़ी क्षेत्र के लगभग हरेक गांव को, जिनकी आबादी मैदान में 250 की है और पहाड़ी क्षेत्र में 150 की है पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है । अब केवल 7 गांव ऐसे हैं जिनको जोड़ना शेष रहता है । राज्य सरकार इसके लिये पहले ही स्वीकृति दे चुकी है । यह सड़कें तभी बन सकेंगी जब उन पर डी-फारैस्टेशन का काम करने के लिए भारत सरकार से अनुमति मिल जायेगी । इस बारे में हम कई पत्र भारत सरकार को लिख चुके हैं और हर लैवल पर मीटिंग भी हो चुकी है । अब आशा की जाती है कि डी-फारैस्टेशन के कार्य के लिये जल्दी ही हमें अनुमति मिल जायेगी । लेकिन इन सड़कों को जोड़ने के लिये अवधि या कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि जब तक फारैस्ट डिपार्टमैंट को सैंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से क्लीयरैंस न मिल जाये, तब तक हम इनको बना नहीं सकेंगे ।

Upgradation of Schools

***744. Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Minister for Education be please to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the following schools—

(i) Govt. Girls High School, Beri to Senior Secondary School;

(ii) Govt. Girls Middle School, Majra to High School;

(iii) Govt. Girls Primary School, Chimni to Senior Secondary School;

(iv) Govt. Primary School, Bakra to Middle School; and

(b) if so, the time by which the schools referred to in part (a) above are likely to be upgraded ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana) :

(a) No, Sir.

(b) Upgradation cases can be considered as per need of the area and subject to the availability of funds.

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अपग्रेडेशन के लिये फंड्ज होने चाहियें । जहां तक अवेलेबिलिटी आफ फंडज का ताल्लुक है, वह तो ये खुद ही करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है । जिन स्कूलों का जिक्र मैंने अपग्रेडेशन के लिये अपने सवाल में किया है, मैं इस बारे में इन को यह बता दूं और इस बारे में चाहे ये अपने डिपार्टमैंट से पूछ भी लें कि 21-6-1992 को, जब मुख्य मन्त्री बेरी में गये थे, तो वहां पर इन स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिये एलान करके आये थे । जहां तक बेरी का ताल्लुक है, वहां पर 20 हजार के करीब आबादी है । इसमें दो हजार के करीब लड़कियां/बच्चियां पढ़ती है । इसी तरह से एक माजरा गांव है । उसकी आबादी भी करीब 13,000 है । इसी तरह से चिमनी की आबादी 7-8 हजार के करीब है । वहां पर बिल्डिंग एक कालेज जसी बना रखी है । इसी तरह से बाकरा में भी यही हालत है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए आश्वासन देंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, बेरी साहब ने कहा है कि मुख्य मन्त्री जी बेरी गए थे और इन स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा करके आए थे । अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने केवल बेरी के स्कूल के लिए घोषणा की थी । मैं बेरी साहब को बताना चाहता हूं कि बेरी में पहले से 10+2 का स्कूल चल

रहा है, इसलिए परमावश्यक न समझ कर उस पर अगले वर्ष विचार कर लिया जाएगा । जहां तक दूसरे स्कूलों के अपग्रेडेशन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, प्रान्त में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर 2.33 किलोमीटर की परिधि से कोई स्कूल दूर पड़ता हो । अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब हम और आप पढ़ा करते थे तो दस बारह किलोमीटर हमें स्कूल के लिए जाना पड़ता था । आज तो शिक्षा विभाग ने शिक्षा के केन्द्र जगह-जगह खोल दिए हैं । आज शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी चेतना पैदा कर दी है । आप लोग अध्यापकों को कहें कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और बच्चों को पढ़ाएं ।

चौधरी अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि हरियाणा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 2.33 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर 10+2 का कोई स्कूल न हो । अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में आज हथीन से मढ़कोला पन्द्रह किलोमीटर का फासला है लेकिन वहां बीच में 10+2 का कोई स्कूल नहीं है, मलाई से हथीन बारह किलोमीटर है और वहां कोई स्कूल नहीं है । मलाई से हथीन ग्यारह किलोमीटर का फासला है लेकिन वहां पर बीच में कोई 10+2 का स्कूल नहीं है । हथीन से औरंगाबाद का फासला तेरह किलोमीटर है लेकिन वहां भी 10+2 का कोई स्कूल बीच में नहीं है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये अम्बाला के आंकड़े दे रहे हैं या भिवानी, हिसार और सिरसा के आंकड़े दे रहे हैं ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त अजमत खां स्वयं अध्यापक रहे हैं । ये जो मैंने फिगर्ज दी हैं, ये ऐवरेज फिगर्ज हैं । ये जो पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर का फासला बता रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पन्द्रह किलोमीटर तक कोई स्कूल न हो । जो मैंने फिगर्ज बताई हैं, उसका मतलब यह है कि फासला ऐवरेज इतना बनता है ।

श्री असीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, कौन से इलाके की ऐवरेज बता रहे हैं ? ये हरियाणा की ऐवरेज बता रहे हैं या किसी और इलाके की ऐवरेज बता रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी ऐवरेज दो तीन किलोमीटर नहीं बनती । हर जगह दस पन्द्रह किलोमीटर से कम फासले पर कोई भी 10+2 का स्कूल नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 10+2 की बात नहीं है । जो फासला बताया गया है वह स्कूल का बताया गया है । हर किलोमीटर पर एक प्राईमरी स्कूल है, दो किलोमीटर पर मिडिल स्कूल है और पांच किलोमीटर पर हाई स्कूल है। ऐसा नहीं कहा कि 10+2 का स्कूल 2.33 किलोमीटर पर है ।

श्री रमेश चन्द : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि हर 2.33 किलोमीटर पर 10+2 का स्कूल है । स्पीकर साहब, इतने फासले पर कहीं कोई स्कूल नहीं है । मेरे बड़ौदा हल्के में सिवानका गांव है, वहां के बच्चों को आठ-आठ किलोमीटर पर स्कूल जाना पड़ता है । न वहां पर कोई हाई स्कूल है और न कोई 10+2 का स्कूल है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेरे हल्के के सिवानका गांव में कोई 10+2 का स्कूल खोलने की स्कीम विचाराधीन है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में कितने प्राईमरी स्कूलों को मिडल स्कूल अपग्रेड किया जायेगा, कितने मिडल से हाई और कितने हाई से 10+2 बनाए जाएंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने एक सवाल के जवाब में बताया था कि यह सब कुछ बजट पर निर्भर करता है । इस बार माननीय सदस्य ने वि मन्त्री श्री मांगेराम गुप्ता जी का एड्रैस भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि 50 स्कूल प्राईमरी से मिडल और 25 स्कूल मिडल से हाई अपग्रेड किये जाएंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 759

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री दरियाओ सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

Jaundice Disease in Pehowa City

***818. Shri Jaswinder Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether any cases of Jaundice disease have been reported from Pehowa City during the months of November, December, 1993 and January, 1994, if so, the reasons therefor; and

(b) the steps, if any taken to prevent the occurrence of such type of disease in future ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) :

(क) हां, मास नवम्बर, दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी, 1994 के दौरान पेहवा शहर में पीलिया रोग के 4 मामले प्रकाश में आए हैं ।

पीलिया एक जल दूषित रोग है जो मल दूषित जल के पीने से होता है ।

(ख) (1) पीने के पानी की क्लोरीनेशन ।

(2) लीकिंग पाईपों की मुरम्मत करना ।

(3) रेजिडूवल क्लोरीन तथा जीवाणु परीक्षण के लिये पानी के नमूनों की नियमित चैकिंग ।

(4) स्वास्थ्य शिक्षा ।

(5) ऐपीडैमिक डीजीजिज एक्ट, 1897 को लागू करना ।

(6) जिला स्तर पर दूषित जल से फैलने वाले रोगों के नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सिविल सर्जन, अधीक्षक अभियन्ता/कार्यकारी अभियन्ता (जन स्वास्थ्य), जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा प्रधान नगरपालिका सदस्य होते हैं ।

श्री जसविन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मन्त्री महोदया ने मेरे सवाल के जवाब में यह माना है कि मास नवम्बर, दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी, 1994 के दौरान पेहवा शहर में पीलिया रोग के केवल 4 मामले प्रकाश में आये हैं । अध्यक्ष महोदय, पेहवा एक यात्री स्थान है, वहां पर यात्री आते जाते रहते हैं और लगभग 50 के करीब वहां प्राईवेट हस्पताल भी हैं । वहां पर 7 केसिज गवर्नमैंट हस्पताल में काफी सीरियस हैं और लगभग 600-700 केसिज हमारे नोटिस में आ चुके हैं जिनमें से दो व्यक्तियों की तो मौत भी हो चुकी है । इस रोग के फैलने का कारण यह है कि वहां का जो सीवरेज सिस्टम है, वह बहुत ही खराब हो चुका है और सीवरेज का गन्दा पानी पीने के पानी के साथ मिल जाता है । 12 नम्बर वार्ड में तो यह शिकायत सब से ज्यादा है । मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इन सारे हालात को देखते हुए वे कब तक पीने के स्वच्छ पानी का प्रबन्ध लोगों के लिये करवा पाएंगी ताकि लोगों को इस रोग से बचाया जा सके जो सीवरेज की गन्दगी के कारण फैलता है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और आज एक बहुत जटिल समस्या सीवरेज के गन्दे पानी की और स्वच्छ पानी की हमारे समक्ष खड़ी है । वैसे तो सीवरेज की पाईप्स और स्वच्छ पानी की पाईप्स एक दूसरे से काफी दूरी पर होनी चाहिएं लेकिन वहां पर दोनों ही पाईप्स साथ साथ चल रही हैं जिससे सीवरेज का जो दूषित पानी है, वह स्वच्छ पानी में मिल रहा है क्योंकि वे दोनों पाईप्स बिल्कुल साथ साथ जा रही हैं ।

[श्रीमती शान्ति देवी राठी]

पाईप्स की लीकेज के कारण पानी आपस में मिल जाता है और लोगों को वह गन्दा पानी पीने से पीलिया का रोग हो जाता है और इससे बच्चे, बूढ़े व जवान, सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह बात इनकी सही है कि पीलिया एक जल दूषित रोग है जो मल दूषित जल के पीने से होता है । इसकी रोकथाम के लिये सरकार पूरी तरह से सजग है । इसके लिये जन स्वास्थ्य विभाग से भी मैंने निजी तौर पर अनुरोध किया है और लिखा है कि वह कम से कम किसी भी विस्तार से पहले, जो खस्ता हालत की सीवरेज की या दूसरी पाईप्स हैं, जो 14-14, व 15-15 साल पुरानी चली आ रही हैं, कम से कम उनको पहले रिप्लेस करें । इस बारे में काफी काम हुआ भी है और भविष्य में हम और सतर्कता बरत रहे हैं । हमारा भविष्य में यह प्रयास होगा कि सीवरेज के पानी से जो दूषित जल होता है, उसकी लीकेज के कारण भविष्य में ऐसा कोई बाकया न होने पाए । जैसा इन्होंने कहा है कि पीलिया के ज्यादा केसिज हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई हैं, मैं इस बारे में इन्हें बता देना चाहती हूं कि अब तक हमारे रिकार्ड के अनुसार केवल चार मामले प्रकाश में आये हैं, मृत्यु का कोई केस अभी तक हमारे सामने नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, पेहवा एक तीर्थ स्थान है । बहुत सारे यात्री रोजाना आते जाते हैं । पेहवा के बारे में बताएं कि स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी ?

श्री जसविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं आया है । जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि सात केसिज हमारी जानकारी के अनुसार काफी सीरियस हैं । वहां के जो तहसीलदार हैं, वे शेर सिंह जी के रिश्तेदार हैं, वे बीमार हुए, सिविल हस्पताल के डाक्टर श्री कोहली भी बीमार हुए । म्युनिसिपल कमेटी के जो प्रेजीडैन्ट हैं, उनका बेटा बहुत सीरियस है । इस तरह से और बहुत से केसिज हमारी नालिज में हैं । मन्त्री महोदया ने तो केवल वे फिगर्ज बताई हैं जो सिविल हस्पताल की हैं । पेहवा में लगभग 50 के करीब प्राईवेट हस्पताल हैं जहां पर लोग इस रोग का इलाज करवा रहे हैं । मेरा स्पीकर साहब, आपके माध्यम से यह कहना है कि कब तक वे पेहवा के दूषित जल को पीने के लायक बनवा देंगे और कब तक सीवरेज की जो टूटी फूटी पाईप्स हैं, जिनका पानी रिस कर पीने की पाईप्स द्वारा लोगों के घरों तक जाता है, उसको रिपेयर करवा देंगे ताकि लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके और इस तरह पीलिया जैसी भयानक बीमारियां आगे से न हो सकें, कब तक यह कार्य करवा देंगी ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि पीलिया से पीड़ित काफी केस हो सकते हैं लेकिन विभाग ने जो रिपोर्ट मुझे दी है, वह मैंने यहां पर बता दी है । अगर माननीय सदस्य के नोटिस में और केसिज हैं तो वे हमें लिख कर भेज दें, उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी । हमने जन स्वास्थ्य विभाग से

पहले ही अनुरोध कर रखा है कि जो पाइप लीक कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करवाया जाये।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जिस जगह पर पाइप ठीक नहीं हैं यानी पाइप से लीकेज हो कर पीने वाले पानी के साथ सीवरेज का पानी मिल जाता है तो उस गन्दे पानी को पीने की वजह से पीलिए की बीमारी फैल सकती है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां जहां पर ऐसी समस्या है, जहां सीवरेज के पाइप लीक करते हैं, उनको सबसे पहले बदला जाएगा ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी देकर पीलिए की बीमारी से बचाया जा सके।

Chhainsa Power Sub-Station

***824. Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the capacity of power Sub-Stations of Chhainsa in District Faridabad ?

Power Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Yes, Sir.

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पावर पोर्टफोलियो संभालने के बाद इसमें बहुत सुधार किया है। मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 'जी हां'। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल मात्र 'जी हां' कहने से मेरे क्षेत्र के लोगों की तसल्ली नहीं होगी। कृपया आप सदन में आश्वासन दें कि छांयसा के पावर सब स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम आने वाले अप्रैल के महीने में शुरू कर दिया जाएगा ?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने जो अपने इलाके का दुख जाहिर किया है, मैं उसके साथ सहमत हूं। इस समय चूंकि छांयसा को हम बदरोला से सप्लाई दे रहे हैं, फिर भी छांयसा में एक की बजाए दो ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। सरकार को इस बात का एहसास है और यह कमी तो आज के दिन हम पूरी कर लेंगे लेकिन हमें पता है कि आने वाले दिनों में बिजली की कमी होगी, इसलिए हमने उसके लिए एक रिपोर्ट पहले ही मांग ली है। हमने उसकी टैक्नीकल फिजिबिल्टी मांग ली है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ऐसा वक्त नहीं आएगा कि आपको गिला रहे। हम पैसे के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस करन्ट ईयर में सारा काम क्लीयर करके काम शुरू करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री धनी राम केहरवाला : अध्यक्ष महोदय, पावर सब स्टेशंज की कैपेसिटी बढ़ाने की कई जगह जरूरत है। जैसे एलनाबाद में और ऐरीवाला में जो ट्रांसफार्मर्ज लगे हुए हैं, वे जरूरत के मुताबिक छोटे हैं। वहां की जरूरत कब तक पूरी कर दी जाएगी ?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, यह सवाल तो बल्लभगढ़ के छांयसा का था लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैंने पिछले दो तीन सवालों के जवाब में हर जिले के बारे में डिटेल में बताया है । जहां ये समझते हैं कि ओवर लोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर को एडीशनल रिकवायरमैंट है, वे कृपया मुझे बता दें ताकि मैं उन पर हाउस में फारमैलिटी के तौर पर जवाब ही न दूं बल्कि उस काम को करवा भी सकूं ।

Cases Registered under the violation of Essential Commodities Act

***836. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) whether any cases have been registered under the violation for Essential Commodities Act with the Police in the State during the year 1993-94, if so, the number thereof; and

(b) the number of licences of depot holders, if any cancelled under the detection of mal-practice and irregularities in Public Distribution System in the State during the period mentioned in Part(a) above ?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) हां, वर्ष 1993-94 में (28 फरवरी, 94 तक) आवश्यक वस्तुयें अधिनियम की उल्लंघना करने पर पुलिस के पास 100 मामले दर्ज करवाये, और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान जन वितरण प्रणाली के तहत अवैध कार्य करने तथा अनियमितताएं करने के कारण 180 डिपो धारकों की अथोरिटी (जिसे आमतौर पर डिपो का लाईसेन्स भी कहा जाता है), रद्द किये गये ।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 100 मामले दर्ज किए गए हैं, उनका जिलावार ब्यौरा क्या है तथा किस किस जिले में कितने कितने केस दर्ज हुए हैं ?

15.00 बजे

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 1993-94 तक जिन डिपो होल्डर्ज या लाईसैंसीज की अनियमितताएं पाई गई, उनके खिलाफ 100 केस दर्ज करवाए गए। उनका जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है : अम्बाला जिले में पांच, जमुनानगर जिले में 13, भिवानी जिले में तीन, सोनीपत जिले में चार, रिवाड़ी जिले में 6,

कैथल जिले में पांच, हिसार जिले में 8, सिरसा जिले में 10, कुरुक्षेत्र जिले में एक, फरीदाबाद जिले में 10, गुड़गांव जिले में 10, रोहतक जिले में दो, पानीपत जिले में 15, करनाल जिले में तीन, और नारनौल जिले में पांच । इस तरह से लगभग 100 केस दर्ज हुए ।

Harijan Chaupals

***841. Shri Ram Rattan :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) the number of Harijan Chaupals, if any, lying incomplete in Hassanpur Block, Distt. Faridabad; and

(b) the time by which construction work of the aforesaid Chaupals is likely to be completed ?

विकास मंत्री (राव बन्सी सिंह) :

(क) फरीदाबाद जिले में ऐसा कोई ब्लाक नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्पीकर साहब, भाई राम रतन ने यह सवाल पूछा है कि जिला फरीदाबाद के हसनपुर ब्लाक में कितनी हरिजन चौपालें अधूरी पड़ी हैं । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हसनपुर कोई ब्लाक नहीं है इसलिए वहां पर कोई हरिजन चौपाल अधूरी रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता । दरअसल मैं इसकी तसल्ली के लिए बताना चाहूंगा कि इनकी कांस्टीच्यूएंसी में दो ब्लाक पड़ते हैं—एक होडल और दूसरा पलवल । अब तक माननीय सदस्य की कांस्टीच्यूएंसी में 59 हरिजन चौपालें कम्पलीट की जा चुकी हैं । अब 25 चौपालें रहती हैं जिनको कम्पलीट करना है । ज्यों ही एफ0डी0 से पैसा रीलीज होगा, उनको कम्पलीट करने की कोशिश करेंगे ।

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में प्रहलादपुर, हुसंगाबाद, डकोरा, कुशलीपुर, शमसाबाद, बाता, गुन्दवास, करवन, सतवागढ़, गुलावद, लिखि और रुंधी यानि कम से कम 25 चौपालें ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हैं, उनको कब तक पूरा करवा दिया जाएगा ?

राव बंसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से भाई राम रतन जी को अभी बताया था कि 25 चौपालें इनकम्पलीट हैं । चौपालों के लिए 25 लाख रुपया मंजूर किया गया था, जिसमें से 15 लाख रुपया रिलीज हो चुका है और वह पैसा हमने जिलाबाइज डी0सीज0 को भेज दिया है । अब 10 लाख रुपया रिलीज

[राव बंसी सिंह]

होना बाकी रहता है । ज्यों ही पैसा हमारे पास आएगा, हम डी0 सीज0 को भेज देंगे और उस पैसे से जितनी चौपालें कम्पलीट की जा सकेंगी, उनको कम्पलीट करने की कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब क्वैश्चंज आवर समाप्त होता है ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखा गया तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Cases of Embezzlement

*773. **Ch. Azmat Khan :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether any cases of embezzlement in Hodel, Nuh and Ferozepur Jhirka sub division of H.S.E.B. has been detected during the period from 1986 to 1992; and

(b) if so, the total amount involved in each case of embezzlement togetherwith the names of the officials held responsible therefor and the action taken against them ?

Power Minister (Shri A.C. Chaudhary) :

(a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Following cases of embezzlement were detected during the period 1986 to 1992 in respect of the Operation Sub Divisions of Hodel and Nuh. There was no case of embezzlement at Operation Sub Divisions, Ferozepur Jhirka during the period.

Name of Sub Division	Amount involved	Name of officer/ Official	Action taken
Operation Sub Division, Nuh.	Rs. 10,53,405.92	Sh. Ajit Kumar Jain, L.D.C. (Cash)	Official arrested and released on bail. Presently under suspension. Case under investigation by Police.
Operation Sub Division, Hodal	Rs. 11,78,174.80	Sh. Siri Chand, Cashier. Sh. Gaisi Ram, U.D.C. (R) Sh. ulshan Nagpal, S.D.O., Sh. Giraj Singh, S.D.O. Sh. I.M. Jain, S.D.O. Sh. R.D. Dhiman, J.E.-I	Sh. Siri Chand Cashier. arrested and released on bail. The extent of responsibility of other officials is being determined for punitive action.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Roads

175. **Shri Mani Ram Rupawas :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the following roads of Distt. Sirsa—

(i) from village Rupawas to Jorkia;

(ii) from village Kumhariya to Rajasthan border;

(iii) from village Sahuwala-II to Sherpura;

(iv) from village Rupana Khurd to Nirwan; and

(v) from village Bakriyawali to Moriakhera; and

(b) if so, the time by which the afore-said roads are likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) :

(क) और (ख) क्रमांक 2, 4 और 5 पर वर्णित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन सड़कों का निर्माण धन की उपलब्धि के अनुसार जल्दी से जल्दी कर दिया जायेगा। क्रमांक 1 तथा 3 पर वर्णित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है। क्रमांक 1 तथा 3 पर वर्णित सड़कों के निर्माण के समय निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

Veterinary Hospital/Dispensary

176. **Shri Mani Ram Rupawas :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the most of the Veterinary Hospitals/Dispensaries of Darba-Kalan of Block Nathusari Chopta District Sirsa are without Doctors; if so, the time by which the doctors are likely to be posted therein; and

(b) whether it is also a fact that the most of the buildings of Veterinary Hospitals/Dispensaries of above said Block are in dilapidated condition; if so, the time by which the aforesaid buildings are likely to be repaired ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (राव धर्मपाल) :

(क) जी नहीं, केवल मात्र 1 पशु हस्पताल एवं प्रजनन केन्द्र तथा 12 पशु औषधालय, बिना पशु चिकित्सक/पशुधन विकास सहायक (वी0 एल0 डी0 ए0) के हैं । इन पदों को भरने बारे पग उठाए जा रहे हैं।

(ख) जी हां, उनकी हालात अच्छी नहीं है । पशु हस्पतालों/औषधालयों के भवनों की मुरम्मत हेतु धनराशि उपलब्ध होते ही कार्यवाही की जाएगी ।

Construction of Water Works at Village Rupawas and Arnianwali

177. **Shri Mani Ram Rupawas :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether the construction work of water works of village Rupawas and Arnianwali of Distt. Sirsa are lying incomplete; and

(b) if so, the time by which the work on the aforesaid water works is likely to be completed ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री रामपाल सिंह कंवर) :

(क) जी हां ।

(ख) रूपावास का जलघर दिनांक 22-12-94 तक तथा अरनियांवाली का जलघर 9/94 तक पूर्ण हो जायेगा ।

कथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में आज ही हमारे सदन के नेता चौधरी भजन लाल के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आपने यह प्रिविलेज मोशन कितने बजे दिया है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैंने 11.45 बजे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने 12.45 बजे दिया है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हाउस में पिछले दिनों मनोज कुमार मण्डल के बारे में चर्चा हुई थी, उस समय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि धनिक

लाल मंडल का कोई मामला नहीं है । लेकिन स्पीकर साहब, मैंने काफी भागदौड़ करके हर महकमे से कागज इकट्ठे किए हैं और मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने राज्यपाल महोदय की नजरों में अपनी छवि बनाने के लिए सदन के समक्ष जो स्टेटमैंट दी, वह गलत थी । यह मनोज कुमार मण्डल, जिसके पिता का नाम हरिकिशन मण्डल है, उनका एफिडेविट स्पीकर साहब, एक जगह नहीं, 3 जगह हरियाणा प्रदेश के कार्यालयों में पड़ा हुआ है । यही नहीं, इससे भी बड़ा धमाका यह है कि जो मनोज कुमार मण्डल है, वह बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता है । स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से 500 रुपये स्टाईपैंड लेने के लिए फार्म में बी0 सी0 को काट कर एस0 सी0 लिखा गया है और 500 रुपये का स्टाईपैंड वह एक दो महीने का ले चुका है । जिसके चैक नं0 व ड्राफ्ट नं0 मेरे पास लिखे हुए हैं । स्पीकर साहब, यही नहीं, गवर्नमैंट कालेज के उन दिनों वहां पर हरिसिंह प्रिंसिपल हुआ करते थे जिन्होंने इस मनोज कुमार मण्डल के लिए सारे गलत तरीके से काम किये । जब उस हरिसिंह का वहां से तबादला हुआ तो मनोज कुमार मण्डल ने फरीदाबाद कालेज के दफ्तर से गवर्नर साहब के निवास स्थान पर टेलिफोन बुक करवाया जिसका नंबर बाकायदा वहां के रजिस्टर में दर्ज है और अक्सर, वहां के जो लैक्चरार हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया करता है, उनके तबादले रुकवाने और करवाने का काम किया करता था । स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जानबूझ कर हमारे जो प्रैस के भाई हैं, उनमें अपनी छवि बनाने के लिए, इस देश में और प्रदेश में छवि बनाने के लिए, इस सदन को गुमराह किया है । स्पीकर साहब, यही हमारे मुख्यमंत्री महोदय की आदत है । (विघ्न)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अभी आप सुनो कि मैं क्या कहने वाला हूं ? (विघ्न) पहले आप सुनिए ।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आपकी बात हो चुकी है । (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब जब मनोज कुमार मण्डल को 500 रुपये स्टाईपैंड शिडयूल्ड कास्टस के नाम से दिए गए तो हरियाणा के अधिकारियों ने आडिट आब्जैक्शन लगाया और उस आडिट आब्जैक्शन को नकारा करके उसको 500 रुपये का स्टाईपैंड दिया गया । स्पीकर साहब, जब शिडयूल्ड कास्टस का स्टाईपैंड लेना होता है, तो एस0 सी0 का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है । वह व्यक्ति हरियाणा की जिस तहसील का रहने वाला है, वहां के उप-मण्डल अधिकारी (सि0) से सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे जाति प्रमाणपत्र कहते हैं । (विघ्न) स्पीकर साहब वह फार्म मैंने आपकी सेवा में दिया है । (विघ्न) इसमें एस0 डी0 एम0 का कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है । (शोर)

चौधरी भजन लाल : आप सुनेंगे तो पता लगेगा । (शोर) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे पहला निवेदन यह है कि अगर कोई आदमी हाउस में गलत प्रिवलेज मोशन दे

[चौधरी भजन लाल]

तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए ? (विघ्न) एक तो इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि कोई गलत स्टेटमैंट दे तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए ? दूसरे, जो इन्होंने कहा है, उसके लिए मेरा चैलेंज है या तो ये सदन से इस्तीफा दे देंगे या मैं दे दूंगा अगर मनोज कुमार गवर्नर साहब का पोता है और उसके बाप का नाम हरिकिशन है । गवर्नर साहब के किसी बेटे का नाम हरिकिशन नहीं है । गवर्नर साहब के दो बेटे हैं और इन दोनों बेटों का नाम हरिकिशन नहीं है। आज कोई आदमी लिख दे सन आफ भजन लाल । भजन लाल एक ही है देश में क्या ? कोई लिख दे जवाहरलाल नेहरू । गलती से नहीं लिखा, वह गलती कर बैठा, उसको जवाहर लाल नेहरू लिखना चाहिए था । अध्यक्ष महोदय, इस तरह से गलतबयानी की है, गलत बात की है, हाउस को गुमराह किया है, इसलिए ऐसे मैंबर के खिलाफ फौरन कार्यवाही होनी चाहिए । मेरा इस बात के लिए इनको चैलेंज है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, क्या आपने बैरीफाई कर लिया ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बनाइये । (शोर) वे गलत बात करते हैं, हाउस को गुमराह करते हैं । (शोर)

श्री मनी राम केहरवाला : यह हाउस में गलत बयानी कर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रिवेलेज मोशन आना चाहिए । (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, यह मामला अखबारों में छपा था और अखबारों की हैड लाईन में जिस तरीके से छपा था, वह आपके सामने रखा गया है । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : आपने लिख कर दिया है, अब आप भागने की कोशिश मत करिए । (शोर एवं विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा । (शोर)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आप हाउस की कमेटी बनाइये । (शोर) पेपर की क्या बात है ? (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप इस मामले को प्रिवेलेज कमेटी में एडमिट करिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : मनोज कुमार पोते का नाम नहीं, हरिकिशन बाप का नाम नहीं । (विघ्न) गवर्नर साहब के दो बेटे हैं, हरिकिशन नाम का उनका कोई बेटा नहीं है । (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर । स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैंने पेपर देख कर यह मोशन दिया, जबकि आज यह कह रहे हैं कि मैंने बड़ी भागदौड़ करके सारे कागज इकट्ठे किये हैं । फरीदाबाद एन0 आई0 टी0 का एड्रैस लिया है और मनोज कुमार की फोटो भी इन्होंने ली है जिसको ये यहां पर दिखा रहे हैं, टैलीफोन किया है, उनका स्टाईपैण्ड कन्सैशन जो होता है, उसके कागज इन्होंने भाग दौड़ कर हर चीज इकट्ठी की है । स्पीकर सर, यह सब किस के खिलाफ किया है ? मैं आपको याद कराना चाहता हूं और आपको तो पता ही है कि गवर्नर साहब के कण्डक्ट के बारे में यह असैम्बली किसी चीज को डिस्कस नहीं कर सकती । पार्लियामैंट प्रैजीडैन्ट के कण्डक्ट के बारे में और असैम्बली गवर्नर साहब के कण्डक्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकती। उस शख्स के बारे में इन्होंने बड़ी भागदौड़ की । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन लाए हैं कि इन्होंने झूठी स्टेटमैंट दी है । स्पीकर साहब, इस तरह से जो आदमी गैर-जिम्मेदारी वाली बातें करे, गलत बयानी करे, सारी बात गलत करे, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । स्पीकर साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिए । असैम्बली पार्टी वाईज रेशो के मुताबिक 5 मैम्बर्ज की एक कमेटी बना दीजिए और अगर उस कमेटी में ये बात गलत साबित हो जाए तो कमेटी जो रिकमैंड करें, उसके हिसाब से आगे कार्यवाही की जानी चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप यह बताइये कि क्या आप ऐफिडैविट देने के लिए तैयार हैं ? (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, ऐसा है कि ऐफिडैविट देने के लिए भी मैं तैयार हूं । (शोर) स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये । (विघ्न एवं शोर) यह मामला जिस दिन उठा था, मैंने उस दिन भी कहा था । (विघ्न एवं शोर) ऐफिडैविट देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है । (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने सवाल किया है कि क्या आप ऐफिडैविट देने के लिए तैयार हैं ? (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, ये जो कागज हैं इनमें ऐफिडैविट पहले से ही लगा हुआ है । यह ऐफिडैविट मेरा नहीं है, मनोज कुमार मण्डल के बाप का है । (शोर) स्पीकर सर, यह जो मामला मनोज कुमार मण्डल के बारे में था आप इसको प्रिविलेज कमेटी में डाल दीजिए । (शोर) प्रिविलेज कमेटी होती किस लिए है ? (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए । (विघ्न एवं शोर) राम पाल सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं ? (शोर)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री राम पाल सिंह कंवर) : स्पीकर साहब, प्रिविलेज मोशन लाने के लिए उसका बेस क्या होना चाहिए, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं ? अध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल जी ने जब खुद प्रिविलेज मोशन मूव करने का प्रयास किया है तो इन्होंने यह कहा कि प्रिविलेज मोशन लाने का हमारा बेस यह है कि हाउस को मिसलीड किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा जैसे कि आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि कमेटी बना दी जाए और उसकी रिपोर्ट मंगवा ली जाए । यदि रिपोर्ट आने के बाद यह साबित हो जाए कि मम्बर साहेबान ने प्रिविलैज मोशन मूव करते समय हाउस को मिसलीड किया है तो क्या यह प्रिविलैज मोशन मूव करने वाले के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता है ? (शोर) अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस के अन्दर आए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए । (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये । (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे जो सवाल किया है, आप उसके बारे में कहिए । आपने उनके ऐफिडैविट का जिक्र तो किया है । लेकिन आप अपना ऐफिडैविट देने के बारे में बताईये ? (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैंने तो रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनैस के रूल 265 के तहत आपको दरख्वास्त दी है । सदन की प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है । (शोर)

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर सर, श्री कर्ण सिंह दलाल प्रिविलेज मोशन लाए हैं । मुख्य मन्त्री जी ने चैलेन्ज किया है और साथ ही यह भी कहा है कि सदन के मैम्बर्ज की एक कमेटी बना दी जाए । इनकी बात ठीक है । सदन के पांच मैम्बर्ज को कमेटी बना दीजिए, उसको इन्क्वायरी कर लेने दीजिए और उसके बाद आगे की जो भी प्रोसीडिंग्ज होंगी, वह आप कर लें । (विघ्न एवं शोर)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, इनका ऐफिडैविट तो आना चाहिए । (शोर)

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब हाउस के मैम्बरों की कमेटी बनाई जा रही है तो फिर उसमें ऐफिडैविट की क्या बात रह जाती है ? (शोर)

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर सर, सदन में आज तक किसी भी मैम्बर का ऐफिडैविट नहीं लिया गया और न ऐफिडैविट लेने का कोई सवाल ही पैदा होता है । क्या आज तक सदन के किसी मैम्बर ने ऐफिडैविट दिया है ? (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ऐफिडैविट लेने की बात कही है कि ऐफिडैविट लिया जाए । क्या आज से पहले किसी से ऐफिडैविट लिया गया है या किसी ने दिया है ? मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि अब यह क्यों मांगा जा रहा है, क्यों सदन को गुमराह किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : कादयान जी, यह मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, यह मैंने कहा है । This matter is under consideration and I will tell you tomorrow. Please take your seat. That matter is finished now.

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर तो आपने एक्सटैन्ड कर दिया है, लेकिन मुझे इस पर दो शब्द कहने हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप इस पर नहीं कह सकते हैं, अगर आपको और कुछ कहना है तो कहें ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ एस० वाई० एल० के बारे में 19 तारीख को मीटिंग हो रही है । परन्तु पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने अखबार के मुताबिक कहा है कि 19 तारीख को कोई मीटिंग नहीं हो रही है। अब हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने कह दिया कि इस बारे में पंजाब के मुख्यमन्त्री ने कहा है बल्कि यह 25 तारीख को होने जा रही है उन्होंने कहा है—

> "Talking to reporters here, Mr. Beant Singh said that no meeting had been fixed for March 19 at Delhi for discussions on the construction of the SYL Canal."

Further, it is written—

> "Mr. Beant Singh said that he would go to Jalandhar on March, 19, to attend a function and was not aware of any meeting to be held in Delhi on that day."

तो स्पीकर साहब, यह जो एक अहम खबर अखबार में निकली है, इससे यह साबित होता है कि यह सरकार सीरियस नहीं है और लोगों को गुमराह कर रही है ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह मीटिंग पहले 19 तारीख को ही तय हुई थी लेकिन हमारे पास टैलेक्स आया कि अब मीटिंग 19 तारीख की बजाय 25 तारीख को होगी । यह रिकार्ड की बात है और टैलेक्स हमारे पास है । अगर आप चाहें तो पढ़ लेना ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने आज एक कालिंग अटैन्शन मोशन दी है । अध्यक्ष महोदय, कल के 14 मार्च, 1994 के इण्डियन एक्सप्रैस में एक खबर निकली है । वह खबर है कि ढूंढाहेड़ा गांव जो गुड़गांव जिले में है, वहां की 80 एकड़ से ज्यादा जमीन को हरियाणा सरकार के फाईनैन्शियल कमीशनर ने इन्तकाल को नामन्जूरी दे दी है । तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि नामन्जूरी किस हिसाब से दी गई है ? यह खबर अखबार में बहुत ही डिटेल में लिखी गई है कि इन्फलयुएंशियल आदमियों के हाथ में आज हकूमत है, वे उस जमीन को हड़पना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक जमाबन्दी की जिरोक्सकापी है । इसमें एक हवाला दिया गया है कि तबदील मलकीयत रैजुलेशन नं0 3, 5-5-79, चिट्ठी नं0 एफ0 आई0 590/707-10 डेटिड 30-1-90 है । इसमें एम0 के0 मिगलानी, कमीशनर एंड सैक्रेटरी आफ हरियाणा सरकार डिवैल्पमैंट एंड पंचायत हैं । अध्यक्ष महोदय, जब यह इन्तकाल दर्ज हुआ और जब यह जमीन पंचायत से लेकर टूरिज्म डिपार्टमैंट के नाम पर की गई तो पंचायत ने रेजुलेशन पास किया होगा क्योंकि इसमें भी रेजुलेशन का हवाला है, एम0 के0 मिगलानी के हुक्म का हवाला है और यह दर्ज किया गया है । खैर, यह बड़े ही ताज्जुब की बात है कि यह जो इन्तकाल तसदीक होने की तारीख है, यह एक जगह तो पहले मन्जूर की गई है और बाद में नामन्जूर कहा गया है । उसमें स्याही भी दो तरह की प्रयोग हुई है, यह बताते हैं । यह मुझे सही नहीं मालूम लेकिन एक बात का मुझे सही मालूम है कि इस इन्तकाल की तारीख एक जगह 10 तथा दूसरी जगह 11 लिखी हुई है और तीसरी जगह 25-3-92 लिखी हुई है । तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि तहसीलदार तो एक ही दस्तखत करने वाला है, फिर उसके एक दिन में तीन तारीखों में दस्तखत कैसे हो गये ? दस्तखत एक जगह हैं, तारीख तीन जगह हैं तथा तारीखें भी तीन अलग अलग हैं तो यह जमीन हड़पने की कोशिश क्यों की जा रही है ? इस इंडियन ऐक्सप्रैस अखबार की रूह से ऐसा लगता है कि पंचायत ने अन्डर प्रोटेस्ट रुपया लिया था और अगर पंचायत ने अन्डर प्रोटेस्ट रुपया लिया ही था तो सवाल सिर्फ इतना ही था कि कीमत उतनी हो या कीमत उससे ज्यादा हो । अगर ज्यादा हो तो कीमत बढ़ायी जा सकती थी । सरकार कीमत बढ़ाकर पंचायत को दे सकती थी । अध्यक्ष महोदय, इस जमाबंदी से साफ जाहिर हो गया है कि इन्तकाल दर्ज हुआ । उसमें बाकायदा कमिश्नर डिवैल्पमैन्ट की चिट्ठी का हवाला है, फिर यह इन्तकाल नामंजूर करने की नौबत कैसे आयी ? श्री एम0 के0 मिगलानी ने अपनी मर्जी से ही बगैर पंचायत के प्रस्ताव के हुक्म भेज दिया कि इस जमीन का इन्तकाल टूरिज्म डिपार्टमैंट के नाम कर दो । अध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो गया ? श्री मिगलानी के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया । अध्यक्ष महोदय, यह कागजों की मैनुपलेशन है, फैब्रिकेशन है या सच्चाई है तो इस विषय पर सरकार एक खुलासा ब्यान दे ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जो इशू चौधरी बंसीलाल जी ने उठाया है, इसमें दो तीन कंट्राडिक्शंज भी हैं । पहली तो यह है कि जो पंचायत ने रैजोल्यूशन

पास किया कि हमें जमीन नहीं बेचनी है और उनको मंजूरी भी मिल गयी बेचने की, और उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमैंट ने भी वह जमीन दस हजार रुपये एकड़ के हिसाब से ले ली । पंचायत ने मुआवजा अन्डर प्रोटेस्ट लिया । बाद में लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं और उनको फालतू मुआवजा मिल भी जाता है लेकिन बाद में जब इस जमीन का इन्तकाल हो गया तो उसके बाद टूरिज्म डिपोर्टमैंट के एक ज्वाइंट सैक्रेटरी ने डी० सी० को चिट्ठी लिखी कि हमें खदशा है कि इस जमीन का इन्तकाल खारिज करवाया जा रहा है और इस को खुर्दबुर्द करने का लोग प्रोग्राम बना रहे हैं । डी० सी० ने लिखा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इन्तकाल नहीं हुआ है । स्पीकर साहब, यह तो डी० सी० का बयान हो गया लेकिन इसके बाद में कमिश्नर साहब ने एफ० सी० आर० के लिए लिख दिया और उन्होंने कहा है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में है । स्पीकर साहब जब यह फैसला हो गया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में है, फिर पता नहीं उनको रात में सोकर सुबह जाग आ गयी और पता लगा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है बल्कि स्वयं मेरे अधिकार क्षेत्र में है । इसके बाद उन्होंने वापस कागज मंगवा लिए और स्वयं ही इन्तकाल खारिज करने के आर्डर कर दिए । स्पीकर सर, एक तरफ तो डी० सी० ने कहा है कि इन्ताकाल नहीं हुआ और दूसरी तरफ खारिज करने के आर्डर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ स्मैल जरूर आ रही है । इसलिए सरकार को ऐक्शन लेना चाहिए तथा इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए कि कौन लोग हैं, ताकि पता लग सके कि क्या मामला है ? क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमैंट को 80 एकड़ लैण्ड देने का फैसला कर दिया था और उसने वह जमीन ले ली थी तथा वहां पर उन्होंने हट्स वगैरह बना लिए थे, कुछ काम कर लिया था तथा बाढ़ वगैरह भी लगा दी थी । स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी भी उस रास्ते से आते जाते रहते हैं । दिल्ली और गुड़गांव के बौर्डर पर बाकायदा टूरिज्म विभाग का बोर्ड लगा रहता है, हम यहां पर कोई क्वेशनल सैन्टर या पर्यटन स्थल बनाने जा रहे हैं । स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि वह दिल्ली के पास है और टूरिज्म के लिए वह स्पौट अच्छी है । इससे तो हमारे टूरिज्म को ही प्रोत्साहन मिलता, लेकिन इस तरह से ऐसा लगता है कि सरकार टूरिज्म को एनकरेज न करके डिसकरेज करना चाहती है । इसलिए जो लोग इस मामले के पीछे हैं, उनको पकड़ने के लिए सरकार को इस मामले की इंक्वायरी करवानी चाहिए और उन लोगों को पब्लिक के सामने लाना चाहिए जिन्होंने गड़बड़ की है । इसके साथ ही मुख्यमन्त्री जी को टूरिज्म विभाग को यह लैण्ड देने के लिए अपनी कमिटमैन्ट भी करनी चाहिए कि टूरिज्म विभाग के पास ही यह लैण्ड रहेगी

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं असलियत बताना चाहता हूं ताकि आपको और हाउस को भी पता लग सके । अध्यक्ष महोदय, जब सम्पत सिंह और ओमप्रकाश चौटाला का राज था, तब की इस जमीन की बात है । यह ढुंढाहेड़ा की जमीन मुश्तरका मालकान की जमीन थी और यह मुशतरका मालकान

[चौधरी भजन लाल]

की जमीन पंचायत में वैस्ट हो गयी । इन्होंने यह जमीन पंचायत से दस हजार रुपये एकड़ के हिसाब से धक्के से टूरिज्म विभाग के नाम करवा दी । जबकि पंचायत यह जमीन नहीं देना चाहती थी । उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया । मालकान ने कहा कि जमीन हमारी है, हम पंचायत को नहीं देंगे । झगड़ा चलता रहा, इन्होंने क्या किया कि 18 एकड़ जमीन प्रकाश सिंह बादल को कौड़ियों के भाव में दे दी । यह रिकार्ड की बात है । इन्होंने चौधरी देवी लाल के धर्म भाई को वह जमीन दे दी । उस जमीन का भाव 10 से 15 लाख रुपये प्रति एकड़ से कम का नहीं था । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल : आपने जमीन का दाम क्या बताया है ?

चौधरी भजन लाल : 10 से 15 लाख रुपये एकड़ कम से कम है ।

चौधरी बंसी लाल : इससे भी कहीं ज्यादा है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, भजन लाल ने जिन्दगी में किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है । मिनिस्टर बने हुए इतने साल हो गए हैं, किसी एग्रीकल्चर इन्स्पैक्टर ने मेरे खेत को जाकर नहीं देखा । नहर भी खेत से निकलती है, कोई यह भी नहीं कह सकता कि भजन लाल ने बगली कर ली या पाइप डाल दिया । भजन लाल ने कभी कोई गलत काम नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मालिकान ने अपील दायर कर दी कि हमारा हक है, जमीन हमारी है, अब जुडिशियल केस है, कमिश्नर ने जो कुछ फैसला किया है, जुडिशियल नेचर के हिसाब से किया है, मैंने फाइल पर आर्डर किए हैं कि फौरन अपील दायर करो । जहां तक जमीन छोड़ने का सवाल है, कम से कम वो बात कहनी चाहिए जिसके पीछे कुछ सच्चाई हो या हेरफेर की बात हो । हमने न तो हेराफेरी कभी की है, न करने की सोच भी सकते हैं ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बड़े संक्षेप में जवाब दे दिया जिससे ऐसा लगा जैसे कोई झगड़ा ही न हो । अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात यह है कि इन्तकाल दर्ज हो गया और यहां से कमिश्नर ने कहा कि इसको ट्रांसफर कर दो टूरिज्म डिपार्टमैंट के नाम । क्या कमिश्नर को इस बात का अधिकार है कि जमीन का मालिक कौन है, इस बात का फैसला करे ? इस बात का फैसला तो दीवानी अदालत करेगी या हाईकोर्ट करेगा कि जमीन का मालिक कौन है ? टूरिज्म डिपार्टमैंट बराबर दखास्त देता रहा है कि हमको इसमें पार्टी बनाओ, हमारा नाम इसमें से हटाया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : बंसी लाल जी, आप ऐसी बात करते हो जैसे वायां भटिंडा वकील बनकर आए हो । जमीन के केस एस० डी० एम० से लेकर एफ० सी० आर० तक जुडीशियल नेचर के होते हैं ।

चौधरी बंसी लाल : मुख्यमन्त्री जी, आप तो भैरों सिंह शेखावत से पी0 एच0 डी0 की डिग्री लिए बैठे थे और जब ये जयपुर गए तो भैरों सिंह जी ने इनसे यह डिग्री छीन ली । (शोर)

चौधरी भजन लाल : किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछोगे तो बताएगा कि जमीन के केसेज, रैवेन्यू केसेज चाहे तहसीलदार के पास हों, चाहे डी0 सी0 के, पास हों, जुडीशियल नेचर के होते हैं । इसी तरह नम्बरदार के पास के केसिज हों तो वे भी जुडीशियल नेचर के होते हैं । आपकी पार्टी में भी एक दो वकील हैं । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं । मैं भी यह बात जानता हूं कि जमीन के केस एफ0 सी0 आर0 तक जुडिशयल नेचर के होते हैं मगर लाइटल का फैसला सिविल कोर्ट करेगी, रैवेन्यू कोर्ट नहीं कर सकती ।

चौधरी भजन लाल : जब इन्तकाल का कोई झगड़ा हो तो रैवेन्यू डिपार्टमैंट करेगा और ये केसिज एफ0 सी0 आर0 तक जाते हैं । एफ0 सी0 आर0 के बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं । कोर्ट ने जो फैसला किया है वह जुडीशियल नेचर के हिसाब से किया है । हम उसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं । सरकार इसके खिलाफ टूरिज्म डिपार्टमैंट की तरफ से अपील में जा रही है । जो हम कर सकते हैं, वह अवश्य करेंगे । (व्यवधान व शोर) ऐसे ही कहने से कोई बात नहीं बनती । जो ठीक बात होगी, हम वह करेंगे ।

श्री धीरपाल सिंह : जमीन खुर्द-बुर्द तो नहीं होगी ?

चौधरी भजन लाल : जमीन खुर्द बुर्द होने का तो कोई सवाल ही नहीं है ।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, अभी आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया है कि कमिश्नर फैसला कर सकता है । मुख्य मन्त्री जी के पड़ौस में नेहरा साहब बैठे हैं, वह भी वकील हैं । उनसे बेशक वह पूछ लें, इनको पता चल जायेगा । उस समय जुलाई, 1993 में कमिश्नर श्री पी0 पी0 छाबड़ा थे ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, यह जुडीशियल नेचर का केस है; क्या इसको यहां पर डिस्कस किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं ।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं । मैं एक बात जानना चाहता हूं । मुख्य मन्त्री महोदय को शायद यह पता नहीं होगा कि जो कमिश्नर हैं, उन्होंने अपना एक आर्डर जुलाई, 1993 में फाईनैंशियल

[श्री छत्तर सिंह चौहान]

कमिश्नर रैवेन्यू को भेज दिया । मुख्य मन्त्री महोदय यह बतायें कि अगर कोई कमिश्नर फैसला खुद कर दे तो क्या उसको वह खुद ही रिव्यु कर सकता है ? रिव्यु के मामले में रैवेन्यु की कोई किताब यह पढ़ लें तो बेहतर होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तहकीकात करके और किताब पढ़ कर जवाब दें । मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि कमिश्नर ने जो फैसला करके फाईनैंशियल कमिश्नर को भेज दिया, वह उसको अपने आप रिव्यु नहीं कर सकता ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पोजीशन थोड़ी सी क्लीयर कर दूं । इस अखबार में यह क्लीयर कट लिखा हुआ है कि कमिश्नर ने फैसला करके फाईनैंशियल कमिश्नर को भेज दिया । फाइनैंशियल कमिश्नर रैवेन्यु के पास यह फैसला जाने के बाद, क्या कमिश्नर उस फैसले को दोबारा खुद मंगा सकता है और रिव्यु कर सकता है या फाइनैंशियल कमिश्नर उसको वापिस भेजेगा ?

चौधरी भजन लाल : जो भी बात कानून के मुताबिक ठीक होगी, वही होगी । मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि हम किसी को उस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने देंगे ।

Mr. Speaker : It is a sub-judice matter and interpretation of law is involved. Therefore, no further discussion will be allowed on this matter.

साथी लहरी सिंह : सर, मेरा एक काल अटैंशन मोशन था ।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में ?

साथी लहरी सिंह : पोटेटो काप के बारे में था ।

श्री अध्यक्ष : यह अभी अंडर कंसीडेशन है, कमैंट्स के लिए सरकार के पास भेजा हुआ है ।

साथी लहरी सिंह : सर, यह कब तक अंडर कंसीडेशन रहेगा ?

श्री अमीर चन्द जक्कड़ : सर, मेरा भी एक काल अटैंशन मोशन था ।

श्री अध्यक्ष : आपका काल अटैंशन मोशन तो आज सवा एक बजे आया है । यह अभी अंडर कंसीडेशन है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

भिवानी शहर में पोलियो का रोग फैलने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 11, given notice of by Sarvshri Ram

Bhajan Aggarwal and Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. regarding breaking out of jaundice in Bhiwani city. I have admitted it. Shri Ram Bhajan Aggarwal may read his notice and thereafter the Health Minister may make a statement thereon.

*श्री राम भजन अग्रवाल
प्रो० छत्तर सिंह चौहान : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि भिवानी शहर में पीलिया फैला हुआ है तथा सैकड़ों व्यक्ति इस बीमारी के शिकार हैं तथा इस बात का डर है कि यह एक महामारी का रूप धारण कर सकती है। यह नागरिकों को सिवरेज खराब होने के कारण दूषित पीने का पानी सप्लाई करने के कारण से है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य—

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में पीलिया के 144 मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें से 11 मामले दिसम्बर, 1993 के अन्तिम सप्ताह में, 75 मामले जनवरी, 1994 तथा 58 मामले फरवरी, 1994 में प्रकाश में आए हैं। कोई मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

इस बीमारी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

1. पीने के पानी का उचित क्लोरीनेशन सुनिश्चित किया जा रहा है।
2. भिवानी शहर में घर-घर में पीलिया के मामलों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने, स्वास्थ्य शिक्षा देने, ट्रिकवैल गोलियों को वितरित करने एवं पीने के पानी में क्लोरीन अंश की उपस्थिति की जांच करने के लिए आठ पैरा मैडीकल टीमों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त बिड़ला टैक्सटाईल मिल तथा टैक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाईल की कालोनियों के लिए चार अन्य टीमें भी लगाई गई हैं।
3. मास जनवरी, 1994 में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि पीलिया के अधिकतर मामले बिड़ला टैक्सटाईल मिल तथा टैक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाईल की कालोनियों एवं आसपास के क्षेत्रों में पाये गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन कालोनियों की जल आपूर्ति बिड़ला टैक्सटाईल

*Read out by Shri Ram Bhajan Aggarwal.

[श्रीमती शान्ति देवी राठी]

मिल एवं टैक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टक्सटाईल में स्थित पानी के टैंकों से होती है। इन स्टोरेज टैंकों में पानी की आपूर्ति जन स्वास्थ्य स्त्रोतों एवं ट्यूबवैलों से मिल अथोरिटिज के टैंकरों द्वारा की जाती है।

4. जनवरी, 1994 में पानी में रेजिडुअल क्लोरीन की जांच के लिए पानी के 25 नमूनें लिए गए जो सभी नेगेटिव पाये गये। जनवरी तथा फरवरी 1994 में जन स्वास्थ्य विभाग, बिड़ला टैक्सटाईल मिल तथा टैक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाईल के अधिकारियों से निवेदन किया गया था कि पानी को सुपर क्लोरीनेशन की जाए। तत्पश्चात पीने के पानी के रेजीडुअल क्लोरीन टैस्ट करने हेतु फरवरी, 1994 में 32 नमूने लिए गए जो सभी पोजिटिव पाये गए।

5. पानी को उबाल कर पीने की आवश्यकता पर बल दिये जाने हेतु सभी को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जन चेतना हेतु जगह जगह पर पोस्टर्ज लगाये गए हैं। इस सम्बन्ध में हिदायतों सहित हैण्ड बिल्ज भी वितरित किये गये।

6. सभी पीने के पानी के स्त्रोतों की क्लोरीनेशन के अतिरिक्त 7000 ड्रिकवल गोलियां पानी की क्लोरिनेशन के लिए घर-घर में बांटी गई हैं।

7. जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार भिवानी शहर में उन द्वारा मास दिसम्बर, 1993, जनवरी तथा फरवरी, 1994 के दौरान 165 पानी के कनैक्शनों को ठीक किया गया।

8. जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी, 1994 में एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके अनुसार म्यूनिसिपल मेन से घरों तक जाने वाली जी0 आई0 पाईपें जो 10-15 साल या इससे अधिक पुरानी हो गई है तथा गल चुकी है, उन्हें बदलने की आवश्यकता है। यह कार्य उन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं जौन्डिस के लिए इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं, वे सत्य नहीं हैं। सी0 एम0 ओ0 ने 86 केसिज स्वयं एडमिट किये हैं लेकिन मन्त्री महोदया जब अपना जवाब पढ़ रही थीं तो उनके आंकड़े सी0 एम0 ओ0 के आंकड़ों से डिफर करते थे। क्या मन्त्री महोदया इस बारे में दोबारा सर्वे करवाएंगी ताकि उनको सही पोजीशन का पता चल सके? लोगों के घरों तक जाने वाली पानी की पाईपें

जो 10–15 साल या इससे अधिक पुरानी हो गई हैं तथा गल चुकी हैं उनके बारे में सरकार ने कहा है कि उन्हें बदलने की आवश्यकता है और साथ ही जवाब के अन्त में यह भी कहा है कि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लोगों को इस भंयकर रोग से बचाने के लिये क्या सरकार इस काम के लिये कोई समय निर्धारित करेगी ताकि निश्चित समय के अन्दर अन्दर यह सारा काम हो सके ? दो महीने, चार महीने, या छः महीने, कब तक सरकार इस काम को करवा देगी ताकि लोगों को भिवानी शहर के अन्दर पीने का शुद्ध पानी मिल सके ? मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि सरकार कब तक गली सड़ी सीवरेज की पाईपों को निकालेगी जो कम से कम 14–14, 15–15 सालों से खराब पड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से गन्दा सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिलकर दूषित हो जाता है। लोग उस पानी को पीते हैं और बीमार हो जाते हैं, कब तक उन गली सड़ी पाईपों को सरकार बदल देगी ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने तो पूरा भाषण ही दे डाला। जैसे पहले ही यह स्वीकार किया है कि भिवानी में पीलिया के 144 मामले प्रकाश में आए हैं। इस बारे में शिकायतें मिली भी हैं और इन सब बातों का हमने पहले ही विस्तार से जवाब दे दिया है, किसी प्रकार से हाउस को गुमराह करने वाली बात नहीं है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि पानी के मामले में चाहे हमारे विभाग की कोई भी अनियमितता हो, जन-स्वास्थ्य विभाग से जो भी अनियमितताएं हुई हों, उन का हम फौरन नोटिस लेते हैं और तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाती है ताकि पीलिया जैसे भंयकर रोग से लोगों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बोलते हुए सरकारी आंकड़ों को भी गलत बताया। मैं इनको बता देना चाहती हूं कि कोई भी आंकड़ा जो हमने बताया है, असत्य नहीं है। सभी सत्य हैं। यदि माननीय सदस्य महोदय चाहें तो सारी डिटेल में उनको बता सकती हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं बताना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिला भिवानी में पीलिया के केसों का क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है—शहर भिवानी में 17 कालोनियों में पीलिया के 137 केस हुए तथा 7 केस आस पास के गांवों में हुए। इस तरह कुल 144 केस जिला भिवानी से रिपोर्ट हुए। क्षेत्रवाईज स्थिति निम्नलिखित है :—

क्षेत्र का नाम	केसों की कुल संख्या
बिड़ला कालोनी	37
लेबर कालोनी	20
डी० सी० कालोनी	11

[श्रीमती शान्ति देवी राठी]

क्षेत्र का नाम	केसों की कुल संख्या
टी० आई० टी० कालोनी	32
कच्ची कालोनी	6
चरणजी कालोनी	5
सेवानगर	7
ब्रिजवासी कालोनी	4
बैंक कोठी	2
कृष्णा कालोनी	7
हरा कालोनी	2
अमल कालोनी	1
हनुमान धनी	2
जैन चौक	1
चिड़ियामार मुहल्ला	1
नीयर मुरारी सिनेमा	1
दुर्गा कालोनी	2
ग्रामीण क्षेत्र	
हलुवास (हलुवास)	5
नथुवास	1
पालुवास	1

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सब क्यों हुआ, इस बारे में बहन जी ने बताया नहीं। यह जो सीवरेज है, यह आज का लगा हुआ नहीं है। यह चौधरी बंसी लाल जी के वक्त का लगा हुआ है और इन्होंने ऐसा घटिया माल वहां लगा दिया जिसकी वजह से जगह जगह लीकेज हो गई और पीने के पानी में वह गन्दा पानी शामिल हो गया। इसी वजह से वहां पीलिया की गम्भीर

बीमारी फैल गई । इसको अब हम जल्दी ही ठीक कर रहे हैं, सरकार इसके लिये पूरी तरह से प्रयत्नशील है । यह सब कुछ चौधरी बंसीलाल जी की मेहरबानी से हो हुआ है । (हंसी)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय शायद किसी स्कूल या कालेज में पढ़े है या नहीं लेकिन ये अपने आपको राजनीति के पी० एच० डी० कहते हैं । जब ये राजस्थान में गये तो भैरों सिंह शेखावत ने इनकी पी० एच० डी० की डिग्री छीन ली (हंसी) अध्यक्ष महोदय, जो सीवरेज स्कीम हमारे वक्त में बनी थी, उस में कोई ऐसी बात नहीं थी। सीवरेज का कायदा होता है कि हर साल में दो बार उसको साफ किया जाए लेकिन छः छः साल से ऊपर का समय बीत चुका है और इस सरकार ने सीवरेज को साफ तक नहीं करवाया स्वभाविक है सीवरेज रुकेगा ही । जब जमीन का पानी ऊपर आ गया है, पहले वह साठ-सत्तर फुट पर था और अब पांच फुट पर आ गया है । जब यह उसकी सफाई नहीं करवायेंगे तो वह ठीक काम कैसे करेगी ? आजकल वैसे भी प्लास्टिक के लिफाफे आ गये हैं, अगर किसी ने सब्जी भी लानी है तो प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर दी जाती है । ये लिफाफे गिरने से भी सीवरेज बन्द हो जाता है । इसके बावजूद भी इन्होंने सीवरेज की सफाई की जरूरत नहीं समझी । स्पीकर साहब, सफाई कैसे हो क्योंकि जो मैन्टीनेंस का पैसा है, वह तो जेबों में चला जाता है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको हमेशा इस बात का फोबिया रहता है । चौधरी बंसी लाल जी, आप इतने पुराने मैम्बर हैं, कोई बात तो ठीक कहा करो । हमने इसको बाकायदा सफाई करवाई है लेकिन मैटीरियल इतना घटिया लगा हुआ है कि वह ठीक होने को नहीं आ रहा है ।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the demand for grants on Budget for the year 1994-95 will take place. As per past practice and to save the time of the House, all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon. Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a sum not exceeding Rs. **2,79,07,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. **55,52,98,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 2-General Administration.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding Rs. **1,96,10,64,000** revenue expenditure and **Rs. 4,50,00,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 3-Home.**

That a sum not exceeding Rs. **34,85,68,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 4-Revenue.**

That a sum not exceeding Rs. **14,57,86,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 5-Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. **1,39,79,09,000** for revenue expenditure be granted to the governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 6-Finance.**

hat a sum not exceeding Rs. **13,61,25,46,000** for revenue expenditure and Rs. **10,50,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 7-Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. 86,14,52,000 for revenue expenditure and Rs 81,77,60,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs 5,05,93,58,000 or revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs 3,28,94,57,000 for revenue expenditure and Rs 46,38,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 10-Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 13,86,18,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development

That a sum not exceeding Rs. 29,96,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 12-Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1,93,34,26,000 for revenue expenditure and Rs. 3,54,31,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 7,93,36,000 for revenue expenditure and Rs. 3,44,47,25,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. **9,96,15,50,000** for revenue expenditure and **Rs. 1,34,07,00,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 15-Irrigation.**

That a sum not exceeding Rs. **30,10,28,000** for revenue expenditure and Rs. **10,97,11,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 16-Industries.**

That a sum not exceeding Rs. **1,21,67,47,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 7-Agriculture.**

That a sum not exceeding Rs. **37,40,00,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No 18-Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs. **4,49,11,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 19-Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. **48,50.07,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 20-Forest.**

That a sum not exceeding Rs. **1, 7,32,90,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under **Demand No. 21-Community Development.**

That a sum not exceeding Rs. 13,94,54,000 for revenue expenditure and Rs. 8,61,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 2,54,83,92,000 for revenue expenditure and Rs. 37,93,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 85,02,000 for revenue expenditure and Rs. 2,60,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 3,23,38,97,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 25-Loans & Advances by State Govt.

I have also received notices of cut motions to the various demands from some M.L.As. These will also be deemed to have been read and moved. However, I will put the various cut motions to the vote of the House when the respective demands are put to the vote of the House. Such members may, however, participate in the discussion.

Demand No. 2

1. Shri Bansi Lal,
2. Shri Karan Singh Dalal,
3. Shri Chhattar Singh Chauhan; and
4. Smt. Janki Devi, M.L.As.

That Demand No. 2 of Rs. 56,83,99,000 on account of General Administration be reduced by Rs. 1/-.

[Mr. Speaker]

Demand No. 3

1. Shri Bansi Lal,
2. Shri Ram Bhajan,
3. Shri Karan Singh Dalal and
4. Shri Attar Singh, M.L.As. } :

That Demand No. 3 of Rs. 2,03,93,19,000 on account of Home be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 5

1. Shri Ram Bhajan, M.L.A. :

That Demand No. 5 of Rs. 14,57,96,000 on account of Excise & Taxation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 6

1. Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. :

That Demand No. 6 of Rs. 6,74,83,89,000 on account of Finance be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 7

Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. :

That Demand No. 7 of Rs. 10,61,54,76,000 on account of other Administrative Services be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 8

1. Shri Chhattar Singh Chauhan,
2. Smt. Janki Devi. and
3. Shri Karan Singh Dalal, M.L.As. } :

That Demand No. 8 of Rs. 1,67,98,12,000 on account of Buildings & Roads be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 9

1. Shri Ram Bhajan,
2. Shrimati Janki Devi,
3. Shri Chhattar Singh Chauhan, and
4. Shri Attar Singh, M.L.As } :

That Demand No. 9 of Rs. 5,05,93,63,000 on account of Education be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 10

Shri Om Parkash Beri, M.L.A. :

That Demand No. 10 of Rs. 3,75,47,69,000 on account of Medical & Public Health be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 11

Shri Ram Bhajan, M.L.A. :

That Demand No. 11 of Rs. 13,86,18,000 on account of Under Development be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 15

Shri Om Parkash Beri, M.L.A. :

That Demand No. 15 of Rs. 9,96,15,50,000 on account of Irrigation Department be reduced by Re. 1/-.

1. Shri Bansi Lal,
2. Shri Karan Singh Dalal, and
3. Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. } :

That Demand No. 15 of Rs. 11,30,58,05,000 on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 16

1. Shri Ram Bhajan, M.L.A. :

That Demand No. 16 of Rs. 41,07,79,000 on account of Industries be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 17

1. Shri Bansi Lal,
2. Shri Karan Singh Dalal, and
3. Shri Om Parkash Beri, M.L.As. } :

That Demand No. 17 of Rs. 1,21,78,97,000 on account of Agriculture be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 22

1. Shri Chhattar Singh Chauhan,
2. Shri Karan Singh Dalal, M.L.As. } :

That Demand No. 22 of Rs. 22,55,73,000 on account of Cooperation Department be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 24

Shri Bansi Lal, M.L.A. :

That Demand No. 24 of Rs. 8,13,66,86,000 on account of Tourism be reduced by Re. 1/-.

Now, discussion will take place. Shri Lehri Singh will speak on these demands first.

श्री सतबीर सिंह का बयान : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दें ।

श्री अध्यक्ष : अब तक जो बोल चुके हैं उनका पार्टीवाइज टाईम इस प्रकार है—

इंडियन नेशनल कांग्रेस 333 मिनट, एस0 जे0 पी0 210 मिनट, हरियाणा विकास पार्टी 125 मिनट, बी0 जे0 पी0 61 मिनट और बी0एस0पी0 3 मिनट 1 अपोजीशन पार्टीज के सदस्य टोटल 399 मिनट बोले हैं और कांग्रेस के 333 मिनट ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, हम इंडिपैंडेंट्स समेत 65 सदस्य हैं, इसलिए हमें दो तिहाई के लगभग समय मिलना चाहिए ।

साथी लहरी सिंह (रादौर, अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । मैं डिमांड नं0 1, 3, 17, 18 और 22 पर बोलना चाहता हूं । सब से पहले मैं विधान सभा के बारे में थोड़ा सा सुझाव दूंगा । स्पीकर साहब, मैं टेलीफोन के बारे में कहना चाहता था । टैलीफोन का सिस्टम बहुत खराब है ।

श्री अध्यक्ष : वह आप अलग से पूछ लें ।

साथी लहरी सिंह : ठीक है जी । स्पीकर साहब, हमारे जमनानगर जिले में पुलिस पूरी इफैक्टिव है और अच्छा काम कर रही है लेकिन अगर साथ के इलाके में कोई घटना हो जाए तो पुलिस इफैक्टिव नहीं होती । **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, जमनानगर जिले के साथ यू0पी0 का इलाका लगता है । वहां पर बहुत बुरा हाल है । जमनानगर का इलाका जो यू0पी0 के साथ लगता है, वहां के डाकू आ कर हमारे किसानों को उजाड़ देते हैं । यू0पी0 के डाकू हमला करके चले जाते हैं, किसी को मार कर चले जाते हैं और किसी को घायल करके चले जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह एडमिनिस्ट्रेशन की बात है इसलिए मेरा निवेदन है कि जमनानगर इलाके को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलना चाहिए । जैसे पुलिस डिपार्टमैंट है, इसको मुकाबला करने के लिए अच्छे साधन दिए जाने चाहिएं ताकि डाकू हमला न कर सकें, लेकिन पुलिस के पास अच्छे साधन नहीं है । जमनानगर जिले के एस0पी0 और डी0सी0 साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन पुलिस के पास अच्छे साधन नहीं हैं, जिसके कारण यू0पी0 के डाकू हमारे लोगों पर हमला करके चले जाते हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि पुलिस को अच्छे साधनों का इन्तजाम करवाएं ताकि पुलिस उन गुण्डों का मुकाबला कर सके । उन गुण्डों को यू0पी0 की एडमिनिस्ट्रेशन शह देती है, प्रोटैक्शन देती है, जिसके कारण हरियाणा के इलाके के लोगों का मनोबल डाउन होता है । इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, जमना नदी पर जो ठोकरें लगाई हुई हैं, वे हमारी तरफ 65 फुट की हैं लेकिन यू0पी0 वालों

ने अपनी तरफ 125 फुट की ठोकरें लगाई हुई हैं जिसका सीधा असर हमारे इलाके पर पड़ता है। यू0पी0 वाले जमना नदी को हमारी तरफ से काटने पर लगे हुए हैं। उन्होंने 125 फुट लम्बी ठोकरें लगाई हुई हैं जिसके कारण हमारे इलाके की उपजाऊ जमीन पानी के बहाव के कारण कट जाती है। ऐसे हालात हैं कि हमारे इस इलाके के कई गांव बहने के कगार पर हैं। यू0पी0 वालों ने 125 फुट लम्बी ठोकरें लगाई हुई हैं, परिणामस्वरूप हमारी काफी जमीन कट कट कर यू0पी0 की तरफ चली गई है। सरकार से मेरा निवेदन है कि हरियाणा सरकार सैंट्रल गवर्नमैंट से बात करें और अनुरोध करे कि 65 फुट लम्बी ठोकरें लगाने का जो स्पैसीफिकेशन है, उसके हिसाब से ही ठोकरें लगानी चाहिएं। हमारी सरकार को यह केस केन्द्रीय सरकार में प्लीड करना चाहिए ताकि हमारे इलाके की जमीन, हमारे इलाके के गांव बचाए जा सकें। कई गांव तो इस समय बहने के कगार पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह मुद्दा पहले भी उठाया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का बड़ा आभारी हूं कि सरकार ने वहां पर स्टेट हाईवे, एक्सप्रैस हाईवे मंजूर किया है। वह सड़क जमनानगर से दिल्ली जाएगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर यू0पी0 के जो गुण्डे हमारे इलाके के लोगों पर हमला करके चले जाते हैं, किसी को मार जाते हैं और किसी को घायल करके चले जाते हैं, उनके बारे में कोई न कोई इन्तजाम किया जाए वरना न सड़क रहेगी और न आबादी रहेगी। जमीन तो कट कट कर पहले ही जा चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा है जिसके बारे में सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि कोई जुगाड़ नाम का व्हीकल आज सड़कों पर बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहा है। न उसके ऊपर कोई नम्बर लिखा हुआ है और न ही कोई और बात है। अगर उनसे पूछें तो कहते हैं कि यह धक्का ट्रांसपोर्ट है। हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब, मेरी इस बात पर हंस रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं के इलाके में यह व्हीकल चल रहा है। अगर यह व्हीकल किसी का एक्सीडैंट करके चला जाए या किसी को मार कर चला जाए तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर कोई नम्बर नहीं लिखा है। यदि उसके पीछे कोई नम्बर वाली व्हीकल आ रही होती है तो एक्सीडैंट के मामले में उसका नम्बर नोट कर लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है लेकिन अगर किसी आदमी को जुगाड़ व्हीकल एक्सीडैंट करके मार जाता है और जो नम्बर वाली गाड़ी उसके पीछे आ रही होती है, उसका नम्बर नोट कर लिया जाता है तो यह बड़ी भारी त्रुटि है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लैवल की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की बात हो, इनको तुरन्त बन्द किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी नीयत अच्छी होती है, उसको परमात्मा भी देखता है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने और एग्रीकल्चर मन्त्री महोदय ने जो अपनी साफ नीयत से काम किया है, उसकी बदौलत हमारे यहां अनाज की रिकार्ड तोड़ पैदावार हुई है।

[साथी सहरी सिंह]

पहले पंजाब में सबसे ज्यादा पैदावार होती थी । मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे एग्रीकल्चर विभाग की, सरकार की नीयत साफ होने की वजह से यहां पर फसल का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ और कुरुक्षेत्र जिला सारे देश में गेहूं की पैदावार में सबसे प्रथम रहा । इनकी नीयत अच्छी थी इसलिए भगवान भी मेहरबान रहे और समय पर बारिश हुई । एक समय था जब इनकी सरकार आई तो उस समय एक बार तो सूखा पड़ गया और दूसरी बार बाढ़ में सारी फसल तबाह हो गई । इसलिए यह नीयत की बात होती है । एग्रीकल्चर विभाग का कामकाज का तरीका बहुत अच्छा है इसलिए मेरा निवेदन है कि यह महकमा बागवानी और फ्रूट की पैदावार की तरफ भी ज्यादा ध्यान दे ताकि किसानों को अपनी फसल का अधिक से अधिक रेट मिल सके । हरियाणा सरकार ने हर फसल का सारे देश से अच्छा भाव अपने किसानों को दिया है । गन्ने के आगामी सीजन के लिए अभी से हमारी सरकार ने 5 रुपए रेट बढ़ा दिए हैं और जब सीजन आयेगा तो और बढ़ा दिए जाएंगे । इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं । हमारे डांगी साहब की बतौर मन्त्री परफोरमैंस बहुत अच्छी रही है । इन्होंने बताया कि इतना बजट मांगा था लेकिन मांगे राम गुप्ता जी ने इतना पैसा दिया, इसलिए अब कसूर इनका न रह कर, मांगेराम जी का रह जाता है । इसलिए मेरी मांगे राम जी से प्रार्थना है कि वे जितना पैसा सड़कों की रिपेयर के लिए मांगते हैं, वह दे दिया जाये ताकि सारी सड़कों की मुरम्मत हो सके । इन्होंने बताया कि इनको हर साल 70 करोड़ रुपये चाहिएं जबकि 18 करोड़ से ज्यादा गुप्ता जी नहीं दे रहे । इन 18 करोड़ रुपये में उपाध्यक्ष महोदय, आपके और हमारे जिले का नम्बर तो आता नहीं । इनको जितना पैसा मिलता है, उस से इनके रोहतक जिले की ही सड़कें पूरी हो पाती हैं । इसलिए मेरी गुप्ता जी से प्रार्थना है कि जितना पैसा डांगी साहब को काम करने के लिए चाहिए, वह पैसा गुप्ता जी इनको दे दें ताकि सारी सड़कों की रिपेयर हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं । हरियाणा सरकार को वर्ल्ड बैंक से 800 करोड़ रुपये मिल गए हैं । इनमें से मेरी मांग है कि 65 करोड़ रुपये तो दादूपुर नलवी नहर के लिए और 100 करोड़ रुपये दादूपुर नाडवा के लिए दे दिए जाएं । यदि हमें 165 करोड़ रुपये मिल जाएं तो ये नहरें पूरी हो सकेंगी । इनके पूरा होने पर हमारे इलाके की पानी की जरुरत भी पूरी हो सकेगी और वाटर लैवल जो बहुत नीचे जा चुका है, वह भी ऊपर आ जायेगा । 16.00 बजे | उपाध्यक्ष महोदय, मैं डांगी साहब का धन्यवादी हूं क्योंकि हर गांव में जा कर वे कोशिश करते हैं कि वहां पर सड़क का काम हो जाए । (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं। (विघ्न एवं घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : लहरी साहब; अब आप वाइंड अप करिये।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी थोड़ा समय और दीजिए। बहिन जी अभी बैठी नहीं हैं। जिस हिसाब से बहन जी काम कर रही हैं।..... (विघ्न) पिछली सरकार ने और इस सरकार ने जो भी डिस्पैंसरीज और प्राईमरी हैल्थ सैंटरज बनाए हैं, उनकी देख रेख में काफी कमी है। न वहां पर पूरी दवाइयां मिलती हैं और न पूरी बिल्डिगज ही हैं। मेरे हल्के में 2 प्राईमरी हैल्थ सैंटरज हैं और वे दोनों ही पंचायतों की बिल्डिगज में चल रहे हैं। सबसिडियरी हैल्थ सैंटरज भी बिना बिल्डिंग के ही चलाए जा रहे हैं और वहां पर कोई कम्पाउंडर या डाक्टर नहीं मिलता। इसके साथ ही जहां पर एक्स-रे प्लांटस लगे हुए हैं, वहां टैक्नीशियन भी मिलने चाहिएं। बहिन जी इस वक्त बैठी नहीं है, मेरा नम्र निवेदन है कि इस ढंग से काम करना चाहिए जिससे सभी को सुविधा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जो 13 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं, उनमें डिप्टी स्पीकर साहब, न तो आपके हल्के का कोई स्कूल अपग्रेड किया है और न ही मेरे हल्के का कोई स्कूल अपग्रेड किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि 1981-82 के बाद से मेरे हल्के का कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया है और न ही कोई नई सड़क उस हल्के में बनाई गई है। मैं डांगी साहब से नम्र निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के में सड़कों की हालत की तरफ जरूर ध्यान दें। सारे हल्कों में बराबर का काम होना चाहिए, बराबर के स्कूल अपग्रेड होने चाहिएं। (घण्टी) मेरा हल्का 15-20 साल से पिछड़ा पड़ा है, उसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक पुल टूट गया था और दो आदमी भी मर गए थे। उस पुल के टूटने से 100 गांवों का रास्ता बन्द हो गया है। वह पुल घनौरा, डब्ल्यू0जे0सी0 पर बनना है और इरिगेशन डिपार्टमैंट ने बनाना है। इस पुल के बनने से 100 गांवों के किसानों का फायदा होगा, लेकिन न बनने से बहुत नुक्सान हो रहा है। (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इससे सब को बराबर सुविधा मिलनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी क्वैश्चन रेज किया था, जो भी ग्रान्ट्स हैं, वे रोहतक, सिरसा, हिसार आदि जिलों में दी जाती हैं। मेरा फाईनैंस मिनिस्टर साहब से नम्र निवेदन है कि ग्रान्टस सभी जिलों में बराबर बांटी जानी चाहिएं। हमारे इलाके में भी गरीब लोग रहते हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, एक क्वैश्चन के जवाब में

[साथी लहरी सिंह]

मुख्य मन्त्री जी ने एनाउंसमैंट कर दी थी कि जो हरिजन चौपालें हैं, वे 31 मार्च, 1995 तक कम्पलीट कर दी जाएंगी । यह कोई छोटा फैसला नहीं है, इस पर 100-150 करोड़ रुपये के लगभग खर्च करना पड़ेगा । आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने हाउस के बाहर भी 4-5 बार एलाउंस किया है कि इन चौपालों का कार्य कम्पलीट हो जाएगा । 70-75 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां चौपालों की मुरम्मत होनी है । (बण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी ही देर में अपनी बात को समाप्त करूंगा । अब मैं इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं । चौटाला साहब, इस समय हाउस में बैठे नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियलिस्टस पलायन कर रहे हैं, वे हरियाणा से जा रहे हैं । मैं चौटाला साहब को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब ये इंडस्ट्रियलिस्टस हरियाणा से उद्योग उठा कर बाहर नहीं जा रहे हैं वे तो चौटाला साहब से डर कर चले गए थे । जब इंडस्ट्रियलिस्टस को यह पता चलता था कि चौटाला साहब आ रहे हैं तो जगाधरी और यमुनानगर के उद्योग बन्द हो जाया करते थे और बहुत से उद्योग हरियाणा से बाहर भी चले गए । इसी तरह से फरीदाबाद में है । अब सरकार की पौलिसी है कि दूसरे देशों से इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर आकर इण्डस्ट्री लगाएं और अब तक कम से कम 100 इंडस्ट्रियलिस्ट आ चुके हैं और इण्डस्ट्री लगा चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : लहरी सिंह जी, आप वाइन्ड-अप कीजिए ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है । अभी माननीय सदस्य ने श्री ओम प्रकाश चौटाला का नाम लिया है । जब वे सदन में हों नहीं हैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए । वे तो अभी-अभी खरीदे गए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कादयान साहब, को अपनी वह बात याद आ रही है जिसमें ये पांच करोड़ के चपले में फंस गए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : लहरी सिंह जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं क्योंकि कादयान साहब कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पांच करोड़ वाली बात कही, वह ठीक नहीं है । मैं जब तक इफको का चेयरमैन रहा हूं, उसको प्रोफिट ही हुआ है । अगर कोई इफको का एक रुपया भी बचा हुआ था तो वह मेरे टाईम में वापिस आ गया था । एक साल तो 101 करोड़ रुपए का प्रोफिट हुआ था ।

श्री राम कुमार कटवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । उपाध्यक्ष महोदय, छाज तो बोले, ये छलनी क्यों बोले है ? अभी बंसी लाल जी

नहीं बैठे हैं । इन्हें अभी दो साल ही हुए हैं और इन्होंने दो साल में पैट्रोल पम्प खोल दिया है ।

Mr. Deputy Speaker : This is not a point of order.

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह पैट्रोल पम्प एक हरिजन को, एक गरीब आदमी को दिया गया है ताकि वह काम करके खा सके । उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन मुझे पैट्रोल पम्प मिला है, उसी दिन चौधरी बंसी लाल के बेटे को भी पैट्रोल पम्प मिला है । यह मुख्य मन्त्री जी के हाथ में नहीं है कि जिसको चाहा पैट्रोल पम्प दे दो और न ही किसी और के हाथ में है । आज इनको तकलीफ होती है । (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खत्म करता हूं ।

Mr. Deputy Speaker : You are stressing too much.

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बिजली के पावर हाऊस इन्होंने अपग्रेड करके 66 के०वी० के किए हैं, वे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं । जैसे गुड़ा और पृथला के पावर हाउसिज हैं, इनको चालू किया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Please wind up.

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म ही कर रहा हूं । इसी तरह से जो हकशफा का कानून है, वह ठीक हो गया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं लेकिन उसमें एक प्रोब्लम रह गई है, उसको भी दूर कर दें । प्रोब्लम यह है कि जो हिस्सेदारी है उस बारे में पुनर्विचार किया जाए ।

इसी तरह से मैं पंचायती राज के बारे में कहना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कारपोरेशन के चेयरमैन के बारे में कह दिया, साथ ही यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर का लड़का अपने आपको सी०एम० लिखता है । (विघ्न) मेरा इस बारे में निवेदन है कि भगवान ऐसी औलाद सबको दे ।

श्री जिले सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, ये किस विषय पर बोल रहे हैं ?

साथी लहरी सिंह : सर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर बोल रहा हूं । मेरा तो कहना यह है कि परमात्मा ऐसी औलाद सबको दे क्योंकि उसके हाथ में इतनी पावर होते हुए भी घर-घर जाकर लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि हम आपसे मिलने आये हैं । ऐसा नहीं है इनकी तरह कि किसी की बहू का कत्ल करवा दे या किसी और का कत्ल करवा दे । वह ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी का हाथ उठ गया तो उसका हाथ कटवा दे जैसा कि ये करवाया करते थे । उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं । (विघ्न)

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का टाईम दें । सर, मुझे टैंशन हो रही है कि मेरा बोलने का नम्बर आएगा या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : कादयान साहब, आप टैंशन न रखिए । आपको बोलने का समय दिया जाएगा । पहले जानकी देवी मान को बोल लेने दें ।

श्रीमती जानकी देवी मान (इन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी के सामने अपने हल्के की कुछ कठिनाईयों के बारे में कहना चाहती हूं लेकिन कहें किससे, मुख्य मन्त्री जी तो उठकर चले गए । मैंने उनसे कई बार कहा कि मेरे हल्के के काम करवायें लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं ।

श्रीमती जानकी देवी मान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अन्दर न स्कूल हैं, न कालेज हैं । मेरे हल्के के अन्दर लड़कियों के पढ़ने के लिए 10+2 का कोई स्कूल नहीं है, साथ ही लड़कियों को स्कूल ले जाने के लिए कोई बस सर्विस का भी प्रबन्ध नहीं है । मेरा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि वे मेरे हल्के के अन्दर 10+2 का स्कूल और कालेज खुलवाएं ताकि लड़कियां पढ़ सकें । ये तो खुद कहते हैं कि वे स्त्रियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं पर हो कुछ भी नहीं रहा है । इनकी सब बातें कहने की ही हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जब तक देश और प्रदेश के अन्दर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तब तक इनका भविष्य ठीक नहीं हो सकता । अगर मां पढ़ी लिखी होगी, तभी वह घर का काम काज ठीक ढंग से कर सकेगी । इसलिए मुख्य मन्त्री जी को मेरे हल्के के अन्दर स्कूल और कालेज खुलवाने चाहिएं । इसके अलावा स्कूल में टीचर्ज भी नहीं हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें जे0बी0टी0 टीचर या अन्य टीचर नहीं हैं, इसलिए आपको नये बच्चों की भर्ती करके टीचर्ज लगाने चाहिएं । इसके अलावा, मेरे हल्के में स्कूलों की छतें भी टूटी पड़ी हैं । सरकार को बरसात से पहले पहले छतें ठीक करवानी चाहिएं ताकि मासूम बच्चे मरने से बच जाएं । मेरे हल्के की सड़कें भी टूटी पड़ी हैं और एक धनौरा जागीर का पुल टूटा पड़ा है जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसलें ले जाने में बड़ी दिक्कत होती हैं । इसलिए सरकार को जल्दी ही सड़कें और पुलों की मरम्मत करवानी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, इन्द्री हल्के के साथ साथ बहुत से गांव जमुना से लगते हैं । जब बरसात में पानी आता है तो जमुना के बहाव से गरीब किसानों की जमीन कट जाती है । इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि बरसात आने से पहले ही वहां पर ठोकरें लगाएं ताकि गरीब किसानों की जमीन बच सके । इसी तरह से बिजली की भी प्रदेश के अन्दर बहुत जरूरत है । इसके साथ ही साथ मैं नेहरा साहब से भी निवेदन करूंगी कि वे नहरों की गाद निकलवाएं । पिछले तीन साल से नहरों पर काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या बात है ? जब इनको सच बात कहते हैं तो ये कहते हैं

कि यह बात क्यों कही है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेती हूं । धन्यवाद ।

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौलथा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है......

श्री उपाध्यक्ष : समय के मामले में जो मिसाल बहिन जी ने कायम की है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सदस्य उसे कायम रखेंगे ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो डिमांड बढ़ा-चढ़ाकर सदन में पेश की हैं, उसमें जो खर्च हैं, वे वास्तविकता से दूर हैं, ज्यादा खर्च तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हैं और फिक्सड ऐक्सपैंडीचर हैं । विकास के लिए बजट में उतना प्रावधान नहीं किया जितना होना चाहिए । राष्ट्रीय मुद्रा स्फीति के हिसाब से ही बजट में दो तीन साल से वृद्धि हो रही है । ऐक्साइज से और सेल्ज टैक्स से जो आमदनी बताई है, वह दस परसैंट होगी । कुछ वृद्धि तो इसलिए कम रह जाती है कि वित्त मन्त्री जी हर महकमे को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते । एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रकृति पर निर्भर करती है । फसल अगर ज्यादा हो जाती है तो सेल्ज टैक्स ज्यादा आ जाता है और जो टैक्स उगाहे जाते हैं, जिनसे प्रदेश का विकास हो सकता है, उस पर सरकार का पूरा ध्यान नहीं रहता । 1977 में चौधरी देवी लाल जी ने मैचिंग ग्रांट्स स्कीम चलाई थी जिसके तहत स्कूल, कालेज, हरिजन चौपाल और गांव की गलियों के लिए दुगुना पैसा किया करती थी और लड़कियों की शिक्षा के लिए तिगुना किया करती थी । मैं मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 27-3-91 को इन्होंने इसराना में एक कालेज बनाने का फैसला लिया था । गांव के लोगों ने 5 लाख 40 हजार रुपए जमा कर रखे थे लेकिन हमारी सरकार आठ दिन के बाद नहीं रही थी, उसके बाद गुप्ता जी की सरकार आ गई । विकास के नाम से लोगों के पैसे जो बैंकों में जमा हैं, उन संस्थानों को न उसका ब्याज मिलता है न मैचिंग ग्रांट देकर दुगुना मिलता है । जब किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है तो उनको पैसे दिये जाने चाहिएं लेकिन सरकार उनको एक्सप्लाइट करती है । न तो किसान को उनकी जमीन का पैसा देती है और न ही विकास का काम हो रहा है । ऐसी योजनाएं बनाई जाएं कि छह महीने के अन्दर अन्दर एक्वायर जमीन की पेमैंट किसान को की जाए । नक्शे आदि तैयार हों, ज्यादा से ज्यादा काम 6 महीने के अन्दर कर दिया जाए । सरकार जिन किसानों की जमीन एक्वायर करती है, उनको नौकरी दी जाए क्योंकि उनके पास आजीविका के दूसरे साधन नहीं होते ।

मैं डिमांड नं० 16, 17, 9, 22, 2, 6 और 3 के ऊपर ज्यादा बोलना चाहूंगा । डिमांड नं० 16 इंडस्ट्री के बारे में है । सरकार बलेगबाग दावे करके हरियाणा की

[श्री सतबीर सिंह कादयान]

जनता को गुमराह करती है कि एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे । कारखाने इतने ज्यादा लगाएंगे कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा । इन दावों से जनता झांसे में आ गई । हमारी सरकार 50 रुपये और 100 रुपये महीना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती थी । इसके अलावा उनको मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी देती थी । मैं प्रदेश के मुख्य मन्त्री को यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर जो आजकल उद्योग लग रहे हैं, वे चाहे एन0आर0आई0 स्कीम के तहत लग रहे हैं, चाहे प्रदेश से बाहर के आदमी लगा रहे हैं या हमारे प्रदेश के अन्दर रहने वाले लगा रहे हैं, वह बाहर के आदमी ही रखते हैं । हमारे पानीपत में एक नैसले की फैक्ट्री लगी है । इसी तरह से एक पैप्सी कोला वालों ने फैक्ट्री लगाई है । वहां पर क्लास-थ्री और क्लास-फोर के सभी कर्मचारी बाहर के लिये हैं । प्रदूषण तो हरियाणा में हो, धुआं फैक्ट्रीज का हम खायें, लेकिन हमारे प्रदेश के आदमी भी इनमें नौकरी में न लिये जायें, यह देखने योग्य बात है । इस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश में कार्यान्वित हो रही हैं । इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने के लिये इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट द्वारा, एच0एफ0सी0 द्वारा और दूसरे अदायरों द्वारा जो धन दिया जाना है, उसको एक्सपीडाईट करना चाहिये । इसके अलावा, जैसे कि आपको पता ही है किस तरह से खानों की बात हो रही है । हरियाणा का एक माईन्ज एण्ड मिनरल्ज का महकमा है । 1986 में जब चौधरी भजन लाल मुख्य मन्त्री थे तब उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो इनके नजदीकी हैं या करीब हैं, उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिये सरकार की जो चट्टानें हैं या खाने हैं, जैसे स्लेट की खानें हैं या और कोई चीज निकलती है, वह उनको दे दी जाये । इनका यह फैसला था ताकि ये खानें इनके अपने चहेतों को दी जा सकें । उसके बाद चौधरी बंसी लाल 1986 में मुख्य मन्त्री बने । इन्होंने इस काम के लिये एक कारपोरेशन बनाई जिसका नाम था एच0एम0एल0 । यह कारपोरेशन काम करती रही । बाद में जब हमारी पार्टी की सरकार बनी और चौधरी देवी लाल जी आये तो हमने यह किया कि पहले इस एच0एम0एल0 से नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट दिया जायेगा, तब किसी दूसरे को लीज पर देंगे । लेकिन जब 1991 में दोबारा चौधरी भजन लाल जी सत्ता में आये तो इन्होंने अपने चहेतों को और अपने परिवार के लोगों को यह जमीन लीज पर देनी शुरू कर दी ।

चौधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । डिप्टी स्पीकर सर, इस ढंग से यें जो वेग एलीगेशन्ज लगा रहे हैं, यह पार्लियामैंट्री परम्परा के मुताबिक बिल्कुल भी ठीक नहीं है । मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि इस ढंग से एलीगेशन्ज न लगायें, इनका इन डिमांडज से कोई संबंध नहीं है । यह जो खानें दी जा रही हैं, उनके लिये बाकायदा एक प्रोसीजर बना हुआ है । उस प्रोसीजर के तहत खानें दी जा रही हैं । ऐसे नहीं कि ऐसे ही मन मर्जी से जिस को चाहो

दे दी जायें । इसके लिये केन्द्र सरकार की कनकरैंस भी लेनी पड़ती है । इसलिये इस ढंग से ऐसे ही एलीगेशन्ज लगाना कि यह अपने परिवारों को दी जा रही हैं, यह ठीक नहीं है । इनके राज में जो कार्यवाही इस बारे में इन्होंने की थी, वह भी लोगों को पता है । आप लोगों ने जो खानें दी थीं, उनका क्या हाल था, क्या वह ये भूल गये ? सारी जगहों पर, इन्होंने भी तो अपने ही रिश्तेदारों के अलावा, किसी और को खानें नहीं दी थीं । किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गयीं, यह सब को पता है ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको लीज के बारे में बता रहा था कि इन्होंने अपने चहेतों को लीज पर दी है । रोजका-गुजर में, सिलिका-सैंड की लीज, हरियाणा मिनरल्ज से सरैंडर करवाकर, शिवजीत सिंह व उग्रसैन को दी गयी है । उग्रसैन मुख्य मन्त्री जी के साले का लड़का है । इसके साथ ही अनंगपुर-कटन व सराय ख्वाजा की सिलिका-सैंड की लीज, कैलाश आहूजा को दे दी गयी है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । डिप्टी स्पीकर साहब, ये मिस्टर आहूजा का नाम ले रहे हैं, क्या यह भी रिश्तेदार है ? (व्यवधान व शोर) इस ढंग से एलीगेशन लगाना और नाम लेना क्या ठीक है ?

श्री सतबीर सिंह कादयान : मैं यह कह रहा था कि इसी तरह से अनंगपुर-कटन व सराय ख्वाजा की सिलिका-सैंड की लीज कैलाश आहूजा को दी गयी है । एक पाली, जिला फरीदाबाद की सिलिका सैंड की दो खानें, शीशपाल सिंह सुपुत्र श्री कर्मवीर सिंह वगैरह को दी गयी हैं । एक गंगानी, जिला गुड़गांव की सिलिका-सैंड की लीज एस0ए0 मिनरल्ज, करोलबाग, नई दिल्ली को दी गयी । इसमें कैलाश आहूजा के अलावा दूसरे व्यक्तियों की साझेदारी भी है । एक रविन्द्र कुमार पुत्र श्री अमीर चन्द मक्कड़, एम0एल0ए0 हांसी को, खरक-सोहना (गुड़गांव) की सिलिका सैंड की लीज दी गयी है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । इस ढंग से एलीगेशन लगाना जिस तरह से यह कर रहे हैं, उचित नहीं है । एम0एल0ए0 का नाम लेकर यह एलीगेशन न लगायें तो ठीक रहेगा । जैसे कर्ण सिंह दलाल जी ने धनिक लाल मंडल जी का नाम लेकर एलीगेशन लगाया, वह भी ठीक नहीं था । क्या यह सब इनके रिश्तेदार हैं या इनके कहने से रिश्तेदार बन जाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठ जाइए । आप एक मिनट मेरी बात सुन लें । आप किसी ऐसे आदमी का नाम न लें जो अपने आपको हाउस में डिफेन्ड न कर सकता हो । (शोर एवं व्यवधान) चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठिए ।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर । उपाध्यक्ष महोदय, इनका मकसद तो कभी ठीक बात कहने का नहीं है । कोई एम0ऐल0ए0 हो, कोई एम0पी0 हो और उसका कोई रिश्तेदार हो काम कर सकता है । काम करना कोई गुनाह तो नहीं है ? चोरी करना, डकैती करना और हेराफेरी करना तो बुरी बात है लेकिन अगर कोई आदमी कानून के हिसाब से सही काम करता है, मर्यादा में रहकर काम करता है तो इसमें क्या हर्ज है ? पहले इन माइन्ज से नौ करोड़ की इन्कम थी और आज के दिन सोलह करोड़ की इन्कम है । बाकायदा ऐप्लीकेशनज मांगी जाती हैं, इंटरव्यू होता है, तब माइन्ज दी जाती हैं । अगर मक्कड़ के लड़के ने ले ली है तो इसमें गुनाह की क्या बात है ? कोई गल्त तरीके से ली हो तो यह कह सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इनके खिलाफ सी0बी0आई0 ने करप्शन का केस दर्ज किया हुआ है और इंक्वायरी भी हुई है । अगर मैं आपका चिट्ठा खोलने लगूं तो आपको सारी बातों का पता लग जाएगा ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, इफको का एक पैसा भी बकाया नहीं है, सारा पैसा वापिस आ गया है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब आप सेन्टर में कृषि मन्त्री थे तो उस वक्त के मेरे पास ऐसे सबूत हैं । एक-एक ट्रक में आठ-आठ नौ-नौ किलो वजन था और पूरे ट्रक के वजन का क्लेम किया गया था । उपाध्यक्ष महोदय, मवन्डी (बम्बई) से आंवला इफको प्लांट बरेली में था और इकोनोमिक ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन कम्पनी, ट्रांसपोर्टेशन की ठेकेदार थी । इस केस में सी0बी0आई0 की इंक्वायरी भी चल रही थी । उन ट्रकों में आठ-आठ और नौ-नौ किलो वजन होता था लेकिन पूरे ट्रक का किराया लिया गया था ।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी कोई प्लांट लगाता है और वह प्राईवेट आदमी है तो यहां पर इस बात को कहने का क्या तात्लुक है ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बाद चौधरी देवी लाल आए, बंसी लाल आए, अगर इनको कोई कमी नजर आई थी तो ये ऐक्शन ले सकते थे और मेरे खिलाफ चौधरी देवीलाल को केस दायर करना चाहिए था । हम कोई फिजूल की बात नहीं करते, मर्यादा में रहकर काम करते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री सतवीर सिंह कादियान ने कहा कि हां उस के नेता जब दिल्ली की सरकार में कृषि मन्त्री थे तो उस समय ऐसे ट्रक आए जिनमें नौ किलो वजन डाला गया और पूरे ट्रक का किराया लिया गया । आप उस समय कृषि मन्त्री थे और आपका नाम इसमें आ सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल ने कहा है कि जब श्री कादियान इफको के चेयरमैन थे, तो उस वक्त काफी गल्त काम हुए लेकिन श्री कादियान ने कहा है कि मेरे खिलाफ कहीं कोई लेनदेन का मामला नहीं है । मुख्य मन्त्री के ऊपर एक दीवारोरेण

लगाया जा रहा है तो आप अपने आपको उस बात से अलग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई माल नहीं आया और अगर आया है तो आप बात को साफ करें ।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बकायदा सी0 बी0 आई0 की इंक्वायरी हुई थी और इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, ये तो फिजूल की बात करते हैं? इनकी बात में कोई सदाकत नहीं है ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : अगर आप चाहें तो मैं आपको ट्रक नम्बर दे सकता हूं जिनमें अठ-नौ किलो वजन आया और पूरे ट्रक का किराया चार्ज किया गया ।

चौधरी जगदीश नेहरा : आप नम्बर दे दीजिए । हम भागने वाले नहीं हैं । ट्रक के नम्बर देने से क्या होता है? हम भी ट्रक के नम्बर दे सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैम्बर साहब डिमाण्ड पर बोलें, हम बिल्कुल भी दखलअन्दाजी नहीं करेंगे । आप इस तरह से बात करें जिससे हाउस की गरिमा को कोई आंच न आए ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडस्ट्रीज की डिमांड नम्बर 16 पर बोल रहा था कि किस तरह से प्रदेश की इंडस्ट्रीज को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है । जब तक प्रदेश के जो साधन हैं उनको सही ढंग से यूटीलाईज न किया जाए तब तक हमारे प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रीज नहीं पनप सकती । मैं आपको इस सरकार के कारनामों के बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरह से यह सरकार अपना कार्य कर रही है जो बड़ा ही आपत्तिजनक है ? इन्होंने अब्दुल रजाक पुत्र गुलाम रसूल गांव पड़ाणी जिला गुड़गावां को सौन्ध की चाईन-क्ले की लीज चौधरी तैयब हुसैन के दामाद को फायदा पहुंचाने के लिये दे दी । (शोर) इसी तरह से सुरेन्द्र पुत्र राम रत्न एम0 एल0 ए0 को स्लेट की लीज कौड़ियों के भाव दे दी । 700 एकड़ भूमि उसको केवल 10 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे दी गई । (शोर एवं व्यवधान) किस तरह से इस सरकार ने लोगों के साथ भेदभाव किया है । (शोर) अच्छा, उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा इंडस्ट्रीज पर न कहता हुआ, ऐजुकेशन पर बोलूंगा क्योंकि अगर मैं और कुछ बातें इंडस्ट्रीज के बारे कह दूंगा तो इस सरकार को तकलीफ होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ऐजुकेशन का संबंध है, इसके लिये वित्त मन्त्री ने अपने बजट में बहुत कम पैसा रखा है । जब हमारी सरकार थी, उस वक्त सिर्फ एक साल के अन्दर ही 350 स्कूलों को अपग्रेड किया गया था और इस मौजूदा सरकार ने चार सालों में केवल 313 स्कूलों को ही अपग्रेड किया है । (शोर)

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में तो केवल घोषणाएं ही घोषणाएं थीं, स्कूल एक भी अप-ग्रेड नहीं किया गया था। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : कादयान साहब, अब आप समाप्त करें। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं। अभी मक्कड़ साहब ने बोलते हुए कहा कि केवल घोषणाएं ही घोषणाएं हमारे वक्त में थीं, काम कोई नहीं किया। हमारे वक्त में ऐसी बात नहीं थी। जहां पर कोई नार्मज को पूरा करता था तो उस जगह पर स्कूल खोल दिया जाता था। आपकी सरकार की तरह हमारी सरकार किसी इलाके के साथ भेदभाव की नीति नहीं बरतती थी। आज स्कूलों की क्या हालत है, कहीं बिल्डिंग नहीं, कहीं बिल्डिंग हैं तो टीचर्ज नहीं, कोई भी काम आपकी सरकार का नार्मज के अनुसार नहीं हो रहा है। (शोर) आज की यह मौजूदा सरकार नार्मज के लिहाज से स्कूलों की अप-ग्रेडेशन नहीं कर रही है, यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं और इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राई स्पोर्टस स्कूल में नकल करवाई गयी। वहां का स्टाफ नकल करवाता रहा और बाद में लड़कों को कह दिया कि अभी नहीं लिये जाएंगे, बाद में दोबारा टैस्ट होगा। (शोर) और जो वहां के प्रिंसीपल हैं, वे कहते हैं कि पहले मुझे मुख्य मन्त्री महोदय ने नौकरी दे दी और बाद में अर्जी ली। ऐसी ऐसी, बातें इस राज में हो रही हैं। (शोर)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि वैद्य डाक्टर, पढ़ाने वाला जो होता है, वह काबिल आदमियों में से लगाया जाता है लेकिन आपकी तरह * * *

* * * * * *

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द कार्यवाही में से निकाल जाने चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ये शब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जाएं।

श्री सतबीर सिंह कादयान : राई स्पोर्टस स्कूल के अन्दर पिछले दिनों कुछ लड़कों ने गुंडागर्दी की। चार लड़कों को स्कूल से निकाला गया, फिर उन्हें दोबारा स्कूल में लिया गया। उन्होंने वहां के वाइस प्रिंसिपल की पिटाई की थी लेकिन किसी के खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 या पर्चा दर्ज नहीं हुआ। जब ऐसा हो तो पढ़ने वाले बच्चों के दिल में क्या भावना पैदा होगी ? यह बड़े सोचने का विषय है। इसी तरीके से हमारे प्रदेश के अन्दर लैंड ग्रैबिंग के तहत

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

एक संस्था बनी है, जिसका नाम 'भजन शिक्षा संस्थान' है। उसने बारह सौ एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। 415 एकड़ जमीन के तो पंचायतों से प्रस्ताव ले लिये। उसमें बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि फरीदाबाद में एक संस्था बनी है। उसे पढ़ कर मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यह पेपर में कैसे आ गई। मैंने उसी वक्त पता किया। उस बारे में किसी पंचायत ने प्रस्ताव नहीं किया और यह सब बेसलैस बात है। ये लोग जैसे खुद थे, इनको वैसा सब को नहीं समझना चाहिये। हमारे पर थोड़ी सी कृपा करो। हर एक को अपने जैसा इन्सान नहीं समझना चाहिये।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की परन्तु मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 'भजन शिक्षा संस्थान' बाकायदा रजिस्टर्ड है। उस शिक्षा संस्थान को उपहार देने के लिये 415 एकड़ जमीन के लिये प्रस्ताव पंचायतों से करवाए गए। जैसे नंगल गुजरान पंचायत से 170 एकड़, कुरैशीपुर से 40 एकड़, गढ़ी गुजरान से 70 एकड़ पाखच से 50 एकड़ मादलपुर से 40 एकड़ नेकपुर से 30 एकड़ और सरूरपुर पंचायत से 15 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपके पास वह प्रस्ताव है, तो आप उनको टेबल आफ दि हाउस पर रख दें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि एक भी पंचायत का प्रस्ताव नहीं है। जब प्रस्ताव ही नहीं है तो ये टेबल पर क्या रखेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान : चलो, हम इसकी और क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। वैसे हम कोई झूठ बात यहां पर नहीं कहना चाहते हैं, यह बात सच्ची है। इसके बाद मैं कोआप्रेशन विभाग के बारे में दो-चार सुझाव देना चाहता हूं। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, यह महकमा ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रोजगार देने में मदद कर सकता है। परन्तु जिस तरीके से हमारे संस्थान चल रहे हैं, वे प्रदेश के लिये हितकर नहीं हैं। किसी भी ऐसी संस्था की एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होनी चाहिए लेकिन यहां पर कोई मीटिंग नहीं होती। अगर इनकी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाए तो उसमें चुने प्रतिनिधि यानी डायरैक्टर्ज आएंगे और जिन लोगों ने उस संस्था में अपनी पूंजी लगाई हुई है, उनको अपने सुझाव उस मीटिंग में देने का मौका मिलेगा। लेकिन उनको वह मौका नहीं दिया जाता। मैं कनफैड के बारे में क्या कहूं। वहां पर एक ऐसा एम0डी0 लगा दिया जो एक जेब में तो टर्मीनेशन के आर्डर रखता है और दूसरी जेब में नौकरी देने के आर्डर रखता है। वाह रे तेरे ठाट क्लर्क दो चपड़ासी आठ। (शोर)

* * * *

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : यह नाम रिकार्ड न किया जाये।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, वह ऐसा एम0 डी0 है जिसको सभी जानते हैं, कोई ढिनाई नहीं कर सकता। उस एम0 डी0 के 70—70 हजार रुपए के हर महीने के बिल आते हैं। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि उसका नाम नहीं आएगा तो इस तरह से कह देते हैं कि वाह रे एम0 डी0 तेरे ठाठ कलर्क दो चपड़ासी आठ।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, अब आप बैठ जाएं। श्री पीर चन्द जी बोलेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप केवल पांच मिनट और बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं।

श्री पीर चन्द (रतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 8, 9, 10, 11, 21 और 23 पर अपने विचार प्रकट करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय मेरे रतिया हल्के में पिछले 12 साल से कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। जो पिछली सरकार आई थी, उसने बहुत हिम्मत के साथ रतिया में एक बस-स्टैंड का पत्थर रखा था। आज उस पत्थर का पता नहीं कहां पर है। उसी सरकार के आदमी उस पत्थर को वहां से उठा कर ले गए। आज चार साल हो गए, उस समय माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्य मन्त्री होते थे। उन्होंने बस स्टैंड के लिए पत्थर रखा था और उन्हीं के आदमियों ने उस पत्थर को उठा कर पता नहीं कहां पर फैंक दिया, उसका आज तक पता नहीं लगा।

प्रो0 सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। वहां पर बस स्टैंड बनाने के लिये पत्थर जरूर लगाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन बाद में यह सरकार आ गई और यह सरकार उस पत्थर और पीर चन्द दोनों को ले गई। (हंसी)

श्री पीर चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सम्पत सिंह जी खुश मिजाज आदमी हैं और वे अपनी गलती को मानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं। इन्होंने अपने चार साल के समय में हरियाणा के अन्दर विकास नाम की एक भी ईंट नहीं लगाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में इस वक्त न कोई अस्पताल है और न कोई बस-स्टैंड है। इसके अलावा मेरे हल्के में स्कूलों की भी बहुत कमी है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 21 जनवरी को वहां पर एक जलसा रखा था। उस समय हमने इनके सामने हल्के की डिमांडज रखीं थी और कहा था कि पिछले 12 साल से हमारे यहां कोई

विकास का काम नहीं हुआ है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उस समय बड़े सम्मान के साथ वहां पर 30 बैड का अस्पताल मंजूर किया और बस स्टैंड के बारे में यह फरमाया कि जिस सरकार ने उसको बनाने का पत्थर रखा था, उस पत्थर को हम बदलना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने पत्थर रखा हो, हम वह बनाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मेरे हल्के में मुख्य मन्त्री महोदय ने रतिया हल्के में एक 33 के0 वी0 पावर स्टेशन मन्जूर किया है। इसके लिए भी मैं मुख्य मन्त्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। जब ये 1979 के अन्दर मुख्य मन्त्री थे, उस समय रतिया की सिर्फ एक थाना और एक ब्लाक के नाते से जाना जाता था। लेकिन जब ये आदरणीय भजन लाल जी, मुख्य मन्त्री बने तो 1979-80 में वह पूरा शहर बन गया। इन्होंने ही उसको तहसील बनाया नई बसें लगाई। इतना ही नहीं बहुत बढ़िया अनाज मंडी भी बनाई। उस समय मैं हेफैड का चेयरमैन होता था। वहां पर 30 करोड़ रुपये की लागत से एक कम्पलैक्स बनाया गया है। अब फतेहाबाद से रतिया की तरफ जाते हैं तो दूर से ही पता लग जाता है कि यह रतिया शहर है। चौधरी भजन लाल जी ने उस समय जितने काम किए, उनके लिये मैं इनको दाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने मुख्य मन्त्री काल में सन 1980 में मेरे हल्के रतिया में एक मिसाल कायम की थी कि एक प्राईमरी स्कूल को सीधा हाई स्कूल अपग्रेड किया था। उस समय ये स्कूल के लिये 2 लाख रुपया देकर आए थे। अब जब दोबारा गए तो उसको ये 10 जमा 2 का कर आए हैं। इसी प्रकार से जाखल गांव का स्कूल अब इनकी घोषणा के मुताबिक 10 जमा 2 का हो जाएगा। इस स्कूल के 25 कमरे बहुत बढ़िया बन कर तैयार हैं। मेरे हिसाब से तो वह 10 जमा दो का स्कूल आज से चार पांच साल पहले बन जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के में एक रंगोई नाला है। इस नाले की खुदाई चौधरी सम्पत सिंह जी के राज में नहीं हो पाई जिस के कारण बाढ़ से नुक्सान होता रहता है। मैं इस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपने समय में इस नाले की खुदाई के लिये 1 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किए लेकिन एक तीन किलोमीटर का टुकड़ा छोड़ दिया। इस टुकड़े के पूरा न होने से जाखल से रतिया और फतेहाबाद से टोहाना के काफी गांव बाढ़ में डूब गए थे। अब गांवों के लोगों ने आपस में मिलकर इस तीन किलोमीटर के टुकड़े को पूरा किया है। अब इस नाले पर सब ने मिलकर एक 3 किलोमीटर लम्बा, 10 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा बांध बांध दिया है। इस काम को गांवों वालों ने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से पूरा किया। इस काम में वहां के डी0 सी0 साहब, एस0 डी0 एम0 साहब, तहसीलदार साहब, बी0 डी0 ओ0 साहब ने भी अपना-अपना योगदान दिया है। यह बांध 10 फुट चौड़ा 6 फुट ऊंचा और 3 किलोमीटर लम्बा है। अगर इस बांध को 10 फुट और चौड़ा कर दिया जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी

[श्री पीर चन्द]

(विघ्न) इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टोहाना रोड और रतनगढ़ तक पुल को अगर बना दिया जाए तो पंजाब को जाने के लिये रास्ता सीधा हो जाएगा और लोगों को सुविधा हो जाएगी। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां के जमींदार बहुत ही मेहनती हैं और उस जमीन का पानी भी मीठा है लेकिन बिजली की शॉर्टेज है। वहां पर 33 के0 वी0 का पावर हाउस बन रहा है और उम्मीद है कि इसके पूरा हो जाने से बिजली की कमी नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के रतिया में मास्टरों की बहुत कमी है, खासकर पंजाबी टीचरज की ज्यादा कमी है। यह इलाका पंजाब के साथ लगता है इसलिये पंजाबी पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। इसीलिये मैं एजुकेशन मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वहां पर ज्यादा पंजाबी मास्टरज भेजने की कोशिश करें। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी कुछ बातें कहना चाहता था लेकिन बोलने वाले और भी बहुत से साथी होंगे, उन्होंने भी अपने विचार रखने हैं। मुख्य मन्त्री जी से मेरा सभ्र निवेदन है कि जैसे पहले इन्होंने अपने शासनकाल में रतिया को चमकाया था, सारे काम पूरे किये थे, इसी तरह अब भी वे इस हल्के का पूरा ख्याल रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री राम भजन अग्रवाल (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 3, 5, 7, 11 और 16 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक डिमांड नम्बर 3 का संबंध है, वह होम डिपार्टमैंट से संबंधित है। आज सारी स्टेट के अन्दर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कानून का पालन पुलिस करवाती है परन्तु इस प्रान्त के अन्दर पुलिस का ऐसा हाल है कि लोगों को नाजायज पुलिस हिरासत में रखा जाता है, ताड़ना दी जाती है, डर और आतंक का बोलबाला है, यहां पर पुलिस लोगों को मारती-पीटती है और उत्तेजित हो कर लोग पुलिस वालों को पीट डालते हैं। जहां पुलिस और जनता में तालमेल न हो वहां पुलिस जनता को मारती पीटती है तो कहीं जनता पुलिस को मारती पीटती है, वहां पर कानून और व्यवस्था की क्या हालत होगी? उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर 5 एक्साईज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट की है। इस विषय में मैंने पहले भी कहा है कि प्रदेश से व्यापार दिन-प्रति दिन खत्म होता जा रहा है। मार्कीट फीस 3% है लेकिन नजदीक की दूसरी स्टेट्स दिल्ली और राजस्थान में मार्कीट फीस कम है इसीलिये इस स्टेट का व्यापार दूसरी स्टेट्स में जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्ज टैक्स के सरलीकरण का सवाल है, वह नहीं हुआ है। जो सैल्ज टैक्स सिस्टम है, वह तर्कसंगत नहीं है और टैक्स बहुत ही ज्यादा हैं। अगर सेल्ज टैक्स का रेट कम कर दिया जाए तो टैक्स की रिकवरी ज्यादा होगी और स्टेट रैवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। हमारे शहरों के अन्दर बाजार होते हैं और इन बाजारों में छोटे दुकानदार होते हैं, वे

अपने तख्त लगाते हैं और म्यूनिसिपिल कमेटी उनसे टैक्स लेती है। अभी मुझे पता चला है कि 1991-92 में उनसे दस पैसे पर स्केयर फुट टैक्स लिया जाता था और 1993-94 में बढ़ाकर 40 पैसे पर स्केयर फुट चार्ज किया जाने लगा। अब इस महीने मार्च के अन्दर म्यूनिसिपल कमेटी ने जो अनाऊन्स किया है, वह पिछले साल के टैक्स से 50 गुणा ज्यादा है और 1992-93 से दो सौ गुणा ज्यादा टैक्स लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसका सुधार किया जाना चाहिये और सरकार की तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी को आदेश दिए जाने चाहिये कि यह टैक्स 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, न कि 50 गुणा बढ़ाया जाए। क्या सरकार इसके लिए म्यूनिसिपल कमेटी को हिदायत जारी करेगी ? भिवानी में यह भी कहा गया है कि 25 मार्च तक इस टैक्स की रिकवरी होनी है और यह आदेश रिकवरी कमेटी के हैं। यह भी कहा गया है कि जो व्यापारी इस अवधि तक यह टैक्स नहीं देगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। यह ठीक नहीं है और न ही यह गरीब आदमी के लिये सहने योग्य है।

अब मैं डिमांड नं0 9 एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। आज स्कूलों को अपग्रेड किया जाता है, उसके क्या मापदंड हैं। पिछले साल भी यह बात आई थी कि हिसार में सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए गए थे। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम तो होने चाहिएं। जो भी उन नियमों को पूरा करता है, उनको अपग्रेड किया जाए। विशेष तौर से जो लड़कियों के स्कूल हैं, उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए ताकि लड़कियों को पढ़ने के लिये दूर न जाना पड़े। इस बारे में तो मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा था कि वे इसको ध्यान में रखेंगे।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, कई स्कूलों में अध्यापक न होने की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं होती है। इसलिये यह नकल जो होती है इसका कारण भी अध्यापकों का न होना है। ठीक है सरकार स्कूल खोल देती है लेकिन सरकार को वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था भी करनी चाहिये। मेरे हल्के में तीन कालेज हैं। अध्यापक की बात तो छोड़ो वहां पर प्रिंसीपल ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर प्रिंसीपल भी न हों, वहां पर शिक्षा का विस्तार कैसे हो सकता है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं0 11 हुड्डा के बारे में है। हाउसिंग कालोनियां हुड्डा डिवैल्प करती है लेकिन वहां पर न तो कालोनियां बनाई गई हैं और न ही सड़कें बनाई गई हैं। ये लोगों से बराबर किस्तें लेते रहते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति किस्त देने में लेट हो जाए तो उससे भारी इन्ट्रैस्ट चार्ज किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कालोनियां अभी तक नहीं बनाई गई हैं, उन लोगों से जो किस्तें ली जाती हैं वह ठीक हिसाब से नहीं ली जाती हैं। अगर वहां पर सड़कें बनाई जाती हैं तब तो किस्तें लें, अगर नहीं बनाई जाती हैं तो किस्तें न लें। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। सड़कों को पता नहीं कौन सा डिपार्टमैंट देखता है। सड़कें बनानी तो दूर

[श्री राम भजन अग्रवाल]

रही, उनकी रिपेयर का काम भी नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी मुरम्मत होनी चाहिए, साथ ही जो सीवरेज है वह भी ठीक होने चाहिएं। आज शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है इसलिये वहां पर सीवरेज सिस्टम होना चाहिए। साथ ही जो पुराने सीवरेज हैं, उनकी भी सफाई होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे शहर भिवानी के अन्दर दो सफाई की मशीनें हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। (घन्टी) उपाध्यक्ष महोदय, उन मशीनों से सीवरेज की सफाई नहीं होती जिस वजह से पीने के पानी में सीवरेज का पानी आ रहा है, इसलिये इस प्रोब्लम को दूर किया जाए।

अब सवाल इन्डस्ट्री का है। आज उद्योग लगाने के लिये बिजली की बहुत आवश्यकता है। बिजली को टाप प्रायरटी देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर जमीदारों को सबसीडी दी जाती है। लेकिन बिजली मिल ही नहीं रही, इसलिये सबसिडी का क्या फायदा ? इसलिये सरकार जमींदारों को बिजली दे। इसके अतिरिक्त लोगों को अपने जैनरेटर सैट लगाने दे ताकि वे अपने उद्योगों को ठीक से चला सकें। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों की स्टेट को बहुत जरूरत है लेकिन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ तो बिजली नहीं है और दूसरी तरफ उद्योग विभाग के अधिकारी भी ठीक तरह से एजुकेटिड नहीं हैं, इसलिये इंडस्ट्री के अधिकारियों को ऐजुकेटिड किया जाए ताकि जो लोग उद्योग लगाना चाहें, वे अधिकारी उन लोगों को ठीक ढंग से शिक्षा दे सकें ठीक तरह से उनको गाईड लाईन दे सकें। ऐसा करने से उद्योगपतियों का हौसला बढ़ेगा। न केवल बाहर के आदमियों को यहां बुलाकर उद्योग लगवाने चाहिएं बल्कि यहां के जो उद्योगपति हैं उनको भी उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिए और सरकार की तरफ से सुविधाएं देनी चाहिएं ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। आज प्रान्त के अन्दर अर्थव्यवस्था खराब हुई पड़ी है, अगर ठीक तरह से इन सब बातों की पालना हो तो अवश्य ही स्टेट का वातावरण ठीक हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अमर सिंह डांडे (गुहला) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, बाकी डिमांडज पर तो सभी साथी बोले हैं लेकिन डिमांड नं0 13 पर कोई साथी नहीं बोला। मैं इसी डिमांड पर कहना चाहूंगा जो समाज कल्याण विभाग से संबंधित है। सर, समाज कल्याण के लिये जो राशि रखी जाती है, उसका बहुत ही मिसयूज हो रहा है। सरकार इस राशि को हरिजनों पर खर्च करने के बजाए अन्य कामों पर खर्च करती है। कागजों में तो हरिजनों का नाम दे दिया जाता है कि हम इतना पैसा हरिजनों पर खर्च करने जा रहे हैं लेकिन वास्तव में वह पैसा उन पर खर्च नहीं होता। सरकार कहती है कि वह हरिजनों के लिये बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन हरिजनों की भलाई

का कोई काम नहीं होता, हरिजनों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, हरिजनों के साथ भेदभाव बरता जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। सी0एम0 साहब ने विधान सभा में चर्चा करते हुए एक बात कही थी कि सरकार 30 एच0सी0एस0 नौमिनेट करने जा रही है लेकिन सरकार ने इन तीस एच0सी0एस0 की भर्ती में हरिजनों के लिये कोई कोटा नहीं रखा यह बड़े खेद की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1981 में जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की पोस्टस एच0पी0एस0सी0 के परिधि से निकालकर डायरैक्ट जुडीशियल मैजिस्ट्रेट लिए गए थे, उस समय भी भजन लाल जी ही मुख्य मन्त्री थे। मुझे पता नहीं कि क्यों मुख्य मन्त्री जी हरिजनों से नाराज हैं, क्यों इन्होंने एच0सी0एस0 में हरिजनों का कोटा काट दिया? उनमें एक भी हरिजन नहीं लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के राज्य में अच्छी-अच्छी पोस्टों पर हरिजन लगाए जाते थे चाहे वह डी0जी0पी0 की पोस्ट थी। लेकिन इस सरकार में कोई भी हरिजन किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं लगाया जाता। सरकार उनके साथ बड़ा भेदभाव कर रही है। प्रमोशन की जो पौलिसी है, सरकार उसको भी पूरी तरह से लागू नहीं कर रही। मुझे विधान सभा की एस0सी0एवं एस0टी0 कमेटी का मैम्बर बनाया गया है। मेम्बर होने के नाते से मैंने देखा है कि सरकार ने किसी भी महकमे में हरिजनों को पूरी रिजर्वेशन नहीं दी। जब कोई टैस्ट होता है तो हरिजनों को छोड़ दिया जाता है। मैंने पिछले सैशन में सवाल भी दिया था कि बी0-1 की पोस्टों में हमारे हरिजन लड़कों को जान-बूझकर क्यों छोड़ दिया गया है, कारण यही है कि सरकार नहीं चाहती कि हरिजनों के लड़के आगे आएं, उनको कुछ फायदा हो। मैंने यह भी पूछा था कि हमारे हरियाणा के अन्दर जे0बी0टी0 अध्यापक कितने हैं और उनमें हरिजन कितने हैं जे0बी0टी0 की भर्ती में भी हरिजनों के साथ ज्यादती की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि अगर सरकार हरिजनों का ध्यान रखना चाहती है तो उनके लिये स्पेशल जे0बी0टी0 की ट्रेनिंग स्कूल खोलकर दे ताकि जे0बी0टी0 की भर्ती में हरिजनों का पिछला बैकलॉग पूरा किया जाए। जो हरिजन सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनके लिये भी सरकार चिंतित हो, उनके विकास के लिए भी सरकार कुछ न कुछ करे। जो हैड आफ दी डिपार्टमैंट्स रिजर्वेशन के कोटे को पूरी तरह से लागू नहीं करते, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो। ऐसा बिल सरकार विधान सभा में लाए, हम उसका समर्थन करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हरिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा की एस0सी0 एस0टी0 कमेटी के सामने ऐसे मसले भी आए कि अम्बाला में म्यूनिसपैलिटी में स्वीपर के पांच पदों पर सामान्य जाति के उम्मीदवारों को लगा दिया गया। इससे बढ़कर सरकार हरिजनों के साथ और क्या भेदभाव करेगी?

श्री उपाध्यक्ष : अमर सिंह जी, अम्बाला की जो बात आपने कही है, उससे मेरा भी ताल्लुक है। आप पर्टिकुलरज़ बता दें।

श्री अमर सिंह ढांडे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पर्टिकुलर्ज भी दे दूंगा पांच पोस्टें जो भरी गई हैं, वह स्वीपर की पोस्टें हैं और उन पर दूसरे लोग लगे हुए हैं । (विघ्न)

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी अभी अमर सिंह जी ने बोलते हुए कहा कि अम्बाला की म्यूनिसिपैलिटी में स्वीपर की पोस्ट पर दूसरे लोगों को लगाया है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर दूसरे भाई इस काम में आना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है । मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि अगर कोई दूसरा भाई सफाई का काम करना चाहे तो उसे भी उस काम में लगाया जाना चाहिए ।

श्री अमर सिंह ढांडे : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हरिजनों की प्रोमोशन के बारे में कह रहा था । (व्यवधान व शोर) सर, मैं डिमांड नं0 13, जो समाज कल्याण विभाग के बारे में है, पर बोल रहा हूं । डिप्टी स्पीकर सर, सरकार कहने को तो कहती है कि हम हरिजनों के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जहां तक प्रोमोशन पालिसी की बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे चौधरी देवी लाल जी की जब पहली बार सरकार आयी तो 9-2-1979 को, इन्होंने हरिजनों के लिये प्रोमोशन पालिसी बनायी थी । कहने को तो यह श्रेय कांग्रेसी लेते हैं लेकिन आप देखें कि यह पालिसी पहली बार किस सरकार ने बनायी थी ? जब दोबारा 1987-88 में चौधरी देवी लाल की सरकार आयी तो उसने सीनियौरिटी-कम-फिटनैस, प्रोमोशन की पालिसी हरिजनों के लिये लागू की । डिप्टी स्पीकर साहब, आप यह देखें कि हरिजनों के लिये किसने काम किया है और किसने नहीं किया है ? यह अब आप ही बता दें । डिप्टी स्पीकर साहब, अब यह पालिसी लागू है और हरिजनों के लिये प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन लागू है । अभी पिछले दिनों रैवेन्यू डिपार्टमैंट में 104 आदमियों की जो डिप्टी सुप्रिन्टैंडैंट्स की प्रोमोशन हुई है, उसमें केवल 10 या 12 हरिजन व्यक्तियों को यह प्रोमोशन दी गयी है । आप खुद अन्दाजा लगाइये, न इसमें बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को पूरी रिजर्वेशन दी गयी है और न ही हरिजनों को पूरी रिजर्वेशन दी गयी है । कहने को तो यह बहुत कुछ कहते रहते हैं लेकिन जहां तक रिजर्वेशन-इन-प्रोमोशन का ताल्लुक है, उसको भी पूरी तरह से यह लागू नहीं कर सकते । हरिजनों के साथ कितना भेदभाव यह सरकार कर रही है, यह आप खुद ही अन्दाजा लगा लें ?

अब मैं अपने हल्के के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । मेरे साथियों ने अपने-अपने हल्कों की दिक्कतों के बारे में बताया है । जो लोग सरकार में बैठे हैं, जब उनके हल्कों में ही बड़ी भारी कमियां हैं तो विपक्ष के आदमियों के हल्कों में तो बिल्कुल ही काम नहीं होते होंगे । मैं तो विपक्ष का आदमी हूं, इसलिये मेरे हल्के में किसी काम के होने का तो सवाल ही नहीं उठता । इससे कितनी दिक्कतें वहां के

लोगों को होती होंगी, इसका आप भली भान्ति अन्दाजा लगा सकते हैं ? मेरा हल्का गुहला-चीका है । वहां पर पिछली बार जब फ्लड आया था तो सबसे ज्यादा इसको मार पड़ी थी । फसलें तबाह हो गयीं, सड़कें भी काफी टूट-फूट गयीं । लेकिन उन टूटी हुई सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया । उन सड़कों की रिपेयर की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये था । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कैथल जिला के गुहला चीका हल्के के अन्दर एक नया पैसा भी सड़कों की मुरम्मत पर खर्च नहीं किया गया और न ही इसके लिये कोई पैसा दिया गया । आज उन सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि पैदल चलना भी मुश्किल है । मैं, चूंकि अपोजीशन में हूं, इसलिये वहां पर कोई काम नहीं हो रहे हैं जबकि बिना भेदभाव के सब जगह पर काम होने चाहियें ।

जहां तक शिक्षा की बात है, मेरे हल्के में शिक्षा का बुरा हाल है । वहां पर चीका और भागल में 10 जमा दो के स्कूल खोले गये थे जिनकी मन्जूरी चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने दी थी । उन दोनों स्कूलों को तोड़ कर, एक छोटे से गांव के स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया । वह गांव चूंकि वहां के पूर्व विधायक का है, जिसका नाम है कायथली । उस गांव के स्कूल को 10 जमा दो तक अपग्रेड कर दिया गया । एजुकेशन का इतना बुरा हाल है जिसकी कोई हद नहीं । हमारा हल्का पंजाब के साथ लगता है । उस एरिया में जितने भी स्कूल्ज हैं, उनमें अध्यापक ही नहीं हैं और जहां हैं, वहां बहुत ही कम हैं । सारे स्कूल अध्यापकों के बिना खाली पड़े हैं । मेरे क्षेत्र के हाई स्कूल में केवल दो-चार अध्यापक ही हैं और मिडल स्कूल में तो कोई एक या दो अध्यापक होते हैं । आज हमारे हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिये । केवल इस बिना पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये कि वह एक विपक्ष के विधायक का हल्का है । हम शुरु से ही चौधरी देवी लाल जी के साथ रहे हैं । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो ठीक बात है, वह इसे करनी चाहिये । ऐजुकेशन के मामले में चीका व भागल में क्या कमी है, उसको 10 जमा दो तक क्यों अपग्रेड नहीं किया जा सकता ? वह आपकी हर शर्त पूरी करता है । वहां पर बिल्डिंग पूरी है, जमीन पूरी है, फिर सरकार 10 जमा दो का स्कूल क्यों नहीं खोलती ? मेरा कहना यह है कि वहां का स्कूल भी जल्दी से जल्दी अपग्रेड होना चाहियें । वहां एक कालेज है। उसके अन्दर करीब एक महीना पहले गड़बड़ हुई थी, शायद उसका आप सबको पता होगा । वहां के पूर्व कांग्रेसी विधायक के भतीजे और लड़के ने, कालेज के एक लड़के के साथ इतनी मार-पीट की और पेट में चाकू मारा । वह लड़का आज भी हास्पिटल में पड़ा है । कालेज के प्रिंसिपल ने उन लड़कों को कालेज से एक्सपैल कर दिया । वहां का पूर्व विधायक आज भी इस इशू पर कालेज के प्रिंसिपल पर प्रैशर डाल रहा है कि उन लड़कों को, जिनको एक्सपैल कर दिया गया था, दोबारा एडमिट किया जाये ।

जहां तक नहरों और माईनर्ज का सम्बन्ध है, मेरे हल्के में दो माईनर्ज पड़ती

[श्री अमर सिंह ढांडे]

हैं। आज तक उनके अन्दर कोई काम नहीं हुआ है। उनकी कभी भी गाद वगैरह नहीं निकाली गई। उपाध्यक्ष महोदय, पानी की हालत यह है कि आज तक टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। मेरा एरिया जोरी का एरिया है। अगर वहां पर पूरा पानी न मिले तो जोरी की फसल को काफी नुकसान होता है। मेरे हल्के में बिजली की भी काफी कमी है। बिजली की हालत यह है कि दो घंटे बिजली मिलती है। कनक की फसल तैयार है और उसे पानी की जरूरत है लेकिन बिजली की कमी की वजह से लोग अपने ट्यूबवैल्ज नहीं चला सकते। आगे जोरी की फसल आने वाली है, उसका सीजन कुछ समय बाद आ रहा है। अगर वहां पर पूरी बिजली नहीं दी गई तो जोरी की फसल की बुआई में काफी नुकसान हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में पंचायत की जमीन का एक बहुत बड़ा घपला हुआ था और उसके बारे में आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। पंचायत की जमीन पर एक पूर्व सरपंच ने कब्जा कर लिया है। यह कब्जा उसने अफसरों की मिलीभगत से किया था। वह चालीस एकड़ जमीन थी लेकिन सरकार ने उसका कब्जा छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो अब पंचायत बनी, उसने उस जमीन से उस सरपंच को बेदखल करने का केस तैयार किया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जिन अफसरों की मिलीभगत से उस पूर्व सरपंच ने पंचायत की जमीन पर कब्जा किया, उन अफसरों के खिलाफ भी सरकार ने कोई ऐक्शन नहीं लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जंगलात के बारे में कहना चाहता हूं कि बिलासपुर में जंगलात को नाजायज तौर पर काट लिया गया। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वे सरकारी पेड़ नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सोलह हजार सरकारी पेड़ थे जिनको काटा गया था। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि वे सरकारी पेड़ नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, कितने ताज्जुब की बात है कि पच्चीस सौ पेड़ काटने का ठेका दिया गया। लेकिन उस ठेकेदार ने सरकार की मिली भगत से 25 हजार पेड़ काट लिए। उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। एक तरफ तो सरकार वन लगा रही है और दूसरी तरफ सरकार के मन्त्री घपला कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को दुबारा दोहराना चाहता हूं कि यह सरकार हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों के सहारे चल रही है लेकिन उनकी भलाई का कोई काम नहीं कर रही है। अगर सरकार उनकी भलाई के लिए कोई पग नहीं उठाएगी तो उन लोगों का कैसे भला हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : अमर सिंह जी, अब आप खत्म करें।

श्री अमर सिंह डांडे : सर, सरकार को चाहिए कि हरिजनों का जो हक है, चाहे वह मुलाजमत में है या आम आदमी है, वह उनको मिलना चाहिए । अच्छा जी, अब मैं खत्म करता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : अब श्रीमती चन्द्रावती जी बोलेंगी ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे न तो गवर्नर ऐड्रेस पर टाईम दिया गया और न ही बजट पर दिया जा रहा है । मैंने एक कट मोशन भी दिया हुआ है । ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे टाईम ही नहीं दिया जा रहा है ? मुझे टाईम मिलना ही चाहिए । बोलने का मेरा कांस्टीट्यूशनल राईट है । यहां पर एक-एक आदमी को आधा-आधा घंटा टाईम दिया जा रहा है लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा है। ऐसी क्या बात है ?

चौधरी जगदीश नेहरा : उपाध्यक्ष महोदय, इन डिमाण्डज पर बोलने के लिए जो टोटल टाईम स्पीकर साहब ने अलाट किया है, उसके हिसाब से जितना जिसके हिस्से में आता है, आप उतना समय दे दें । ओम प्रकाश जी के हिस्से में अगर एक मिनट आता है तो एक मिनट दे दें और अगर नहीं आता है तो न दें । आप जानते हैं कि हमारे पैसठ मैम्बर हैं और इनमें से केवल दो मैम्बर बोले हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे मैम्बर्ज को पूरा समय दिया जाए ।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : डिप्टी स्पीकर साहब, समय देने के लिए आपका धन्यवाद । मैं डिमान्डज पर बोलना चाहती हूं । इन डिमाण्डज में इरिगेशन की डिमाण्ड तो है लेकिन पावर की डिमाण्ड नहीं है । क्या पावर का अलग से बजट है ? मेरे ख्याल से पावर की डिमाण्ड भी होनी चाहिए थी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं कोआप्रेटिव की डिमाण्ड के बारे में कहना चाहती हूं । मैं इस बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी । उपाध्यक्ष महोदय, जो कोआप्रेटिव सोसायटीज हैं, अगर वे डिफाल्टर हो जाती हैं तो कुछ लोग उन पर कब्जा कर लेते हैं । कुछ ने उन पर कब्जा कर भी रखा है और वे उसी के हिसाब से रल मिल कर ठीक कर लेते हैं और दूसरे किसी व्यक्ति को उसमें घुसने नहीं देते । ऐसे लोगों की सोसायटीज में मैम्बरशिप नहीं होनी चाहिये । मैं चाहूंगी कि सचिव व रजिस्ट्रार के लैवल पर इस बात को देखा जाना चाहिये । जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उनको हटाये जाने के लिये सरकार को कोई उचित कदम उठाने चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं हुड्डा के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी । हुड्डा कुछेक किसानों की जमीनों को ले लेता है लेकिन उनको उसका सही मुआवजा व आल्टरनेटिव नहीं दिया जाता । किसानों के पास उस जमीन के सिवाये खाने पीने का कोई दूसरा साधन नहीं होता और कोई दूसरा काम धन्धा भी उनके पास नहीं होता जिसके सहारे लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकें । इसलिये मैं आपके द्वारा

[श्रीमती चन्द्रावती]

सरकार से कहूंगी कि जिन लोगों की सरकार जमीन लेती है, उन को सरकार को नौकरियां देनी चाहियें या कोई दूसरा आल्टरनेटिव सरकार को देना चाहिये ताकि वे लोग, जिनकी जमीनें हुड्डा ले लेता है, उसके पास जीवन निर्वाह करने के पक्के साधन हों । पैसा जो सरकार देती है, वह तो एक किस्म का कंपन्सेशन होता है और वह पैसा खत्म भी हो सकता है । अगर सरकार कोई ऐसा साधन ऐसे लोगों को जुटाये जिससे उनका परिवार का गुजारा परमानैन्ट होता रहे, तो बड़ी अच्छी बात है । उपाध्यक्ष महोदय, अपनी रोजी-रोटी कमाना, उनके फण्डामैन्टल राईट्स में आता है, इसलिये सरकार इस तरफ ध्यान दे । वह नहीं होना चाहिये कि लोगों की सारी की सारी जमीन ले ली जाए और उनको उसका कोई आल्टरनेटिव न दिया जाए । इसमें कुछ अफसरों का इंट्रैस्ट भी होता है । इसलिये सरकार ऐसे किसानों को, जिनकी जमीनें ले ली जाती हैं, उनको आल्टरनेटिव जॉब प्रदान करे ।

दूसरी बात मैं सिविल सप्लाई के बारे में भी कहना चाहती हूं । इस बार तो भगवान् की कृपा से सभी जगहों पर बारिश के कारण फसल काफी अच्छी हो गई है । पिछली दफा फसल अच्छी नहीं थी । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सरकारी डिपोज पर राशन का 20 किलो गेहूं एक परिवार को दिया जाता है, वह सफीशीऐन्ट नहीं है । इससे एक परिवार का काम नहीं चल सकता । सरकार को ज्यादा मिकदार में गेहूं मुहैया कराना चाहिये । इसी तरह से दूसरी चीजों की सप्लाई, जैसे चीनी, चावल वगैरह व दूसरी जितनी भी जरूरी चीजें डिपोज में मिलनी चाहिएं, उनकी सप्लाई में वृद्धि होनी चाहिये और सभी को सारी चीजें सरकारी डिपोज पर अवेलेबल होनी चाहियें ।

इससे आगे मैं पैट्रोल पम्पों के बारे में भी कहूंगी । मैंने पहले भी एक बार इस बात का जिक्र किया था कि पैट्रोल पम्पों के ऊपर डीजल में मिट्टी का तेल मिलाकर बेचा जाता है जिससे किसानों के ट्रैक्टर्ज, सरकारी जीपों को, व बसों को काफी नुक्सान होता है । मिट्टी का तेल मिलाकर अगर तेल बेचा जाएगा तो इंजनों का भट्ठा बैठ जाएगा । डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में काफी फर्क है जिस कारण से शायद यह हेराफेरी होती है । या तो सरकार इनकी कीमतों को एक कर दे ताकि अडल्ट्रेशन कम हो सके । नहीं तो इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे । इससे गरीब किसानों के ट्रैक्टर्ज को काफी नुक्सान पहुंच सकता है । जो लोग ऐसे कामों में संलग्न हैं, उनको अपराधिक श्रेणी में गिना जाना चाहिये । इसका सरकार को जल्दी ही कोई न कोई इलाज करना चाहिये । मेरे नोटिस देने के बाद कई जगहों पर छापे भी पड़े हैं लेकिन यह सफीशीऐन्ट नहीं है । डीजल में मिलावट करके जो पैट्रोल पम्प वाले बेचते हैं, उससे जनता को काफी नुक्सान होता है । किसान इससे काफी दुखी है । मैं तो यह कहूंगी कि जो विभागीय अधिकारी होते हैं, उनसे मिलकर ही यह

सब कुछ होता है । मैं सुझाव दूंगी कि जो ईमानदार अफसर हैं, उनका ऐसे लोगों के ऊपर चैक होनी चाहिये ताकि वे इस तरह का गल्त काम न कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे अगली बात मैं बिजली से सम्बन्धित कहना चाहती हूं । मैंने पहले भी अर्ज किया था कि लोहारू के अन्दर 33 के0वी0 का सब-स्टेशन लगा हुआ है, उसको 66 के0वी0 का कर दिया जाना चाहिये । इसी तरह से बहूल का, डिकोडा का है । नकीपुर का एक दफा फाउंडेशन स्टोन सरकार की तरफ से रखा गया है, मेरी प्रार्थना है कि सरकार वहां का काम जल्दी करवाये । इसी तरह से भोवड़ा व बादड़ा जो मेरे हल्के में आते हैं। मेरी कांस्टीचुऐन्सी तीन जिलों से मिली हुई है और भादड़ा महेन्द्रगढ़ जिला में पड़ता है । मेरी गुजारिश है कि इन सभी सब-स्टेशनों पर जल्दी ही काम पूरा करवा दिया जाए ताकि लोगों को सही मिकदार में बिजली मिल सके और बिजली का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके । दूसरे डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली के मामले में कुछ सुधार जरूर हुआ है, इतना ही सुधार और होना चाहिए । यह सुधार तभी हो सकता है जब ज्यादा थर्मल या हाइडल पावर प्लांटस लगाए जाएंगे । आपको पता है कि रोजाना नई नई इंडस्ट्रीज लगती हैं, बिजली के बिना उनको भी मुश्किल होती है । आज मुझे जगाधरी के कुछ लोग मिले थे । जगाधरी, फरीदाबाद या सोनीपत जैसी जगहों में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं । वे लोगों को भी रोजगार देती हैं और अपना रोजगार भी चलाती हैं । आपको पता है कि जमीन अब इतनी नहीं रही है । कुछ जमीन पर लोग बस जाएंगे, कुछ सड़कें वगैरह बनाने में आ गई इसलिए लोगों को काम देने के लिए केवल इंडस्ट्री ही है, इसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए । हमारे लोहारू के लोगों की काफी समय से मांग है कि वहां पर एक पोलेटैकनिक होना चाहिए । इसी तरह से दादरी की एजुकेशन सोसाइटी ने रिप्रजैंटेशन दिया है कि उनको फारमेसी कालेज खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए । इसी तरह से हस्पतालों की हालत है । लोहारू और दादरी के हस्पतालों का मुझे पता है, उनकी बहुत अच्छी हालत नहीं है। वहां पर ज्यादा डाक्टर्ज की जरूरत है और दवाइयां तो न के बराबर हैं । मेरी आपके द्वारा सरकार से अपील है कि जो जरूरी दवाइयां गरीब आदमी के लिए चाहिएं, कम से कम वे तो होनी चाहिएं । आपको मालूम है कि गांवों के हस्पतालों में तो गरीब आदमी ही जाते हैं । इसलिए वहां पर ज्यादा डाक्टर भी भेजे जाएं और दवाइयां भी दी जाएं । कई डाक्टर ऐसे हैं जो गांव में नहीं जाना चाहते, इसलिए सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए । यही हालत स्कूलों की है । जो स्कूल शहरों में हैं, वे तो स्टाफ के साथ ओवर क्राउडिड हो जाते हैं और गांवों में पोस्टें खाली पड़ी रहती हैं । हमारे यहां बिसलवास में कई सालों से हैडमास्टर नहीं है। यही हाल खरखड़ी और मंडोली कलां का है । बच्चे स्कूलों में नकल क्यों करते हैं क्योंकि अध्यापक उनको नहीं पढ़ाते ? यह तो वह बात हुई कि लौह खोदा लोहार भी खोदा । लोहारू में एक डाक्टर है जो ड्रंगिस्ट है । मैंने विभाग वालों को कहा कि इसको ऐसी जगह लगाओ, जहां जिम्मेदारी न हो, बरना इसको पैन्शन देकर घर

[श्रीमती चन्द्रावती]

भेज दो । ऐसे आदमियों को ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां डाक्टरों की तादाद ज्यादा हो । जहां पर डाक्टर की एक ही पोस्ट हो, ऐसी जगह पर ऐसे लोगों को न लगाया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे टाईम दिया ।

चौधरी ओम प्रकाश (बेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आखिर टाईम दे ही दिया । मैं डिमांड नं0 11, 15 और 17 पर बोलूंगा । मैं सबसे पहले इरीगेशन के बारे में कहना चाहूंगा । आज हरियाणा प्रदेश की 70% जनता कृषि पर आधारित है और कृषि के लिए इरीगेशन वाटर की जरूरत है । नहरी पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 17 साल से हरियाणा प्रदेश के अन्दर.....

श्री उपाध्यक्ष: बेरी साहब, आप एक मिनट के लिए बैठें । जिन मैंबर साहेबान ने बोलने के लिए अपने नाम दिए हुए हैं, मेहरबानी करके वे अपनी सीट पर रहें वरना उनका नाम कट जाएगा ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जहां तक सिंचाई के लिए पानी का ताल्लुक है, उसमें बहुत बड़ा भेदभाव जमना सिस्टम के एरिया के साथ किया जा रहा है । उस एरिया के साथ ज्यादा भेदभाव रहा है । एस्टिमेट्स कमेटी का चेयरमैन होने के नाते मैंने पिछले साल 1992-93 में उस कमेटी की 25वीं रिपोर्ट हाउस के सामने पेश की थी । उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर दर्शाया गया था कि हरियाणा प्रदेश में रावी व्यास का 18 लाख एकड़ फीट पानी आ रहा है और उस पानी में केवल भाव रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव और भिवानी जिलों का हक है । लेकिन वह पानी उन जिलों को न देते हुए वह पानी हिसार जिले के हांसी उपमण्डल को छोड़ कर, बाकी सभी उप मंडलों को, पूरा सिरसा जिला, कैथल जिला और जींद जिले के नरवाना क्षेत्र को अनअथोराइज्ड-वे से दिया जा रहा है । यह पानी पिछले 17 साल से भाखड़ा मुख्य नहर में डाल कर हरियाणा प्रदेश में लाया जा रहा है । जब इस बारे में सवाल उठाया गया तो कह दिया गया कि नरवाना ब्रांच की इतनी कैपेसिटी नहीं है जिससे इस पानी को लाया जा सके । इस बारे में मैं सरकार को सुझाव दूंगा जिसके जरिए जमना सिस्टम में पानी पहुंचाया जाए ताकि जिन इलाकों का वह पानी है, उनको वह पानी दिया जा सके । एक तो नरवाना ब्रांच के किनारों को तीन-तीन फुट ऊंचा किया जाए और नरवाना ब्रांच की छंटाई करवाई जाए । यह काम केवल 50 किलोमीटर पंजाब के क्षेत्र में केवल 3 महीने में किया जा सकता है । नरवाना ब्रांच की आज तक डीसि-लटिंग नहीं करवाई गई, वह बिल्कुल अंटी पड़ी है । नरवाना ब्रांच की 4022 क्यू-सिक्स की कैपेसिटी थी, वह आज घट गई है। उसकी तरफ आज तक ध्यान नहीं

दिया गया । मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पोलीटिकल आधार पर दक्षिणी हरियाणा के साथ पिछले 17 साल से सिंचाई पानी के बारे में भेदभाव होता रहा है । जिस जिले का मुख्य मन्त्री बना, उसने उसी जिले के बारे में सोचा, दूसरे जिलों के बारे में नहीं सोचा । (शोर)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात बार-बार चौधरी ओम प्रकाश बेरी ने प्रेस में भी कही है । मैं इनको बताना चाहता हूं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ सिंचाई के पानी के बारे में कतई भेदभाव नहीं है और वह क्यों नहीं है ? वह इसलिए नहीं है क्योंकि जो सिस्टम पिछला चला आ रहा है, वह इनके जो बड़ भाई श्री शेर सिंह इरीगेशन मिनिस्टर थे, के समय से ही चला आ रहा है । वे ज्वायंट पंजाब में भी रहे, उन्होंने जो पानी तकसीम किया, उसके हिसाब से सभी जगहों पर पानी दिया जा रहा है । उस सिस्टम को बनाने में चौधरी रिजक राम और लहरी सिंह भी रहे हैं । जो भाखड़ा और जमना नदी के पानी का सिस्टम है, वह उसी हिसाब से चल रहा है। उस सिस्टम को किसी भी सरकार ने नहीं बदला । न उस सिस्टम को चौधरी भजन लाल की सरकार ने बदला, न चौधरी बंसी लाल की सरकार ने बदला और न ही चौधरी देवी लाल की सरकार ने बदला, किसी भी सरकार ने नहीं बदला । इन्होंने तो इस तरह से बात कह करके यह मुद्दा उठाना है । डिप्टी स्पीकर साहब, डब्ल्यू0 जे0 सी0 को जो कैपेसिटी है, उसमें पानी कम आता है । उसका रीजन है और वह यह है कि भाखड़ा नहर में जो पानी है, वह स्टोर कर लिया जाता है और लीन सीजन में, सर्दियों के टाईम में वह पानी मिलता रहता है । जो भाखड़ा का पानी है वह स्टोर हुआ हुआ है और उसको जब पानी की कमी होती है, तब उसको छोड़ा जाता है और लीन सीजन में वह पानी भाखड़ा के एरिया में सप्लाई होता है । इसलिए यह कहना कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेद भाव होता है, वह गलत बात है। इसके अलावा जब तक जमना के बारे में कोई समझौता नहीं होता, तब तक उसका पानी स्टोर नहीं होगा । माननीय सदस्य द्वारा ऐसी बातें केवल पोलिटिकल गेन लेने के लिए कही जाती हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है । ये अपनी बात अपने जवाब में कह सकते हैं । मंत्री जी ने जो बात कही है, उससे मैं डिमोरेलाइज होने वाला नहीं हूं । दक्षिणी हरियाणा के साथ जो सिंचाई पानी के बारे में भेदभाव हुआ, चाहे वह किसी कारण से हुआ, वह दूर होना चाहिए । वह शेर सिंह की वजह से हुआ, चाहे रिजक राम और लहरी सिंह की वजह से हुआ, आज आप सत्ता में हैं आपको यह डिस्क्रिमिनेशन दूर करनी चाहिए । मंत्री जी जान बूझकर हाउस को गुमराह कर रहे हैं । पोलिटिकल आधार पर दक्षिणी हरियाणा के साथ सिंचाई के पानी के बारे में पिछले 17 साल से भेदभाव किया जा रहा है और इस भेदभाव में चौ0 शेर सिंह, चौ0 लहरी सिंह आदि का कोई हाथ नहीं है । उपाध्यक्ष

[चौधरी ओम प्रकाश बेरी]

महोदय, मैं सुझाव दे रहा था कि एक तो नरवाना ब्रांच की छटाई करवाई जाए। उसके किनारों को तीन-तीन फुट ऊंचा किया जाये। दूसरा इनका यह कहना कि इसमें 18 लाख एकड़ फुट पानी नहीं समा सकता तो इस बारे में मेरी परपोजल यह है कि बरवाला लिंक कैनाल को, जिसमें भाखड़ा का पानी लगता है, उसको पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी से अगर जोड़ दें, जिस की लम्बाई 30 कि0 मी0 है, इससे सिवानी कैनाल का कमांड एरिया और हांसी सब डिवीजन में भाखड़ा का पानी मिल सकता है। और इस तरह से पूरा 18 लाख एकड़ फुट पानी जो हमारा हक है, वह इन इलाकों को दिया जा सकता है। इसके अलावा, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पानी की वजह से इनकी 22 दिन नहरें महीने में चलती हैं। यानी हिसार सिरसा जो इनके इलाके मैंने गिनवाये हैं, मुख्य मंत्री जी का इलाका, सिंचाई मंत्री जी के इलाके में तो एक महीने में 22 दिन नहरें चलती हैं जबकि रोहतक और सोनीपत में एक महीने में एक सप्ताह नहरें चलती हैं और भिवानी में एक माह में साढे तीन दिन नहरी पानी वहां के लोगों को मिलता है। इसके अलावा, गुड़गांव फरीदाबाद में तो इस पानी को ले जाने के लिए नहरों के निर्माण की बात तो छोड़िए, नहरों के निर्माण के बारे में सोचा तक नहीं गया। इतना ग्रेजल डिस्क्रिमिनेशन है। इसके अलावा, मैं आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि हमारे यहां नहरी पानी पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रदेश में दो मुख्य सिस्टम हैं। एक तो यमुना सिस्टम और दूसरा भाखड़ा सिस्टम। यमुना सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं कि यमुना का कमांड एरिया 40 लाख एकड़ है, पानी उसके लिए 38 लाख एकड़ फुट, भाखड़ा सिस्टम में 29 लाख एकड़ रकबा और 58 लाख एकड़ फुट पानी इतना ग्रेजल डिस्क्रिमिनेशन है। इसके अलावा, यमुना सिस्टम की आबादी 80 परसैंट, एरिया 70 परसैंट और पानी 40 परसैंट। भाखड़ा की 20 परसैंट पापुलेशन, 30 परसैंट एरिया और 60 परसैंट हरियाणा का पानी मिलता है। एवरेज वाटर एक साल में जो भाखड़ा सिस्टम से मिलता है, वह है 264 दिन और यमुना सिस्टम को मिलता है एक साल में 96 दिन, यानी 3 गुना पानी इनको अधिक मिलता है। यह हालत इन लोगों ने पानी के बारे में कर रखी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि.......

चौधरी जगदीश नेहरा : यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं। यह जो आंकड़े दे रहे हैं वह गलत हैं। यह जो भाखड़ा सिस्टम है, यह 1954 का बना हुआ है और डब्लू0 जे0 सी0 सैंकड़ों सालों से है। मैं बताना चाहता हूं कि जब भाखड़ा नहीं बनी थी तो उस समय उस एरिया की क्या हालत थी और जब भाखड़ा बन गया तो उस समय बटेज करने में क्या इनके बड़े भाई शेर सिंह का हाथ नहीं है ?

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : वे तो 1956 में मंत्री बने थे जबकि भाखड़ा 1954 में बनी।

चौधरी जगदीश नेहरा : ये जो आंकड़े दे रहे हैं, वे सही दें। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये आंकड़े वह दें जो सही हों और सारे हाउस को

गुमराह करने के लिए वही बातें दुबारा न कहें कि दक्षिणी हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है। दक्षिण हरियाणा की नहरें कोई नयी नहीं हैं बल्कि 40-50 साल पहले की बनी हुई हैं, न कि आज की। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ पौलिटिकल गेन लेने के लिए बातें कर रहे हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कुल पानी, जिसमें ट्यूबवैल्ज का पानी भी शामिल है, वह है 16 एम0ए0एफ0, जबकि हमें इससे कम से कम 2 गुना पानी चाहिए। यह पानी कहां से आयेगा, इस पानी को लाने के लिए क्या रिसोर्सिज हों इस बारे में हरियाणा सरकार ने सोचने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इनके इलाके में आज जो हकूमत कर रहे हैं 17-18 साल से, वही पानी के बारे में गड़बड़ कर रहे हैं। इन के इलाके में पानी बहुतायत में है, इसलिए इस बारे में इन्होंने नहीं सोचा कि हमें भी पानी की जरूरत है, चाहे हमारा इलाका प्यासा मर जाये, जमीन प्यासी मर जाये लेकिन इस बात की इनको कोई चिंता नहीं है। इस बारे में सरकार को डिस्क्रिमिनेशन दूर करना चाहिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को बराबर पानी मिलना चाहिए। इसके लिए रिसोर्सिज कौन से हैं। कैसे इनको पानी मिल सकता है ? इसके बारे में जो मैं सुझाव दूं, अगर उन पर सरकार अमल करे तो यह समस्या दूर हो सकती है और सारे इलाकों को पानी मिल सकता है। मेरा सुझाव है कि आगरा कैनाल का कन्ट्रोल हरियाणा सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और यदि हरियाणा सरकार यह कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले सकती तो बैनिफिशरी स्टेट होने के नाते हरियाणा सरकार को चाहिए कि सैन्ट्रल सरकार के साथ मिलकर इसका कन्ट्रोल अपने हाथ में ले ले ताकि जितना हिस्सा गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों का है, वह पानी उनको मिल सके। दूसरे, दादूपुर नलवी नहर की स्कीम काफी दिनों से धूल चाट रही है। यह 1985 में मन्जूर हुई थी। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि जब यह मंजूर हुई थी तो उस वक्त से इसका खर्च बढ़कर 5 गुना हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस नहर को बनाने पर अमल किया जाये ताकि कम से कम 3-4 जिलों का फायदा हो सके और उनको नहरी पानी सिंचाई के लिए मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि यमुना पर किसाऊ डैम के बारे में एक स्कीम थी। सैंट्रल गवर्नमैंट से बात करके जल्दी से जल्दी यह बान्ध बने, रिजरवायर हो ताकि पानी किसान को मिल सके और खेतों की प्यास बुझ सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हम दिल्ली को पीने का पानी दे रहे हैं। क्या दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी केवल हरियाणा सरकार की है ? यह बात ठीक है कि दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाना सबका फर्ज बनता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हरियाणा जैसी छोटी सी स्टेट अकेले ही उसकी पानी की जरूरत को पूरा करे। यमुना के पानी में दिल्ली का कोई शेयर नहीं है। रावी-व्यास में से 2 लाख एकड़ फुट पानी उसके हिस्से का है।

[चौधरी ओम प्रकाश बेरी]

इस बारे में केन्द्र सरकार से बात करके दूसरी स्टेट्स को भी दिल्ली को पानी उपलब्ध करवाने के लिए हिस्सेदार बनाया जाए । यू0पी0 भी दिल्ली की एडजायनिंग स्टेट है और काफी मिकदार में उसके पास पानी अवेलेबल है इसलिए वह भी दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाने में हिस्सा दे । उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि ताजेवाला हैड वर्क्स 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। हथनी कुण्ड बैराज की स्कीम के बारे केन्द्र सरकार से जल्दी से जल्दी बात करके इस स्कीम को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए ताकि सारी स्टेट को हम ठीक ढंग से सिंचाई के लिए पानी दे सकें । हरिके-हैडवर्क्स के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । फिरोजपुर में सतलुज के बेड़े से पानी यूज करता है । यह पानी पंजाब से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ समुद्र में जा गिरता है और वेस्ट जा रहा है । इस बारे में मेरी परपोजल है । इस बारे एक स्कीम भी शायद बनी थी । इस पानी को हम राजस्थान कैनाल में डाल दें और यह पानी राजस्थान को दे दिया जाए । जितना पानी राजस्थान को दें उतना पानी हम हरियाणा के लिए ले लें तो हरियाणा को उस पानी से लाभ हो सकता है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बेरी साहब, आप वाइंड अप करिये । आपका टाईम अप हो चुका है । (विघ्न) आप अपनी बात सिर्फ 2 मिनट में समाप्त करें । (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा टाईम नहीं लूंगा सिर्फ 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मैं तो 5-7 मिनट ही बोला हूं, ज्यादा टाईम तो इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने ही ले लिया । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, नहरों की हालत बहुत बुरी है । अब मैं डी-सिल्टिंग के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे इलाके में डज्जर सब-ब्रान्च बहुत बड़ी नहर है, उसकी कैपेसिटी 900 क्यूसिक पानी की है परन्तु इस समय उस की क्षमता केवल 450 क्यूसिक पानी की रह गयी है । वहां पर मन्त्री जी भी गए थे और देख कर आए थे । मेरा सुझाव है कि शीघ्र इस नहर की छटाई करवाई जाए और लाईनिंग करवाई जाए ताकि पानी टेल तक पहुंच सके । उपाध्यक्ष महोदय, एक और प्रॉब्लम भी है । जे0एल0एन0 के साथ-साथ जे0एस0बी0 भी पैरलल चलती है । सीपेज की प्रॉब्लम बहुत भारी प्रॉब्लम है । जे0एल0एन0 के साथ डिच ड्रेन की स्कीम मन्जूर की गई थी । उपाध्यक्ष महोदय, केवल स्कीम मन्जूर करने का कोई फायदा नहीं है बजट एलोकेशन होनी चाहिए ताकि काम हो सके । जे0एल0एन0 के साथ जे0एस0बी0 भी पैरलल बहती है । दोनों तरफ से डिच ड्रेन बनेगी, तब जा कर वाटर लौगिंग की प्रॉब्लम हल हो सकेगी । हमारे अकेले जिले का 40 हजार एकड़ का रकबा सीपेज की वजह से खराब हो चुका है इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, गजब की बात यह है कि जिन लोगों के खेत 15-16 साल से वाटर लौगिंग की वजह से खराब हो गए हैं और एक दाना भी पैदा नहीं होता, उनसे आबियाना वसूल

किया जा रहा है । अगर यह बात गलत हो तो बेशक हाउस की कमेटी बना दी जाए जो इस बात का पता कर ले । उन किसानों से आबियाना वसूल नहीं होना चाहिए बल्कि उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, इसी ढंग से मैं एक बात एस0 वाई0 एल0 नहर के बारे में कहना चाहता हूं । पिछले ढाई-तीन साल से जब से मुख्य मन्त्री जी प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने हैं, रोज ब्यान दे देते हैं कि एस0 वाई0 एल0 कैनाल एक वर्ष में बन जाएगी । मैं जानना चाहता हूं कि वह साल किस तारीख से शुरु होगा और कौन सी तारीख को खत्म होगा और उस साल के कितने दिन होंगे ? ताकि हरियाणा की जनता इस गुमराही से तो बच जाए । उपाध्यक्ष महोदय, कभी मुख्य मन्त्री जी का कुछ ब्यान आ जाता है और कभी कुछ और, रोज ये तरह तरह के ब्यान दे देते हैं और बेअन्त सिंह का कुछ और ब्यान आ जाता है । (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में हरियाणा सरकार श्वेत-पत्र जारी करे ताकि हरियाणा की जनता को पता लग जाए कि यह नहर बनाने की हरियाणा सरकार की मन्शा भी है या नहीं । एस0 वाई0 एल0 कैनाल की कन्स्ट्रक्शन के बारे में हरियाणा सरकार का इन-डिफरैंट एटीच्यूड है । अगर यह नहर बन गई तो फिर रावी-व्यास का पानी भाखड़ा कैनाल में डालने की जरूरत नहीं होगी, वहां से सीधे उसमें डाल कर यमुना से जा मिलेगा और उस पानी की ये लोग चोरी नहीं कर सकेंगे । यह नहर बनाने का हरियाणा सरकार का कोई इन्ट्रैस्ट नहीं है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बेरी साहब, आपका समय खत्म हो गया है, अब आप बैठें ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो मिनट एग्रीकल्चर के बारे में लेना चाहता हूं । एग्रीकल्चर के बारे में मैंने कट मोशन भी दिया था । वाटर की प्रोपर मैनेजमैंट के लिए सरकार काफी जोर देती है । सप्रिंकलर सैट्स के द्वारा सिंचाई करने से पानी की काफी बचत होती है । हमारे प्रदेश के अन्दर सप्रिंकलर सैट्स पर सेल्ज टैक्स है, जबकि एडज्वायनिंग स्टेट्स में कोई सेल्ज टैक्स नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, खासकर दक्षिणी हरियाणा में आबपाशी के लिए यह सबसे बेहतरीन साधन है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार एग्रीकल्चरल इम्पलिमैंट्स को सेल्ज टैक्स से एग्जम्पट किया हुआ है, उसी प्रकार से सप्रिंकलर सैट्स को भी सेल्ज टैक्स से एग्जैम्पट किया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, करनाल के अन्दर एक दुकान सरकार ने खोल रखी है । वहां पर अप्रोच द्वारा पांच हजार रुपए सैम्पल ठीक करने के लिए लिये जाते हैं । यह बहुत ही घटिया बात है । मैं पूछता हूं कि जिलों में डिप्टी डायरैक्टर कृषि विभाग किस लिए बैठा हुआ है ? किसानों को मार्केट में कृषि अधिकारियों की मिली भगत से घटिया इन्सैक्टीसाईडस तथा पैस्टीसाईडज बेचा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : बेरी साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । अब अमर सिंह धानक बोलेंगे ।

श्री अमर सिंह धानक (बवानी खेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं डिमान्ड नं0 17–एग्रीकल्चर, डिमान्ड नं0 15–इरीगेशन, डिमान्ड नं0 16–इंडस्ट्रीज, डिमान्ड नं0 23–ट्रांस्पोर्ट, डिमान्ड नं0 13–सोशल वैल्फेयर, डिमान्ड नं0 9–एजुकेशन आदि पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने और आनरेबल वित्तमंत्री जी ने जो बजट सदन में रखा है, वह टैक्स रहित है । यह किसान को समृद्ध और बैकवर्ड क्लासिज और शैडूलकास्ट को आगे लाने के लिए है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । आज अगर किसान की हालत सुधर जाएगी तो यह बहुत ही अच्छा होगा । अगर किसान सुखी है तो देश सुखी है और अगर किसान दुखी है तो सारा देश दुखी है । जब भी किसान की हालत खराब हुई, तो कहीं पर बाढ़ की वजह से, कहीं पर सूखे की वजह से । सरकार ने ऐसी हालात में किसानों को कई तरह की सहायता देकर बचाया । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी से दरख्वास्त है कि अगर एग्रीकल्चर, इरीगेशन और इलैक्ट्रीसीटी को बजट में ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो हमारी स्टेट के हालात और अच्छे हो सकते हैं। वित्तमंत्री जी ने तीनों मदों पर जोर दिया है । एग्रीकल्चर का मतलब मैं यह समझता हूं कि अगर किसान को जरूरत के मुताबिक पानी मिल जाए तो वह काफी तरक्की कर सकता है । हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है । वह कड़ाके की सर्दी और धूप की परवाह भी नहीं करता । इसलिए उसे पानी जरूरत के मुताबिक मिलना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से बहुत सारी बातें आती हैं । इधर के विरोधी भाई बोलकर नुक्ताचीनी तो करते हैं लेकिन सही सुझाव देने के लिए तैयार नहीं । ये लोग जब कुर्सी पर होते हैं तो एस0 वाई0 एल0 को भूल जाते हैं और कुर्सी से हटते ही उसको याद करने लगते हैं, आलोचना करते हैं । यह एस0 वाई0 एल0 का मामला कई सालों से लटका हुआ है । जब ताऊ मुख्यमंत्री था, तब उसने भी कोई बहुत कोशिश नहीं की । अगर वे कोशिश करते तो बहुत पहले ही हरियाणा के खेतों में एस0 वाई0 एल0 का पानी आया हुआ होता क्योंकि जब वे उप प्रधानमंत्री थे और उनका बेटा चीफ मिनिस्टर था, उस समय पंजाब में उनका पगड़ी बदल भाई मुख्यमंत्री था । अगर वह प्रयास करते तो बहुत जल्दी ही हरियाणा में इसका पानी आ सकता था । डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाऊस यह कहता हूं कि मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ही रावी व्यास का पानी एस0 वाई0 एल0 में ला सकते हैं बाकी सब देख लिए हैं । (विघ्न)

श्री सतबीर सिंह कादयान : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । उपाध्यक्ष महोदय, जब चौधरी देवी लाल जी उपप्रधानमंत्री थे, तब तो पंजाब में गवर्नर राज था जबकि ये पगड़ी बदल भाई का राज बता रहे हैं । चौधरी देवी लाल जी ने ही 80 प्रतिशत काम एस0 वाई0 एल0 का कराया था जबकि आज कुछ भी इस नहर का काम नहीं हो रहा है ।

श्री अमर सिंह धानक : डिप्टी स्पीकर साहब, 1977 में कौन था ? 1977 में तो देवी लाल जी ही थे । मैं 1977 की ही बात कह रहा हूं । ये तो अच्छी बात कहने पर इंटरफियर ही करते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये 1977 की ही बात कर रहे है तो उस समय उनका बेटा सी0एम0 कहां से आ गया ? चौटाला साहब तो उस समय सी0एम0 थे ही नहीं ।

श्री अमर सिंह धानक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ताऊ के बारे में कह रहा था कि वे पानी ला सकते थे । लेकिन वे पानी नहीं लाए । इसके अलावा, पिछली बार हरियाणा में रिकार्ड तोड़ फसल का भाव मिला है जिसकी वजह से किसान खुशहाल हुए हैं । किसानों को बहुत अच्छा भाव मिला, जबकि ताऊ के राज में ऐसे भाव किसानों को नहीं मिले । उपाध्यक्ष महोदय, अगर परमेश्वर की कृपा हो गयी तो इस बार भी रिकार्ड तोड़ फसल होगी और इसको रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी । इस साल हमारी रिकार्ड तोड़ पैदावार होगी (विघ्न) मैं इरीगेशन के बारे में बता रहा था कि पिछली बार ताऊ की सरकार में इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला थे । उस समय मई 1987 में, ताल्लू सिवाड़ा लिंक माईनर का एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** इसके लिए पैसा भी निकाल दिया गया था जो 49.45 लाख रुपया था और काम भी शुरू हो गया था लेकिन ताऊ की सरकार आने के बाद उस पत्थर को तोड़कर नहर में डाल दिया गया । यह माईनर नहीं बनायी गयी अगर बन जाती तो चार गांव सिवाजपुर, मंढावा और लोहासीजादू को पानी मिल जाता । इसके अलावा ताऊ के चार सालों के राज में भूरे माईनर, खानक माईनर, गैंडावास माईनर के जो पत्थर रखे गये थे इन पत्थरों का नामों निशान मिटा दिया क्योंकि कभी ये पत्थर नजर न आ जाएं । इन पत्थरों को तोड़कर नहर में डाल दिया । ये अगर कोई माईनर बनवा देते तो किसान सुखी हो जाते, पैदावार बढ़ती और वे लोग इनका गुणगान करते लेकिन इन्होंने इनको बनवाने के बजाए उल्टा काम किया । अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो पत्थर इन्होंने तोड़े हैं कम से कम अब उन्हें लगाकर उन नहरों पर काम शुरू करवा कर पानी चालू करवाया जाए ।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता साहब, आप बोलने के लिए कितना समय लेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री भागे राम गुप्ता) : सर, मैं बोलने के लिए दस मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । अमर सिंह जी, आप जल्दी ही खत्म करें क्योंकि आपका टाईम भी हो गया है ।

श्री अमर सिंह धानक : स्पीकर सर, ऐजूकेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कंवारी और जमालपुर में 1986-87 में बारह लाख इकतालीस हजार

[श्री अमर सिंह धानक]

प्रति बिल्डिंग के हिसाब से 24.82 लाख रुपये खर्च करके सरकार ने यह दोनों बिल्डिंग बनाई थीं अगर वह 10 जमा 2 बिल्डिंग बनकर तैयार हैं तो उनको 10 जमा 2 बनाया जाए । इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट के मामले में बसों के बारे में कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि सहूलियत बढ़ी है लेकिन बसों का पूरी तरह से इंतजाम नहीं है । बसें बढ़ाई जाएं और भिवानी डिपो में और अधिक बसें दी जाएं ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके । भिवानी जिले में सभी माईनर की टेल हैं खास तौर पर बवानी खेड़ा टेलों का हल्का है। मेरा सुझाव है कि इरीगेशन मिनिस्टर साहब इसको नोट करें । 121 बुरजी सुन्दर ब्रांच से 179 बुरजी तक हिसार डिवीजन में है । टेल और हैड एक डिवीजन में रखे जाएं ताकी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से हो सके । इससे 150 क्यूसिक जो टेलों का पानी है वह हैड वाले ले जाते हैं वह बवानी खेड़ा के हल्के का पानी है । इलैक्ट्रिसिटी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब से पॉवर मिनिस्टर साहब ने यह महकमा संभाला है काफी यत्न किया गया है काफी कोशिश की है । यदि बारिश न होती तो वे बिल्कुल विफल हो जाते, बारिश ने उनकी बचाया । उनकी मेहनत और भगवान की कृपा से किसान को काफी राहत मिली है । मेरी गुजारिश है कि गांवों में दीये की तरह से टिमटिमाती हुई बिजली है । थ्री फेज की लाइट सब जगह दी जाए जिससे चक्की चल सके । सिंगल फेज की लाइट तो दीये के बराबर है । जितनी देर हरियाणा में बिजली रहे तीन फेस की होनी चाहिए । गांव और शहर में कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए । पिछले दिनों मैं सिवानी के गांवों में गया था । खाना खाने के वक्त बिजली चली जाए तो बड़ी परेशानी होती है । मैं पॉवर मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से हो ताकि सभी को बिजली मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांड्ज का अपनी तरफ से समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ (सालहावास) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान किए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं फिर बजट को सदन में पेश किया जाता है । मैं जानना चाहूंगा कि जब हम बजट को पास करते हैं, क्या उसको चैक करते हैं कि कहां मिसयूटीलाइजेशन हुआ है, ठीक तरह से खर्च हुआ या नहीं हुआ ? वित्त मंत्री जी ने अपने बजट 'इकोनोमिक सर्वे आफ हरियाणा' में माना है कि टोटल 46.33 लाख मैनडेज होंगे लेकिन ये 31 दिसम्बर तक केवल 12.05 लाख मैनडेज ही क्रर पाए । मैं गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि 31 दिसम्बर तक आप 12.05 लाख मैनडेज कवर कर पाए हैं, बाकी तीन महीनों में 34 लाख मैनडेज कैसे क्रिएट करेंगे ? अगर 34 लाख क्रिएट कर भी दिये तो इस तरह से करने का क्या यूज होगा ? ट्रैक्टर के द्वारा मैनडेज खोदे जा रहे हैं, उसको चैक करना चाहिए । ट्रैक्टर से खोद कर मैनडेज बना देंगे । इसी तरह से फंड की एलौटमैंट अगर क्वार्टरली हो

तो उसका यूटीलाइजेशन हो सकता है। डिपार्टमैंट्स को निर्देश दिए जाते हैं कि 31 मार्च से पहले-पहले यह पैसा खर्च हो जाना चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि अफरा-तफरी में पैसा खर्च किया जाता है, पैसा फूंक दिया जाता है ताकि किसी तरह से पैसा खत्म हो जाये। इस तरह का प्रोविजन करने का क्या फायदा होगा ? क्वार्टरली, फंड डिपार्टमैंट वाइज पैसा दिया जाए ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो।

डिमांड नं0 3 होम के बारे में है। पुलिस का जो रवैया हमारे प्रति है या हमारा पुलिस के प्रति है, वह अच्छा नहीं है। पुलिस को गाली न सिखाकर अच्छी बातें सिखानी चाहिएं ताकि वे पब्लिक की सुरक्षा करें, समाज में अच्छा वातावरण पैदा करें। आज अगर मंत्री जी के लड़के सेफ नहीं हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा ? पुलिस का आदमी भी सेफ नहीं है तो ऐडमिनिस्ट्रेशन बरकरार कैसे रखा जा सकता है ? पुलिस को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के दौरान उनका अच्छा आचरण बनाया जाए ताकि समाज की सुरक्षा मेनटेन्ड रह सके।

स्पीकर साहब, आगे मैं डिमांड नं0 8 पर कहना चाहता हूं। यह डिमांड 18.00 बजे। बिल्डिंग्ज एंड रोड्ज की है। रोड्ज का यह हाल है कि हमारे यहां पर कोई भी रोड ठीक नहीं है। सारी सड़कों में गढ्ढे पड़े हुए हैं। सारी सड़कें बरबाद हैं और सारी टूटी-फूटी पड़ी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितना पैसा ऐजिंग के लिये खर्च किया जा रहा है, उस की बजाये सड़कों को चौड़ा करने पर खर्च किया जाये तो ठीक रहेगा। आज यह हो रहा है जो 8, 10 या 12 फुट की सड़कें हैं, उनके किनारों पर ईंटें खड़ी कर रहे हैं, यह बेकार में पैसा वेस्ट करने वाली बात है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बजाये उसी पैसे से, उन सड़कों को थोड़ा वाईडन कर दिया जाये तो ठीक रहेगा। सड़कों के टूटने का एक ही कारण है। हर गांव में, हर टाउन में या हर शहर में जहां-जहां पानी खड़ा रहता है, वहां से रोड्ज टूट जाती हैं। हमारे यहां पर कौसली में भी खड़े पानी की दिक्कत है। हो सकता है दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही दिक्कत होगी। रोड के साथ-साथ पानी के लिये चैनलज बननी जरूरी हैं ताकि पानी रोड्ज पर जाने की बजाये, उन चैनलज में से गुजर सके। इस समय सिस्टम यह है कि गांव की सड़कें तो पंचायत बनायेगी तथा शहर की सड़कें म्युनिसिपल कमेटी बनायेगी और दूसरा डिपार्टमैंट चैनलज बनायेगा यानी पी0 डब्ल्यू0 डी0 (पब्लिक हैल्थ) को चैनलज बनाने का काम दिया हुआ है। मेरा कहना यह है कि यह एक ही किस्म का काम है। रोड्ज को बनाने और उनको बरबाद होने से बचाने के लिये इस काम को एक ही डिपार्टमैंट को दे देना चाहिये।

अब मैं डिमांड नं0 10 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह डिमांड मैडीकल एंड पब्लिक हैल्थ के बारे में है। आप किसी भी हौस्पिटल में चले जाइये, वहां पर दवाईयां नहीं हैं, डाक्टर्ज नहीं हैं। पिछले दिनों मेरे हल्के के गांव जमालपुर में,

[चौधरी जिले सिंह जाखड़]

मुख्य मंत्री महोदय, सी0एच0सी0 की ओपनिंग सैरेमनी के लिये गये थे। वहां पर केवल एक डाक्टर एक कम्पाउंडर और 16 चपड़ासी हैं। आप ही देखें, क्लास-फोर के 16 आदमी हैं और डाक्टर केवल एक है। मेरा कहना यह है कि वहां पर आप डाक्टर्ज की संख्या को बढ़ायें। इस तरह से न करें कि चपड़ासी तो 16 लगा दें और डाक्टर केवल एक ही हो। वहां पर आप दवाइयां ज्यादा दें और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां भेजें। इतने ज्यादा चपड़ासी भर्ती करने का कोई फायदा नहीं है। आज भी उस सी0एच0सी0 के अन्दर कोई डाक्टर नहीं है। तनख्वाह तो उस डाक्टर की जमालपुर के बजट से ली जाती है लेकिन वह काम कहीं और जगह करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक तो आप अच्छी दवाइयां दें, और दूसरे जो वहां का डाक्टर आन डैपुटेशन कहीं दूसरी जगह पर काम कर रहा है, उसको वहीं पर रखा जाये। किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। पब्लिक हैल्थ का जहां तक ताल्लुक है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं। आज सरकार दावा तो करती है कि उसने 6739 गांवों को पीने का पानी दे दिया है, मगर इन गांवों में से केवल 10 फीसदी लोग ही ऐसे होंगे जहां पर वाटर सप्लाई के हैड हैं और वहां के लोग ही आपका पानी पीते होंगे। 10-20 फीसदी गांवों में ही पानी ठीक जाता होगा, लेकिन सब जगह नहीं। इल्लीगल कुनैक्शन्ज बहुत ज्यादा हैं जिनके कारण पानी टेल तक जाता ही नहीं है। हमारे यहां पर 1960-1962 से वाटर सप्लाई की स्कीम बनी हुई है। आज आबादी 15,000 के करीब पहुंच चुकी है और वाटर पाईप लाईन्ज बड़ी पुरानी पड़ी हुई थी। उन पाईप्स को बदला गया है और जो पुरानी पाईप्स निकाली गयी हैं, वह बेकार पड़ी हुई हैं। पानी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिये ही पाईप लाईन्ज बदली गयी हैं। जो इल्लीगल कुनैक्शन्ज दिये जा रहे हैं, उनको भी रोकना बड़ा जरूरी है ताकि पानी की कैपेसिटी जो बढ़ाई गयी है, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही लास्ट टेल तक पानी पहुंचाने का प्रबन्ध भी किया जाये। कैपेसिटी बढ़ाने के कारण जो पाईप लाईन्ज उखाड़ी गयी हैं और बेकार पड़ी हुई हैं, उसका किसी दूसरी जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। वह लोहे की पाईप्स हैं, मेरा विचार यह है कि उनको दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से जो पाईप्स उखाड़ी गयी हैं, उनको बरबाद न करके कुनैक्शन देने के लिये या कैपेसिटी बढ़ाने के लिये इस्तेमाल किया जाये। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो इन पाईप्स को नीलाम कर दिया जाये। जो पैसा वसूल होगा, उसको उस जगह की बहबूदी के लिये लगाया जाये।

एक आवाज : कहां की पाईप्स की बात कर रहे हो ?

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : मेरे इलाके कोसली में एक नंगल खेड़ा की स्कीम है, वह कम से कम 85 गांव की स्कीम है। उसमें से, कम से कम 20 गांवों की स्कीम में से, लोहे की पाईप लाईन उखाड़ी गयी है जो बेकार पड़ी हुई है। उन लोहे की पाईप्स

को किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है । यह मेरा सुझाव है । इसके अलावा, सरकार की एक और स्कीम है । जिन गांवों में मीठा पानी नहीं है, उन गांवों के जोहड़ों को बरसात के पानी से भरने की एक स्कीम है । उस स्कीम के तहत जोहड़ों की खुदाई के लिये सरकार 80,000 रुपया देती है ताकि पीने का पानी मिल सके । मेरे हल्के में एक खोरड़ा गांव है । वहां पर 5 एकड़ का जोहड़ है । वह तो बरसात के दिनों में भरता नहीं है लेकिन तीन जोहड़ और खोदने के लिये 80,000 रुपये के हिसाब से दिये गये हैं मातनहेल ब्लॉक में पैसे का बहुत ज्यादा मिसयूटीलाइजेशन हुआ है । अस्सी अस्सी हजार के इतने जोहड़ खोद दिए और वह सारा रुपया बरबाद हो गया । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हाउस की एक कमेटी बनाए और वह कमेटी वहां जाकर देखे कि वे जोहड़ वहां जरूरी भी थे या नहीं थे । अगर उस पैसे को ठीक ढंग से यूटीलाइज करते तो वह पैसा किसी और काम आ सकता था । जोहड़ खोदने की क्या जरूरत थी ? जब पांच एकड़ का एक जोहड़ बरसात के पानी से नहीं भरता तो तीन और जोहड़ खोदने का क्या फायदा है और वे क्यों खोदे गए ? जब पानी का कोई साधन नहीं है । बरसात का पानी वहां बह जाएगा और पशुओं को दो महीने पीने का पानी नहीं मिलेगा । इसलिए इस तरह की फिजूलखर्ची को रोका जाए ।

स्पीकर साहब, इस डिमाण्डज में एजूकेशन के लिए पैसा रखा गया है । मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हमारे यहां शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है । हमारे यहां 55.85 परसैन्ट लोग पढ़े लिखे हैं और पंजाब के अन्दर 58 परसैन्ट समथिंग पढ़े लिखे लोग हैं । स्पीकर साहब, ऐजूकेशन का बजट बढ़ाकर हम टीचर्ज की संख्या बढ़ा सकते हैं, टैक्नीकल स्कूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, टीचर्ज ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है । स्पीकर साहब, आज टीचर्ज की जो ट्रांसफर पौलिसी है वह हमारे लिए बड़ी भारी सरदर्द बनी हुई है । कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या कोई और सरकार हो या कोई भी शिक्षा मन्त्री हो, ट्रांसफर पोलिसी एक समस्या बनी हुई है । शहर के जे0 बी0 टी0 टीचर्ज आज किसी दूसरे जगह नहीं रहना चाहते । उनका कहीं और ट्रांसफर हो जाता है तो वे वहां नहीं जाते । एक महीने में एक दिन हाजिरी लगा देते हैं और तनख्वाह ले लेते हैं । हजारों लोग सैक्रिटेरिएट में चक्कर काटते रहते हैं । शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हम ट्रांसफर पौलिसी बना लें । उसी पौलिसी के तहत हम उनका ट्रांसफर करें हम ट्रांसफर पौलिसी ऐसी बना लें कि पांच साल तक किसी भी टीचर का ट्रांसफर नहीं होगा । ऐसा करने से हमारी सरदर्दी काफी कम हो जाएगी । आज शहर के आसपास के जो टीचर हैं वे दूर गांवों में जाना नहीं चाहते । अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है तो वे वहां नहीं जाते, इससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है । सरकार हर टीचर से पूछ ले कि वह कहां रहना चाहता है और उसकी मर्जी के मुताबिक उसका ट्रांसफर कर दिया जाए लेकिन उसके पांच साल के बाद तक कोई ट्रांसफर न किया

[चौधरी जिले सिंह जाखड़]

जाए । शिक्षा का स्तर सुधारने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता । इससे टीचर्ज भी संतुष्ट रहेंगे । स्पीकर साहब, डिमाण्ड नम्बर 13 सोशल वैलफेयर की है । सोशल वैलफेयर के अन्दर समाज कल्याण आता है । समाज कल्याण का मतलब है कि हम अपने समाज का कल्याण करें । स्पीकर साहब, आज हम अपने समाज का कल्याण नहीं कर रहे हैं । आज आंगनवाड़ी में लाखों बच्चों को खिचड़ी, खिलाने के लिए, दलिया खिलाने के लिए छोटे-छोटे बच्चों से अपने घरों से कटोरे मंगवाए जाते हैं । स्पीकर साहब, उनको खिचड़ी देना, अण्डे देना, दलिया देना, और गुड़ देना क्या यह कोई समाज कल्याण की स्कीम है ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर साहब, यह कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी में खिचड़ी बनती है । हमने अब आंगनवाड़ियों के लिए नई पॉलिसी निकाली है । हमने 'अंकुर' नाम की एक किताब निकाली है । यह किताब नर्सरी ट्रेनिंग के बारे में है । बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं । यह गल्त कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी में कोई काम नहीं होता ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : मैं तो यह कहना चाहता हूं, कि हाउस की एक कमेटी बनाकर उनका काम देख लिया जाए । हमारी पी० ए० सी० कमेटी ने इनको देखने का प्रोग्राम बनाया था लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ा । स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि आप कुछ फैमिलीज फिक्स कर लें, कुछ फैमिलीज आइडैन्टीफाई कर लें, जिन फैमिलीज को और जिस बच्चों को आपने देना है, उनकी आइडैन्टीफाई करें और उनको दें । मैं यह नहीं कहता कि आप न खिलाओ । सैन्ट्रल गवर्नमैंट का न्यूट्रीशन का प्रोग्राम है उसको आप यूटीलाइज करो । लेकिन अब हालत यह है कि उस मैटीरियल को कहीं भैंस खा रही है या कोई कट्टी खा रही है । बच्चों को नहीं मिल रहा है । कितना आता है और कितना जाता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है ? आप फिक्स करा दें कि एक परिवार के एक बच्चे को पचास ग्राम मिलेगा, सौ ग्राम मिलेगा या दो सौ ग्राम मिलेगा या दस ग्राम मिलेगा जिससे कि उनका कुछ भला हो सके ।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमाण्ड नम्बर 15 जो इरीगेशन की है, के बारे में कहना चाहता हूं । इरीगेशन के लिए मैं गुप्ता जी को कहूंगा कि इस मद में बहुत ज्यादा पैसा दिया जाए । यहां पर एस० वाई० एल० के पानी के बारे में झगड़ा है कि 3800 लाख एकड़ फीट पानी नहीं मिला या 3500 लाख एकड़ फीट पानी नहीं मिला । मैं तो यह कहूंगा कि 3800 की बजाए अगर 3600 मिल जाए तब भी ले लो । पचास साल हो गए और हम पानी की वजह से बरबाद हो रहे हैं । अगर अगले बीस साल भी पानी नहीं मिला तो वह भी सारा चला जाएगा । झगड़ा करने से क्या फायदा है ? फिजूल में लटठम लट्ठा हो रहा है । हमारे पास डब्ल्यू जे० सी० का, जमुना का दो तिहाई पानी है । हम उसको यूटीलाइज नहीं कर रहे

हैं और एस0 वाई0 एल0 पर लट्ठ बजा रहे हैं । उसका क्या फायदा है ? हथनी कुंड बैराज बनाओ ताकि ताजेवाला हैड का पानी मिल सके । दक्षिणी हरियाणा में बरसात में एक लाख एकड़ फीट पानी होता है और उसमें से पचास हजार या अस्सी हजार एकड़ फीट पानी वेस्ट चला जाता है । यह बात मन्त्री जी ने मानी है । उस पानी को यूज करने के लिए नहरों की डिसिल्टिंग कराकर दक्षिण हरियाणा के जिलों को भेज दिया जाए तो कम से कम वाटर रिचार्ज होकर पानी तो आ जाएगा । हमारे ट्यूबवैल्ज तो चल पड़ेंगे । अगर सरकार इन स्कीमों में भी पैसा नहीं लगाएगी तो कहां लगाएगी ? जब बरसात के दिनों में आपके पास पानी स्पेयर होगा तो जरूरत के दिनों में आप उस पानी को दे सकते है । स्पीकर साहब, एम0 आई0 टी0 सी0 और कांडा के अन्दर जो आप वाटर कोर्सिज बनाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे वाटर कोर्सिज जितने भी हैं वे बेकार पड़े हैं । उनके बनने के बाद से आज तक एक घूंट भी पानी उसमें नहीं चला है । बीस-बीस किलोमीटर लम्बे वाटर कोर्सिज बने पड़े हैं जिनमें एक घूंट भी पानी नहीं चल रहा है । आप सर्वे कराकर देख लें कि इन वाटर कोर्सिज में पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है । अगर कोई वाटर कोर्स पांच किलोमीटर लम्बा है तथा वह टूट गया और सरकार के पास उस पर लगाने के लिए पैसा नहीं है तो उसका क्या फायदा है ? इसलिए रिपेयर के लिए भी सरकार पैसा दे । रिपेयर के लिए कौन बैनीफिशयरी पैसा देगा और कौन पैसा इकट्ठा करेगा और कौन उसको बनाएगा । कौन उसकी रिपेयर करेगा ? इसलिये बजट में इसकी रिपेयर के लिए पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिये ।

इससे आगे मैं इरीगेशन विभाग का भी कुछ जिक्र करना चाहूंगा, इस में ड्रेनेज डिवीजन भी आता है । उसमें डोजर ट्रेक्टर केनज वगैरह और दूसरी तरह की बहुत सारी मशीनरी होती है जो यूंही पड़ी बरबाद हो रही है। 10-15 साल पहले हमारी साहलावास की ड्रेन बनी थी, पता नहीं वहां पर कितना लोहा यूंही बेकार पड़ा हुआ है । कोई उसकी सुध बुध नहीं लेता । मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वह वेस्ट मैटीरियल है, उसका कोई यूटीलाईजेशन नहीं है, उसको अगर कंडमड करार दे दिया गया है तो उसकी जल्दी से जल्दी नीलामी करवा दी जाए । आक्शन से जो पैसा सरकार को मिले, उसको दूसरे कामों पर लगायें । पी0 ए0 सी0 कमेटी का मैम्बर होते हुए हमने इस मुद्दे को एग्जामिन किया था लेकिन वह बात नहीं बनी । हमें बताया गया कि इस के लिये काफी समय लग जाता है । हमें समझ नहीं आता कि कोई चीज जो किसी काम की नहीं है, उसकी डिसपोजल में दो-दो, तीन-तीन महीने का समय कैसे लग जाता है ?

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है जिले सिंह जी । अब आप बैठें ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : सर, मैं एक दो मिनटों में अपनी बातें कह कर समाप्त करूंगा । मैं कह रहा था कि जो सामान वेस्ट होता है, यूटीलाईज नहीं हो पाता, कंडम होता

[चौधरी जिले सिंह जाखड़]

है, चाहे जीपें हों, ट्रैक्टर्ज हों, उनकी जल्दी ही आक्शन करवा दी जानी चाहिये ताकि उन से जो पैसा आए, उस का कहीं और सदुपयोग किया जा सके । अगर उन चीजों को समय पर कंडम करके आक्शन कर देंगे तो सही कीमत मिलेगी और अगर देर से आक्शन की जाएगी तो पैसा कम मिलेगा । इसलिये सरकार इस ओर विशेष ध्यान देवे ।

इससे आगे मैं डिमाण्ड नम्बर 17 के बारे में बोलना चाहूंगा । इरीगेशन में जो हमारी जमीन खराब हो रही है, उसकी ओर सरकार ध्यान दे । जैसे जेहलम, डब्ल्यू0 जे0 सी0 और जे0 एस0 पी0 के साथ जो पैरेलल जमीन पड़ी है, वह बर-बाद हो रही है । ऐसी जमीन लगभग 50–60 हजार एकड़ के करीब होगी, सरकार को ऐसी जमीन को जल्दी ही ठीक करवाना चाहिये । इससे किसानों का नुक्सान हो रहा है और सरकार का भी हो रहा है । रोहतक, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ की जो जमीन हैं, टीले पड़े हुए हैं, उनकी सरकार को लैवलिंग करनी चाहिये जहां पर न बरसात का पानी है और न ही ट्यूबवैलज का पानी है, उसकी लैवलिंग करवायी जाए ताकि किसानों को और ज्यादा जमीन जोतने के लिये मिल सके ।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा जहां तक स्टाफ का सम्बन्ध है जैसे एस0 डी0 ओज0 हैं, सर्किल आफिसर्ज हैं, इंस्पैक्टर्ज हैं उनको साल के 265 दिनों में एक घण्टा भी काम नहीं है ये सारे कोई कहीं बैठता है, कोई गांव में बैठता , कोई हैड क्वार्टर में बैठता है । अगर ये कोई काम करते हों, किसी किसान के खेत में कभी गये हों, उनको कुछ बताया हो, या किसी को कुछ नालिज हो तो सरकार बताए ऐसी बात नहीं है । बस महीने में एक दिन आए, टिकट लगाई और तनख्वाह ले गये । इनकी कुछ चैकिंग सरकार द्वारा होनी चाहिये । अगर ये किसानों के पास जाते हों तो उनको पता हो सकता है कि खेती क्या होती है इनको किसानों को पूरी तरह से मदद देनी चाहिये कि फसल खेती किस तरह से हो सकती है । अगर फसल खेत में बीमारी पड़ जाए तो इसके लिये क्या करना होगा लेकिन जब स्वयं को ही कुछ पता न हो तो ये किसानों को क्या बतायेंगे । इसलिये सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये ।

सरकार का इस तरह का स्टाफ यूंही बैठकर तनख्वाह ले रहा है इसलिये मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस सरप्लस स्टाफ को कहीं और जगह पर इस्तेमाल करे ।

इससे आगे मैं मार्किटींग बोर्ड का जिक्र करूंगा । इसमें मंडियां भी आती हैं । सरकार नई मंडियां बनाने जा रही है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे नई मंडियां बनाने की बजाये जो पहले की पुरानी मंडियां अधूरी पड़ी हुई हैं, पहले उनका काम खत्म किया जाए, उनको पूरा किया जाए, फिर नई मंडियों की ओर ध्यान

दिया जाए । इस तरह नई मंडियों की घोषणा करने का कोई लाभ नहीं होगा, जब तक पुरानी मंडियां इंकम्पलीट पड़ी हों । मेरे कोसली हल्के में एक मंडी पिछले 10-15 सालों से अधूरी पड़ी है और उसके नजदीक आस पास कोई दूसरी मंडी भी नहीं है । कोसली हमारा सैन्ट्रल प्लेस है। उस मंडी पर 5-7 लाख रुपया पहले लगाया गया है, वह बिल्कुल बेकार पड़ा है । इसलिये सरकार जो नई मंडियां बना रही हैं, उनकी तरफ ध्यान न दे कर पहले पुरानी मंडियों को पूरा करने पर ध्यान दे ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट विभाग का भी जिकर आया। मैं यह कहूंगा कि सामूहिक विकास का जो पैसा सरकार लगा रही है, उसका ठीक ढंग से यूटीलाईजेशन नहीं हो रहा है । उस पैसे को फिजूल में बरबाद नहीं किया जाना चाहिये ।

पहले मैंने यह जिकर किया था कि यूंही फिजूल में जोहड़ खोदे जा रहे हैं और वे ट्रैक्टर्ज के द्वारा खोदे जा रहे हैं, फिर उनके मेनडेज बना दिये जाएंगे । सब से पहली उस इलाके की यह डिमांड है कि वहां पर हमारी बहन, बहू-बेटियों के लिये बुजुर्गों के लिये लैट्रीन बनाई जाये । इसलिये सरकार को मेरा सुझाव है कि सरकार इसके लिये एक या आधा एकड़ भूमि अर्जित करके, चार दीवारी बना दे, यही सफीशीऐन्ट रहेगा ताकि लोगों को लैट्रीन वगैरह जाने के लिये कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े । यूंही फिजूल कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट के लिये पैसा लगाया जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं है । इसमें हम कामयाब नहीं हैं । बाद में सप्लाई भी कोई नहीं है जिससे इन लैट्रीनज को पानी के साथ कनैक्ट कर दें । इसलिये सरकार गांव में रहने वाली हमारी बहन, बहू-बेटियों व बुजुर्गों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए चारदीवारी करवा दे ताकि लोगों को सुख-सुविधा हो सके । ऐसा काम सरकार को तुरन्त ही करना चाहिये । (धन्यवाद)

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 2, 3, 8 15, 17, और 22 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । स्पीकर साहब, सदन में इरीगेशन की डिमांड पर चर्चा की गई । मैं उस जगह से संबंध रखता हूं, कई बार सदन में चर्चा हुई कि जिला फरीदाबाद को नहरी पानी देने के बारे में सरकार का बिल्कुल इरादा नहीं है । बार-बार हमारे उस जिले के दूसरे माननीय सदस्यों ने भी सदन में चर्चा की है । जिला फरीदाबाद में जो आगरा नहर है, उसमें से हरियाणा को अपने हिस्से के तौर पर पानी मिलता है । आज उस नहर में पहले से ज्यादा पानी आता है । अगर हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से उसका कन्ट्रोल लेने के बारे में फिलहाल बात नहीं कर सकती है तो उस पानी का हिस्सा बढ़ाने की बात तो कर सकती है । अगर ऐसा हो जाए तो जो पानी बढ़ेगा, उस को गुड़गांव कैनाल में डाल कर हम न सिर्फ फरीदाबाद जिले को बल्कि गुड़गांव के मेवात के इलाके में भी पानी दे सकते हैं ।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

जिला फरीदाबाद के जितने उद्योग और दिल्ली के उद्योग हैं तथा दिल्ली का जितना सीवरेज का गंद है, वह सारा आगरा और गुड़गांव नहरों में चला जाता है । उस पानी मे बहुत ज्यादा बदबू आती है । जहां जहां से ये नहरें गुजरती हैं, वहां पर बदबू के मारे लोगों का जीना दूभर हो गया है । उस गन्दे पानी की वजह से लोगों की सेहत पर असर पड़ा है । मैं चाहता हूं कि इनका पर्यावरण महकमा उस गन्दे पानी को रोके । आज पर्यावरण के नाम पर यह सब से बड़ा मजाक है । फरीदाबाद को केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि नौर्थ इंडिया का उद्योग सैन्टर कहा जाता है । हरियाणा सरकार ने पर्यावरण अदालतें बनाने का जिक्र किया । यह अदालतें एक हिसार में, एक अम्बाला में तथा एक और किसी जगह बनेगी । जबकि उस अदालत का हकदार फरीदाबाद जिला था क्योंकि उद्योगों की सब से ज्यादा गन्दगी फरीदाबाद में है । इसके अलावा हमारे पलवल के इलाके में सड़कों की बहुत बुरी हालत है । हम जहां भी बोलते हैं तो हमारे मन्त्री और आदरणीय मुख्य मन्त्री हमारे साथ इस तरह से पेश आते हैं जैसे हरियाणा प्रदेश में इनका ही हक है, सदन में भी केवल इन्हीं का हक है, हमारा कोई हक नहीं है । हमें झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है । चौधरी भजन लाल ने फरीदाबाद से एम० पी० का इलैक्शन लड़ा था । इन्होंने लोगों को कहा था कि अगर मैं सांसद बन गया तो मैं जिला फरीदाबाद को इंग्लैंड बना दूंगा । (विघ्न) आज हालत यह है कि प्रदेश में 110 ए० एस० आई० की भर्ती हुई । स्पीकर साहब, हमारे फरीदाबाद जिले के शायद ही किसी बच्चे का नाम उस लिस्ट में हो । प्रदेश में कोई भी नौकरी निकलती है तो उसके लिए या तो हिसार के लड़के लिये जाते हैं, या कालका के लिए जाते हैं । स्पीकर साहब, कोई भी स्कीम या तो कालका के लिए बनती है या हिसार के लिए बनती है । फरीदाबाद के लिए कुछ नहीं होता । हमारे मुख्य मन्त्री जी को फरीदाबाद से 50 लाख रुपए महीने की कमाई है ।

चौधरी भजन लाल : क्या कहा आपने यह दोबारा बता दें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : फरीदाबाद में जो ट्रक यूनियन है, उसको मुख्य मन्त्री ने अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ है । वहां के डी० सी० और एस० पी० को इन्होंने आदेश दे रखे हैं कि चाहे जिला प्रशासन चले या न चले, मुख्य मंत्री को उस यूनियन से 50 लाख रुपये पहुंच जाने चाहिएं । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात कही है उससे घटिया बात कोई आदमी कह नहीं सकता, सदन के मैम्बर को ठीक बात कहनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, अगर ये इस बात को साबित कर देंगे, तो मैं अस्तिफा दे दूंगा या फिर ये अस्तिफा दे दें । जैसा इन्सान होता है वह वैसी ही बात करेगा । इनको इस तरह के बेहूदा

एलीगेशन लगाने का कोई लाईसैंस नहीं मिला हुआ है । * * * * * * * । यह कोई तरीका है । ऐसी गलत बात कहने का इनको कोई लाइसैंस नहीं मिला हुआ है । (शोर)

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने जो शब्द कहे हैं वे रिकार्ड पर नहीं आने चाहिए । (शोर)

श्री अध्यक्ष : ठीक है वे शब्द रिकार्ड पर न आएं । (शोर)

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वे शब्द मुख्य मन्त्री जी को वापिस लेने चाहिएं । (शोर)

श्री अध्यक्ष : उन शब्दों को रिकार्ड से निकाल दिया गया है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । विधान सभा के माननीय सदस्यों को सदन में प्रवेश करते ही सामने खम्बे पर जो बात लिखी हुई है, उसको पढ़ लेना चाहिए । माननीय सदस्य दलाल साहब बार बार सदन में गलत बात कहते हैं । इनका यह कोई तरीका नहीं है । (शोर)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाएं । (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल ने जो राज्यपाल महोदय के बारे में कोई बात कही थी, उस के बारे में आज सुबह मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ आपको एक प्रिविलेज मोशन दिया था जबकि गवर्नर साहब के कंडक्ट के बारे में असैम्बली के अन्दर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती । जब इस बारे में दलाल साहब से एफेडेविट देने के लिए कहा गया तो मुकर गए । अगर ये सच्चे होते तो एफेडेविट देते । आप समझदार आदमी हो, विधायक हो और जिम्मेदार आदमी हो आप एफेडेविट देते । अगर आप सच्चे हैं तो एफेडेविट देते । आप अब भी एफेडेविट दें हम अब भी तैयार हैं । इस तरह से गलत बोलने से क्या फायदा । यह आपका कोई तरीका नहीं कि हर टाईम गलत एलीगेशन लगा दो। (शोर)

श्री राम रतन : स्पीकर साहब, मुझे भी अपनी कुछ बातें कहनी हैं । मुझे भी अपनी बात कहने का हक है । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने के लिए पांच मिनट का टाईम दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हमारे जिले के लोगों के साथ हर मामले में यह सरकार भद्दा मजाक कर रही है । हमारे वहां पलवल, बल्लभगढ़, होडल

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

के लिए जो पहले आई0 एस0 बी0 टी0 से बसें चलती थीं, वे अब बन्द कर दी गई हैं । अब कोई कालेजों अड्डा बनाया गया है वहां से ये बसें चलती हैं, जो आई0 एस0 बी0 टी0 से 12 कि0 मी0 दूरी पर पड़ता है । जो सवारियां चण्डीगढ़, रोहतक या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाना चाहती हैं, उनको आई0 एस0 बी0 टी0 से बसें पकड़ने के लिए काफी परेशानी होती है । मेरी सरकार से मांग है कि हमारे एरिया में जो बसें पहले आई0 एस0 बी0 टी0 के लिए चलती थीं, अब भी वहीं से चलनी चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी मांग है कि हमारे एरिया में बिजली के खम्भों की काफी कमी है । खम्भे न होने की वजह से बांस के डण्डों पर तारें नंगी लगी हुई हैं, उनके गिरने से कई बार जानवर और इन्सान के जीवन को खतरा बना रहता है । मेरी मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी बिजली के खम्भों को भिजवाने का प्रबन्ध करे ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठें । आपको पहले ही काफी समय मिल गया है । अब श्री रामरतन जी बोलेंगे ।

श्री राम रतन (हसनपुर एस0 सी0) : स्पीकर साहब, मैं आपके ध्यान में और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दलाल साहब इस्तीफे की बात कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सैशन में भी मैंने इस्तीफा दिया था । ये दलाल साहब जो हैं, ये पहले इस्तीफा दें । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप डिमांडज पर बोलें ।

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि जब से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तब से हरियाणा में काफी विकास के काम हुए हैं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं0 1 से 7 पर बोलना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, तबसे हरियाणा में काफी विकास के काम हुए हैं । मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि हमारा जिला काफी पिछड़ा हुआ है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का टाईम 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब की दुकान मार्किट कमेटी, पलवल में है । इनकी दुकान के बाहर दो पेड़ शीशम के खड़े थे जिनकी कीमत कम से कम 20 हजार रुपये होगी । उन दोनों पेड़ों को ये लोग काट कर ले गए थे और अब वहां शीशम के पेड़ नहीं हैं । (शोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, अगर यह बात झूठी हो तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । चौधरी कर्ण सिंह जी भी इस्तीफा दे दें और मैं भी अपना इस्तीफा लिख कर आपको दे देता हूं । अगर मेरी बात झूठ हो तो मेरा इस्तीफा मन्जूर कर लिया जाए । (विघ्न एवं शोर) अगर मेरी बात सच साबित हो जाए तो इनका इस्तीफा मन्जूर कर लेना चाहिए । (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : शीशम के ये पेड़ कितना टाईम पहले काटे गए हैं ? (विघ्न एवं शोर)

श्री राम रतन : ये पेड़ करीब 2 महीने पहले ही काटे गए हैं । पलवल में कालोनी के अन्दर इनकी कोठी बन रही है । उन शीशम के पेड़ों को काट कर ले गए हैं और उनसे वहां पर किवाड़ बनाए जा रहे हैं । (विघ्न एवं शोर) अगर यह बात गलत हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । (विघ्न एवं शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम रतन जी, आप बैठिए । कर्ण सिंह जी, आपका प्वायंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री राम रतन जी ने सदन में कही है, वह बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, मेरी कोई दुकान पलवल मार्किट कमेटी में मेरे नाम से नहीं है और न ही मैंने शीशम या कीकर का कोई पेड़ काटा है । ये बेबुनियाद बात यहां पर कह रहे हैं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमान जी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का व्यवहार सदन की मर्यादा के खिलाफ है । ये श्रीमान जी सदन के किसी मिनिस्टर के माध्यम से या राम रतन जी के माध्यम से चाहे जो भी कहलवा ले, लेकिन ये मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हैं । मैं अपनी बात कहूंगा और इनके इस प्रकार रोकने से नहीं रुकूंगा । (विघ्न एवं शोर)

श्री राम रतन : स्पीकर साहब, मैंने शीशम के पेड़ का जिक्र किया है, कीकर के पेड़ का मैंने नाम नहीं लिया । हो सकता है इन्होंने कोई कीकर का पेड़ भी काटा हो लेकिन मैंने सिर्फ शीशम के पेड़ की ही बात कही है । (विघ्न एवं शोर) शीशम के पेड़ इनके भाई ने काटे हैं, मार्किट कमेटी, पलवल के लोगों को इस का पता है। स्पीकर साहब, आप हाउस की कमेटी बना कर सर्वे करवा लें । (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए काफी टाईम ले लिया है और टाईम काफी ज्यादा हो गया है । हमने कट मोशन दिया है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कट मोशन पर बोलने के लिए हमें समय मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : डिमांड फार ग्रांट्स के लिए जितना टाईम ऐलोट होगा आपकी पार्टी के सदस्यों के हिसाब से आपको टाईम जरूर देंगे । (विघ्न) जितना टाईम रूलिंग पार्टी को मिलना है उतना उनको मिलेगा और पार्टी की रेशो के मुताबिक आपकी पार्टी को टाईम मिलेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं भी डेढ़ लाख वोटों से चुन कर हाउस में आया हूं और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए परन्तु अपनी बात को बार-बार रिपीट न करें ।

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम रतन जी, आप रिपीट न करें अगर कोई और बात आप कहना चाहते हैं तो कहिए या अपनी सीट पर बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । आज की सरकार ने शिक्षा में नकल को रोकने के लिए काफी प्रयास किए हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में दस जमा दो के स्कूल नहीं हैं और जो हैं भी, वह 15 किलो-मीटर दूर हैं । .....

श्री अध्यक्ष : राम रतन जी, आपका टाईम हो गया है, अब आप बैठ जाएं । बंसी लाल जी क्या आप बोलना चाहेंगे ?

चौधरी बंसी लाल : जी हां ।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, ये तो बोल चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने थोड़ा सा बोलना है । आप पहले इनको बोलने दें ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्ड नं 2,3,15,17 और 24 पर बोलना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए खेतों में जो दवाईयां छिड़कने के लिए मिलती हैं उन का कीड़ों पर कोई असर नहीं होता । पिछले दिनों मैं सिरसा गया था, वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि कपास पर छिड़कने के लिए जो दवाई दी गई है, वह बेकार है, उसका कीड़ों पर कोई असर नहीं पड़ता । लोगों ने ककोरे में दवाई डाल कर उसमें कीड़े डाल दिये लेकिन वे कीड़े मरे नहीं, बल्कि ऊपर तैरने लग पड़े । वह दवाई पानी की तरह है ।

अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें अलग से मार्किटिंग बोर्ड बनाता है, वह डुप्लिकेट काम हो जाता है । अध्यक्ष महोदय, पहले भी यह होता था कि मार्किटिंग बोर्ड, पी डबल्यू० डी० डिपार्टमैंट को काम दे देता था । मार्किटिंग बोर्ड वाले जो सड़कें बनाते हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती , उनके पास टैक्नीकल नौ-हाऊ नहीं होते । मेरा सरकार को सुझाव है कि मार्किटिंग बोर्ड का पैसा पी० डबल्यू० डी० को दे दिया जाए ताकि अच्छी सड़कें बनें ।

अध्यक्ष महोदय, अब गर्मी आ रही है । खासकर मेरे जिले में पानी की किल्लत होगी । इस तरह से रोहतक, सोनीपत, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी पीने के पानी की किल्लत आएगी । क्या सरकार इसके लिए पहले से ही प्रबन्ध करेगी क्योंकि एक महीने के अन्दर अन्दर गर्मी आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय, जिला हिसार में फर्जी खाद सप्लाई हो रही है । यह खुद मुख्य मन्त्री जी का जिला है । वह गौरखपुर गांव और भूना के इलाके मोजी, गैमउनपुर, और चौबारा में कई जगह पर खाद के नमूने लिए गए थे लेकिन वह खाद गलत निकली थी और ठीक नहीं थी । अगर ऐसी खाद किसानों को दी जाएगी तो किसानों का बहुत नुक्सान होगा । अध्यक्ष महोदय, मेरी इत्तलाह के मुताबिक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अखबार में बयान दिया था कि दो सौ से ज्यादा नमूने फेल हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं जे० एल० एन० के बारे में कहना चाहूंगा । जे० एल० एन० कैनाल पर डिच ड्रेन जल्दी से जल्दी बनाए जाएं । अगर यह नहीं बनाई गई तो सोनीपत और रोहतक जिले के गांवों की हालत बहुत खराब हो जाएगी क्योंकि इनके दोनों तरफ 4-5 एकड़ जमीन में पटेरा खड़ा हो गया है और वह जमीन कल्लर बन गई है । इसलिए सरकार को डिच ड्रेन जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए । जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है, इसके लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, इस बारे में कुछ पता नहीं है और न ही कुछ कहा जा सकता है । मैं जगह जगह पर जाता हूं और पूछता हूं कि क्या नहरों की डी-सिल्टिंग

[चौधरी बंसी लाल]

हुई है तो किसी ने भी यह नहीं कहा कि हां डी-सिल्टिंग हुई है । अध्यक्ष महोदय, नहरों की डीसिल्टिंग होनी चाहिए । आज पहले ही पानी की दिक्कत है । अगर टेल पर पानी नहीं पहुंचेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय दस मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय दस मिनट और बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो राई के कम्पलैक्स के लिए पैसा रखा गया है, वह बहुत ही कम है, ज्यादा पैसा रखना चाहिए ताकि इस कम्पलैक्स को जल्दी डिवैल्प किया जा सके । इसके साथ ही रोहतक के पास जो तलयार लेक है, वहां पर हर संडे को दिल्ली से लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए इसको भी ऐक्सटैन्ड करना चाहिए । वहां पर मोटल भी बनाया जाए ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके । ऐसा करने से सरकार को आमदनी भी होगी और स्टेट का नाम भी ऊंचा होगा । इसके अलावा, धारुहेड़ा कम्पलैक्स में भी अकमोडेशन की कमी आ गयी है क्योंकि जयपुर आने जाने वालों का ट्रैफिक बहुत है इसलिये इस कम्पलैक्स को भी बढ़ाना चाहिए । इसके अलावा डैपेचिक जो होडल के पास है, बहुत अच्छा नहीं है, वहां भी अकमोडेशन की कमी है, इसलिये अकमोडेशन बढ़ायी जाए । रैस्टोरेंट की जगह पर पीने के पानी का प्रबन्ध बढ़िया किया जाए । आजकल लोग यू० पी० में चार पांच किलोमीटर की दूरी पर, कोसी में ठहर जाते हैं लेकिन हमारे यहां नहीं ठहरते, इसलिये सरकार को वहां पर भी अच्छा प्रबन्ध करना चाहिये । रिवाड़ी के टूरिस्ट कम्पलैक्स में भी पीने के पानी का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए और ठहरने के लिए ज्यादा से ज्यादा अकमोडेशन होनी चाहिए । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज यह है कि वहां पर जो तकिये मैटरसिज बैड शीट्स, बैड कवर्ज हैं, वे पुराने हो गये हैं । अगर उनको हटाकर देखते हैं तो वे बिखरने लगते हैं, इसलिए सरकार उनको रिप्लेस करे ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि टूरिज्म के लिए जो 3,20,00,000 रुपया रखा है, यह बहुत ही कम है । सरकार को कम से कम 15 करोड़ रुपये रखने चाहिये थे ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहूंगा । पुलिस का मोरल बहुत ही नीचा है क्योंकि डी0 जी0 पी0 नीचे वाले स्टाफ की तकलीफों का ध्यान नहीं करता । पुलिस का ढांचा अच्छी तरह नहीं चल रहा । ला एण्ड आर्डर में गड़बड़ है । ला एण्ड आर्डर में गड़बड़ क्या है यह तो बिल्कुल है ही नहीं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए कहूंगा कि जो डी0 जी0 पुलिस लगा हुआ है, वह कभी कभी पंचकूला रैस्ट हाऊस में रहता है लेकिन परमानेंटली दिल्ली में रहता है । कभी वह चण्डीगढ़ में या पंचकूला में रहता है, कभी दिल्ली में । उससे कहें कि या तो वह यहां का काम कर ले या दिल्ली का काम कर ले । इनको उसकी जगह पर किसी और अफसर को लगा देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट के व्हीकल्ज का भी बहुत मिसयूज होता है । चाहे सब्जी लानी हो चाहे कहीं और ले जाना हो, चाहे मुख्य मन्त्री जी को कहीं जाना हो तो काफी गाड़ियां उनके साथ चलती है । तो मैं सरकार को इसके बारे में सलाह दूंगा कि ऐसी जगहों पर एक ही गाड़ी तीन चार अफसरों को लेकर जाए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गाड़ी एक ही अफसर को लेकर जाए । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, जो गुड़गांव जिले में 80–90 एकड़ जमीन की चर्चा आज सुबह हुई है, अगर उस जमीन पर टूरिज्म कम्पलैक्स बना दिया जाए, रेसकोर्स बना दिया जाए, गोल्फ क्लब बना दिया जाए या फिर टूरिज्म की कोई दूसरी चीज बना दी जाए तो मैं समझता हूं यह बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यह जगह दिल्ली के दरवाजे पर इन्दिरा गांधी ऐयरपोर्ट के साथ ही है । इससे सरकार को कम से कम बीस या तीस करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है । सरकार इस जमीन को चाहे ऐक्वायर करे या कुछ भी करे, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमैंट से वापस न ले । अगर वह जमीन वापस ले ली है तो उनको वापस देकर वहां पर टूरिस्ट का कम्पलैक्स डिवैल्प करे ताकि स्टेट को फायदा हो सके और स्टेट का नाम ऊंचा हो सके । अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट की मशीनरी का मिसयूज तो बेहद ही है । एक एफ0 आई0 आर0 नं0 307, दिनांक 11–11–93 संगरिया मंडी में दर्ज हुई है । वहां पर इसके लोग बूथ कैप्चरिंग करने गये थे लेकिन वे खुद ही कैप्चर हो गये। अध्यक्ष महोदय, यह कोई अच्छी बात नहीं है । इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद की खानें हैं, अगर उन सबको नेशनेलाईज कर दें तो सरकार को ज्यादा फायदा होगा । आज उन खानों से नाजायज तौर पर पत्थर निकालकर बेचा जाता है जिसकी वजह से सरकार की आमदनी कम हुई है । और यह जो गुड़गांव और फरीदाबाद जिले में, पंचायतों की, गांवों की जितनी जमीनें नीलाम हुई हैं, उन सबकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए ताकि पता लग सके कि वह सारी जमीनें ठीक नीलाम हुई हैं या नहीं ? नीलामी की खबर अखबार में महीने या दो महीने में एक बार छपती है, लेकिन इसकी आक्शन नहीं होती, किसी आफिसर के घर के ऊपर नीलामी हो

[चौधरी बंसी लाल]

जाती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए। आजकल बड़ी तेजी से एक धारा चल रही है, मुख्य मन्त्री जी ने एक नयी प्रथा चलाई है कि मंत्रियों को कारें भेंट हों, एम० एल० ए० को कारें भेंट हों, तोहफे भेंट हों। यह जो इस तरह का धन्धा चल रहा है यह ठीक नहीं है। धक्के से चंदा वसूल होता है। 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। मैं उनके नाम लेकर बदमगजी पैदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि चंदा वसूल करने में सरकारी मशीनरी का मिसयूज न किया जाए लेकिन मिसयूज होता है। अध्यक्ष महोदय, एक कमिश्नर इन्होंने रोहतक में लगा रखा है वह चार सौ या पौने चार सौ रुपये में वी० डी० ओ० के थ्रू कैसिट और किताबें बेचता है उसकी आप कनाट प्लेस में कोई दुकान खुलवा दो, वहां बेच लेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी चीजों पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और अब भी खुलासा तौर से कह देता हूं कि मुख्य मन्त्री जी के अपने शहर में, 2 अक्तूबर, 93 को, महात्मा गांधी जी, की स्टैच्यू पर माला डालने गए शराब बंदी आन्दोलन के कार्यकर्ता शांति से अपना आन्दोलन चला रहे थे। मुख्य मन्त्री जी ने हिसार तो दरकिनार, रोहतक तक गिरफ्तारियां करवा दीं। इससे उनकी हिसार की फैक्टरी को तो कोई खतरा नहीं था। शराब के खिलाफ आन्दोलन का तो आपको भी समर्थन करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, बातें तो और भी बहुत सारी कहनी हैं लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। (धन्यवाद)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल ने डी०जी०पी० के बारे में कहा कि डी०जी०पी० रहते रैस्ट हाउस में हैं और घर दिल्ली में हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में उनके बच्चे पढ़ते हैं, आफिसर को दिक्कत हो सकती है। जितना काबिल, जितना शानदार डी०जी० हरियाणा का है, उतना देश में किसी भी प्रदेश का नहीं है। ला एण्ड आर्डर जितना शानदार हरियाणा में है, उतना किसी भी प्रदेश में नहीं मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठ जाइए। कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं।

चौधरी भजन लाल: क्या आपके बारे में कुछ कहा है? डी०जी०पी० के बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, डी०जी०पी० के बारे में पिछली बार भी इन्होंने कहलवाया, यह ठीक बात नहीं है। अच्छे आफिसर की तारीफ करनी चाहिए। कोई गलत काम करते हों, बेईमान हों तो कहें, फिर हम भी मानेंगे (विघ्न)।

चौधरी बंसी लाल: मैं तो कहूंगा कि वह इनकंपिटैंट है।

चौधरी भजन लाल : आप के कहने न कहने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो आपका और मेरा एक ही जिला था । आपने छांटकर बढ़िया एस० पी० हिसार में लगाया हुआ था । ये वही डी०जी०पी० हैं ।

चौधरी बंसी लाल : ये जरूरी तो नहीं कि जो आदमी आज से 15 साल पहले अच्छा था वह आज भी अच्छा हो ?

चौधरी भजन लाल : एक तो अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कमिश्नर का नाम लेकर यह कह दिया कि वह कैसेट बेचता है । यह बिल्कुल सच्ची बात नहीं है वह कमिश्नर इनके जिले का श्री के०सी० शर्मा है । वह बहुत ही बढ़िया शानदार और ईमानदार अफसर है । कोई इन्होंने उसको गलत काम कह दिया होगा, उसने किया नहीं होगा । चौधरी बंसी लाल का एक सुख है कि शेर एक मिनट लगाता है लड़ने में । एक मिनट की भी टाल नहीं करता । यह इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है । यह क्वालिटी भी किसी किसी आदमी में ही मिलेगी (हंसी) दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कह दी कि गवर्नमैंट मशीनरी का संगरिया में बहुत मिसयूज किया गया । यह बात इन्होंने पहले भी कही है पता नहीं, इनको क्या फोबिया हो जाता है । ऐसी बात कहने का गवर्नमैंट मशीनरी मिसयूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अभी फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है । इसलिये यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाये ।

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय 10 मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : मैं तो अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा । बाकी तो गुप्ता जी ने 10 मिनट के लिये बोलना है, वे आपसे बात करेंगे । आप जानते हैं, कोई भी अधिकारी इलैक्शन के दौरान छुट्टी ले कर

[चौधरी भजन लाल]

जा सकता है। राजस्थान और हरियाणा के लोगों का आपस में मेल जोल है रिश्तेदारियां हैं। हम उनकी मदद के लिये जाते हैं और वह हमारी मदद के लिये आते रहे हैं। लेकिन सरकारी मशीनरी का मिसयूज कहना, कोई मुनासिब बात नहीं है। एक बात इन्होंने फरीदाबाद की खानों के बारे में कही है। पहले वहां से इन्कम 9 करोड़ रुपये की थी लेकिन अब इन्कम 16 करोड़ से भी ऊपर हो रही है। इसलिये कोई गड़बड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी बंसी लाल: इनको नैशनेलाईज कर दो। नैशनेलाईज कर दोगे तो इन्कम 50 करोड़ होगी।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने नैशनेलाईज करके भी देख लिया है। एक बात इन्होंने पंचायत की जमीन के बारे में कही है कि नीलामी ठीक नहीं हुई या उसमें कुछ कमी रही है। पंचायत प्रस्ताव पास करने के बाद ही बाकायदा ओपन आक्शन से जमीन को नीलाम करती है। जब भी कोई आक्शन पंचायत की जमीन की होती है तो सारी पंचायत से प्रस्ताव पास होता है तब वह नीलामी होती है। जब वह नीलामी छूटती है तो अगर अच्छा भाव होता है तो उस जमीन को पंचायत बेच सकती है, वरना वह टाल भी कर सकती है। कोई प्राईवेट आदमी जब अपनी जमीन बेचता है और अगर उस को कोई दूसरा आदमी लेना चाहे तो सरकार उसमें क्या दखल दे सकती है? इसी तरह से पंचायत अगर कोई जमीन बेचना चाहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर ओपन आक्शन में पंचायती जमीन आक्शन न हुई हो तो बतायें। हां, अगर कोई शिकायत हो तो ये लिख कर भेज दें, हम उसकी जांच करवा सकते हैं। एक बात इन्होंने यह कही कि मंत्रियों को और एम0एल0एज0 को कारें दी जाती हैं। अगर किसी हल्के के लोग उनके भले के काम के लिये ऐसा करते हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? यह प्रथा तो चौधरी बंसी लाल ने ही डाली हुई है। इनके खुद के जमाने में स्टेज पर एम0एल0एज0 को कारें भेंट की जाती थी इसके लिये सरकारी मशीनरी चन्दा इक्ट्ठा करती थी। (व्यवधान शोर)। मैंने यह कहा है कि आपके जमाने में तो एम0एल0ए0 को कार स्टेज पर भेंट होती थी -

चौधरी बंसी लाल: कब हुई है, यह भी जरा बता दो?

चौधरी भजन लाल: वह भी हम आपको बता देंगे। एक बात और होती थी सरकारी मशीनरी की बाकायदा डियूटी लगती थी। जो जलसे होते थे, उनमें पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक और एक सिपाही से लेकर एम0पी0 तक की डियूटी लगती थी। लेकिन हमने किसी भी आदमी की डियूटी नहीं लगायी है। हमारे जलसों में तो आदमी अपने आप ट्रैक्टरों में, बसों में या पैदल चल कर आते हैं। इस लिये किसी भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी बंसी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मुख्य मन्त्री ने मेरे ऊपर एक इल्जाम यह लगाया था कि यू०पी० में सरकारी मशीनरी लगाकर मैंने जलसे किये थे । यह आरोप निराधार और बे बुनियाद है ।

चौधरी भजन लाल : मैंने तो यू०पी० का नाम नहीं लिया है, मैंने तो हरियाणा का नाम लिया है । हरियाणा ही आपके लिये फालतू पड़ता है ।

चौधरी बंसी लाल : मैंने कभी हरियाणा में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया । यह तो अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन दिनों से आप भी देख रहे होंगे और आप ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि बसों में काली पैंट पहन-कर जो जाते थे या काली चुन्नियां ओढ़ कर जाती थी या काली जुराबें पहन कर जाते थे, उनको बसों से उतरवा देते थे । कोई भी आदमी काला कपड़ा पहन कर नहीं चल सकता इनके जलसों में काला कपड़ा पहन कर कोई नहीं आ सकता है ।

चौधरी भजन लाल : ये तो हरेक को ऐसा ही समझते हैं । ये आप करते थे, वैसा ही सोचते हैं कि भजन लाल भी करता होगा । लेकिन ऐसा कुछ नहीं है । मैं आपकी तरह से नहीं करता । डाक्टर मंगल सैन जी की पार्टी का मैम्बर यहां पर बैठा नहीं है । वे बड़े ही सीनियर लीडर थे । लेकिन उस आदमी को इन्होंने बोरी में बन्द करके पिटवाया था । चौधरी बंसी लाल जी आप अपने पर्चे उखड़वाना क्यों चाहते हो ।

चौधरी बंसी लाल : आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर । यह बेबुनियाद इल्लजाम है । मुख्य मन्त्री को सच बोलना तो आता ही नहीं है । इनकी मजबूरी भी है, इनको सच बोलना तो आता ही नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : चलो, स्पीकर साहब, मैं बात को यहीं खत्म करता हूं ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री धर्मपाल द्वारा—

श्री धर्मपाल सिंह : आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन । अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री छतर सिंह चौहान ने कहा कि दादरी में अधिकारियों ने जलसे के लिये चन्दा इक्ट्ठा करके दिया और गाड़ी दी, यह बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं और गलत बात है । किसी भी अधिकारी को मैंने चन्दे के लिये नहीं कहा और न ही किसी व्यापारी को कहा । यहां तक की मैंने किसी को टेलीफोन पर भी किसी तरह के चन्दे के लिये नहीं कहा । मैंने इस बारे में कोई बात तक

[श्री धर्मपाल सिंह]

नहीं की है। अगर कोई इस बात को साबित कर दे तो मैं बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। अगर यह बात साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। माननीय सदस्य ने जो इस तरह का ऐलीगेशन लगाया है, यह बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। इनका यह कहना कि दादरी के जलसे में पुलिस ने लोगों को पीटा या काले कपड़े उतरवाए। यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग यह भी कहते थे कि विधायक धर्मपाल को गांव के लोग घुसने नहीं देते और जलसे में एक भी आदमी नहीं आएगा जबकि छः तारीख को जलसे में यह हालत थी कि मुख्य मन्त्री के सम्मान में जनसभा में इतने लोग आए कि आज तक दादरी में किसी भी नेता के सम्मान में और किसी भी पार्टी के जलसे में नहीं आए। उस दिन इतने लोग जलसे में आए कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं इनके बारे में सारी बातें कहना नहीं चाहता क्योंकि लोग कहेंगे कि कल तक तो इनका गुणगान करता था और आज इनके खिलाफ बोलता है। स्पीकर साहब, हमने खुद चन्दा इकट्ठा करके इनको कारें भेंट की थी। करण सिंह ने चन्दा इकट्ठा करके इनको कार भेंट की थी लेकिन आज ये सारी बातों के लिये इन्कार कर रहे हैं। स्पीकर साहब इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, वे बेबुनियाद और गलत है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से हमने आज हाउस में वर्ष (1994-95) की अनुदान मांगों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए अपने-अपने हल्के की दिक्कतों और शिकायतों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनते ही मुख्य मन्त्री जी, ने सब से पहले फैसला लिया कि प्रदेश में शान्ति के साथ विकास होगा। स्पीकर साहब, हमने यह सारा केवल कागज पर ही बुलन्द नहीं किया बल्कि इसको वास्तविक रूप दिया। हमने हमेशा ही मुख्यमन्त्री जी के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजट बनाते समय, इन बातों का ध्यान रखा है। अध्यक्ष महोदय, आज आप देख रहे हैं कि जहां तक हरियाणा में शान्ति का सम्बन्ध है, कानून और व्यवस्था का जो माहौल है वह बहुत ही अच्छा है। हरियाणा के हर एक आदमी का हमने पूरा ध्यान रखा है, चाहे वह शहर का रहने वाला है, चाहे गांव का रहने वाला है किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी धर्म का है, हमने सब की सेफ्टी के लिए और ला एण्ड आर्डर को मैनटेन रखने के लिए बजट में पैसा रखा है। यही कारण है कि आज हरियाणा में कोई गुण्डागर्दी नहीं कर सकता। हमने ला एण्ड आर्डर को पूरी तरह से और अच्छी तरह से मैनटेन करने के लिए अपनी पुलिस को जो साधन उपलब्ध कराए है। उसके कारण आज कोई भी बदमाश आदमी बच नहीं सकता उसके खिलाफ

सख्त कार्यवाही हो सकती है। आज लोग हरियाणा के अन्दर अमन से रहते है। स्पीकर साहब, जहां तक विकास का ताल्लुक है, जिस प्रदेश में जितना विकास होगा, उतने ही लोग विकास के लिये और ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है। हमारे माननीय सदस्यों ने अपने हल्कों के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए मांगों पर चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्कूलों के बारे में चर्चा की गई कि कि गांवों में स्कूलों की कमी है। शिक्षा की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। स्कूलों में टीचर्ज की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने स्कूल हमारी सरकार के आने के बाद अपग्रेड हुए हैं, इनकी सरकार चार साल रही, इनके चार साल में ही नहीं बल्कि मैं तो यहां तक कह सकता हूं, कि पिछले दस साल में भी इतने स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। स्पीकर सर, यहां पर मेरे 19-00 बजे | भाइयों ने बोलते हुए टीचर्ज की बात भी कही कि टीचर्ज की कमी है। बाकई गांव के अन्दर टीचर्ज की कमी रही थी। (शोर)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी, मेरे विचार से 10 मिनट का समय सदन का और बढ़ा दें।

वित्तमंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : ठीक है जी, बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

वित्तमंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि स्कूलों में बाकई टीचर्ज की कमी रही थी, नफरी कम रही थी जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफी नुक्सान होता था। मैं इन भाईयों से पूछता हूं कि जब इन भाईयों की सरकार थी तो इन्होंने अपने चार साल के कार्यकाल में कितने टीचर्ज लगाये थे ? चार साल के अर्से में इन्होंने स्कूल व कालेजों में एक भी पोस्ट नहीं दी थी। लेकिन हमने एक-एक गांव की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जितनी पोस्टें खाली पड़ी थीं, उनको भरा था और कालेजों में अब चार साल के बाद पहली बार हमने पोस्टें दी हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कूल अप-ग्रेड होंगे तो उसके साथ-साथ टीचर्ज की डिमांड भी बढ़ती ही जाएगी। इसलिये सरकार यह प्रयास

[श्री मांगे राम गुप्ता]

करती रहती है ताकि स्कूलों में बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बजट में ज्यादा से ज्यादा पैसे का प्रावधान किया जाए और बच्चों की पढ़ाई खराब न हो। सरकार पूरी तरह से जागरूक है कि हरियाणा का कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे जो व्यक्ति पहले अनपढ़ रह गया था साक्षरता अभियान के तहत उसके लिये सरकार यह कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा फण्डज की ऐलोकेशन करके अनपढ़ता को समाप्त किया जाए (तालियां)

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, यहां पर हस्पतालों का जिकर भी आया। डाक्टर्ज का जिकर भी किया गया कि हस्पतालों में डाक्टर्ज नहीं है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मांगेराम जी, आप यह बताएं कि देहात में जो गर्ल्ज कालेज खोले हुए हैं, उनको भी आप ग्रांट देंगे या नहीं।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, शायद कहीं स्कूल खुलवाने की आपकी भी इच्छा है। इसके लिये आप बड़े ही शुभचिन्तक हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : खुलवाने की इच्छा नहीं है, खुलवा लिये हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शिक्षा के लिये बजट में हम पैसे का पूरा प्रावधान करते हैं लेकिन जब हम बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेन्टस की नफरी बढ़ती ही रहती है। हमारे शिक्षा मन्त्री बता रहे थे कि हिन्दुस्तान में हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जहां प्राईवेट स्कूल की शिक्षा के लिये अपने गांव से एक किलोमीटर तक, मिडिल स्कूल की शिक्षा के लिये दो ढाई किलोमीटर्ज तक तथा हाई स्कूल की शिक्षा के लिये पांच किलोमीटर्ज तक बच्चों को जाना पड़ता है। सभी माननीय सदस्यों को पता होगा कि जब हम लोग पहली क्लास में अपने गांव से पढ़ने के लिये जाया करते थे तो हमें कम से कम दो किलोमीटर्ज का फासला तय करना पड़ता था। इस तरह इस से हालात में स्कूलों और कालेजों में टीचर्ज की मांग तो रहेगी ही। जब तक प्राईवेट लोग स्कूल और कालेज खोलने का प्रयास करते रहेंगे और शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार को योगदान देते रहेंगे तब तक शिक्षा को बढ़ावा मिलता ही रहेगा। यह अकेले सरकार के बस का काम नहीं है। जो प्राईवेट संस्थाएं हैं, अगर वे अच्छा कालेज चलाते हैं, अच्छा स्कूल चलाते हैं अच्छी ऐजूकेशन देते हैं, अच्छी मनेजमैंट है तो उनको सरकार अपनी तरफ से पूरा-पूरा सहयोग देगी, प्रोत्साहन देगी, जितनी भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा सकती होंगी, यह सरकार उनको प्रोवाईड करेगी ताकि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का विघ्न न पड़ने पाये। अध्यक्ष महोदय कालेजों में आज भी सरकार 95 प्रतिशत ग्रान्ट देती है। आप ही बताइए कि इससे ज्यादा सरकार और क्या कर सकती है ? इससे ज्यादा सरकार और क्या मदद कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : मतलब क्या दोगे ?

श्री मांगे राम गुप्ता : दे रखी है पुंडरी में स्पीकर सर। (शोर)

आवाजें : पुण्डरी के भी दोगे या नहीं। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक पुंडरी के लिये ही नहीं सरकार तो सारे हरियाणा के लिये चिन्तित है। सरकार की नीति के अनुसार अगर पुंडरी उसमें आता है, तो अवश्य देंगे। जो नीति है उस नीति में अगर पुंडरी आएगा तो प्रायोरिटी हम देंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

इसके साथ साथ स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है सब से ज्यादा किसानों को पानी देने की और बिजली देने की। सरकार हमेशा ही एग्री-कलचर सैक्टर को ज्यादा पैसा देने की कोशिश करती है लेकिन साधन सीमित होने के कारण सारा पैसा एक ही तरफ नहीं लगाया जा सकता, दूसरे कामों पर भी सरकार को नजर रखनी पड़ती है। इसलिये सरकार ने यह प्रयास किया है कि खेत क्यारी और किसानों के टेल तक पानी पहुंचाया जाए। इसके लिये सरकार ने पूरा-पूरा प्रयास किया है। अभी बोलते हुए बंसीलाल जी ने कहा कि नहरों की, माईनर्ज की सिल्ट बगैरह, निकलवाने के लिये सरकार के पास कोई साधन है ही नहीं और न ही नहरों और माईनर्ज की सफाई का सरकार प्रयास ही कर रही है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि साधन न होते हुए भी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से इस काम के लिये 800 करोड़ रुपया मन्जूर करवाए हैं ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। अब नहरों में सिल्ट ही रहेगी और न ही माईनर्ज के कच्चे पक्के होने की शिकायत ही रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर शहरों के बारे में भी चर्चा हुई और कुछ टैक्स के बारे में भी चर्चा हुई। मैं बताना चाहता हूं कि शहरों और गांवों को अलग नजर से देखने का पहली सरकार का ध्यान था, हमारा नहीं है। पहली सरकार शहर को एक नजर से देखती थी और गांव को दूसरी नजर से देखती थी। हमारी सरकार इनमें फर्क नहीं रखती है। हम गरीब, किसान और हरिजन सभी का ध्यान रखते हैं। हम हर वर्ग को सहुलियत देने की बात करते हैं। यहां पर सीवरेज के पानी का जिक्र आया कि पीने के पानी में मिलने की वजह से लोगों को पीलिया हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटियां इतने साधन नहीं जुटा सकती थी इसलिये सरकार ने यह काम अपने हाथ में ले लिया। अब हरियाणा के किसी शहर और गांव में, जहां सीवरेज सिस्टम है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। अब अगर कहीं भी पाईप लीक हो जाएगा तो उसका पूरा इन्तजाम करने के लिये हमने बजट में पैसा रखा है।

यहां पर सड़कों के बारे में भी शिकायत आई। अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत से प्रदेशों में घूमते हैं। आपको तो पता ही है और हम यह कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की सड़कें आज देश में नम्बर एक पर हैं। हमें जो आदेश

[श्री मांगे राम गुप्ता]

मुख्यमन्त्री जी ने दिए थे और अब दिए हैं, उसके अनुसार आप देख लें। आप सारे हरियाणा में देख लें कि कोई भी सड़क, चाहे वह किसी देहात के कोने में लगती हो, वह टूटी हुई नहीं रहेगी। हमने तो एक मिसाल आपके सामने पेश की है। पहले किसी सरकार ने फीर-लेन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब दो महीने के अन्दर करनाल से दिल्ली तक फोर लेनिंग पूरी तैयार हो जाएगी। इन्होंने पता नहीं उस सड़क को क्यों रोक रखा था ? इस बारे में पीछे मुख्य मन्त्री जी ने बताया था। अध्यक्ष महोदय, और कई बातों पर यहां चर्चा हुई। मैं किसी बात को रिपीट नहीं करूंगा। बहुत सी बातों का जवाब मुख्य मन्त्री जी ने दे दिया है और कंसर्ड मिनिस्टर्ज ने भी दिया है। जो बजट हमने पेश किया है, वह वक्त की मांग को देखते हुए, पूरी बातों को कंसिडर करके पेश किया है। हम यह भी कोशिश करेंगे कि इसका सही प्रयोग हो। कहीं कोई मशीनरी गलत चलेगी तो उसको रोकने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आम पब्लिक ने इस बजट की सराहना की है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। (धन्यवाद)।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now voting on demands on the Budget for the year 1994-95 will take place.

First, I will put the cut motions on the demands to the vote of the House and then I will put the demand to the vote of the House.

Demand No. 1

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,79,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Demand No. 2

Mr. Speaker : Now I put the cut motion on demand No. 2 given by Sarvshri Bansi Lal, Karan Singh Dalal, Chhattar Singh Chauhan and Smt. Janki Devi Mann to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 2 of Rs. 56,83,99,000 on account of General Administration be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 55 ,52,98,000 for revenue expenditure be granted to the governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 3-General Administration.

The motion was carried.

Demand No. 3

Mr. Speaker : Now I put the cut motion on Demand No. 3, given by Sarvshri Bansi Lal, Ram Bhajan, Karan Singh Dalal and Attar Singh, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 3 of Rs. 203,93,19,000 on account of Home be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,96,10,64,000 for revenue expenditure and Rs. 4,50,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 3-Home.

The motion was carried.

Demand No. 4

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 34,85,68,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

The motion was carried.

Demand No. 5

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No 5, given by Shri Ram Bhajan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 5 of Rs. 14,57,96,000 on account of Excise & Taxation be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 14,57,86,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 5-Excise & Taxation.

The motion was carried.

Demand No. 6

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 6, given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 6 of Rs. 6,74,89,84,000 on account of Finance be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,39,79,09,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

The motion was carried.

Demand No. 7

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 7, given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 7 of Rs. 10,61,54,76,000 on account of Other Administrative Services be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 10,61,25,46,000 for Revenue expenditure and Rs. 10,50,000 for Capital expenditure be granted to the Governor defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 7- Other Administrative Services.

The motion was carried.

Demand No. 8

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 8, given by Sarvshri Chhattar Singh Chauhan, Smt. Janaki Devi and Karan Singh Dalal, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 8 of Rs. 1,67,98,12,000 on account of Buildings & Roads be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 86,14,52,000 for revenue expenditure and Rs. 81,77,60,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charge that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges Demand No· 8—Buildings & Roads.

The motion was carried.

Demand No. 9

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 9 given by Shri Ram Bhajan , Smt. Janaki Devi, Shri Chhattar Singh Chauhan and Shri Attar Singh, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 9 of Rs. 5,05,93,63,000 on account of Education be reduced by Rs 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5,05,93,58,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

The motion was carried.

Demand No. 10

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 10, given by Shri Om Parkash Beri, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 10 of Rs. 375,47,69,000 on account of Medical & Public Health be reduced by Rs. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,28,94,57,000 for revenue expendiure and Rs. 46,38,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 10 Medical and Public Health.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि सहमति हो तो हाउस का समय और 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 10 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

Demand No. 11

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 11, given by Shri Ram Bhajan, M.L.A., to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 11 of Rs. 13,86,18,000 on account of Urban Development be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 13,86,18,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

The motion was carried.

Demand No. 12 to 14

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 29,96,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 12-Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1,93,34,26,000 for revenue expenditure and Rs. 3,54,31,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 7,93,36,000 for revenue expenditure and Rs. 3,44,47,25,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 14-Food & Supplies.

The motion was carried.

Demand No. 15

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 15, given by Sarvshri Bansi Lal, Karan Singh Dalal and Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 15 of Rs. 11,30,58,50,000 on account of Irrigation be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost

Mr. Speaker : I also put cut motion given by Shri Om Parkash Beri, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 15 of Rs. 9,96,15,50,000 on account of Irrigation Department be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 9,96,15,50,000 for Revenue expenditure and Rs. 1,34,07,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

The motion was carried.

Demand No. 16

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 16 given by Shri Ram Bhajan Aggarwal M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 16 of Rs. 41,07,79,000 on account of Industries be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 30,10,28,000 for revenue expenditure and Rs. 10,97,11,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

The motion was carried.

Demand No. 17

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 17, given by Sarvshri Bansi Lal, Karan Singh Dalal and Om Parkash Beri, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 17 of Rs. 1,21,78,97,000 on account of Agriculture Department be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,21,67,47,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

The motion was carried.

Demand Nos. 18 to 21

Mr. Speaker : Question is—

hat a sum not exceeding Rs. 37,40,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 4,49,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 48,50,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 1,17,32,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

The motion was carried.

Demand No. 22

Mr. Speaker : No I put cut motion on Demand No. 22, given by Sarvshri Chhattar Singh Chauhan and Karan Singh Dalal, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 22 of Rs. 22,55,73,000 on account of Cooperation Department be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 13,94,54,000 for revenue expenditure and Rs. 8,61,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

The motion was carried.

Demand No. 23

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,54,83,92,000 for revenue expenditure and Rs. 37,93,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

The motion was carried.

Demand No. 24

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 24, given by Shri Bansi Lal, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 24 of Rs, 8,13,66,86,000 on account of Tourism be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 85,02,000 for revenue expenditure and Rs. 2,60,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of Charges under Demand No. 24-Tourism.

The motion was carried.

Demand No. 25

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,23,38,97,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of Charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Govt.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 16th March, 1994.

(The Sabha then *adjourned for Wednesday, the 16th March, 1994.)

*1917 Hrs.

25802—H.V.S.—H.G.P., Chd